C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. VI Third Session, 2014/1936 (Saka)
No. 12, Tuesday, December 09, 2014/Agrahayana 18, 1936 (Saka)

S U B J E C T	**P A G E S**
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 221 to 225	4-51
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 226 to 240	52-115
Unstarred Question Nos. 2531 to 2760	116-574

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 575-582
702

MESSAGES FROM RAJYA SABHA 583

STANDING COMMITTEE ON LABOUR 584
Statements

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 57th Report of the Standing Committee on Agriculture on National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management (NIFTEM), pertaining to the Ministry of Food Processing Industries

Sadhvi Niranjan Jyoti 585

ELECTION TO COMMITTEE
Welfare of Other Backward Classes 585

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE
Abduction of and harassment meted out to Tamil Fishermen by Sri Lankan Navy and steps taken by the Government in this regard

Dr. P. Venugopal 586-597

Shrimati Sushma Swaraj 586-589
595-598

MOTION RE: EIGHTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 600

SUBMISSION BY MEMBER
Re: derogatory remarks made by a Member during a public rally in Kolkata 604-609

MATTERS UNDER RULE 377 610-627

(i) Need to allocate a coal mine for setting up of a dedicated power plant for Chandigarh

Shrimati Kirron Kher 610

(ii) Need to set up parking fee collection cabin within the Parking Area of vehicles at Ahmedabad Airport

Shri D. S. Rathod 611

(iii) Need to run Garib Rath Express (Train No. 12211/12212) between Delhi and Muzaffarpur (Bihar) daily and also provide a stoppage of the train at Bagaha in Bihar

Shri Satish Chandra Dubey 611

(iv) Need to run Amritsar Express (Train No. 11057/11058) from Dadar, Mumbai

Shri A.T. Nana Patil 612

(v) Need to enhance the rate of honorarium to Accredited Social Health Activists engaged under the National Rural Health Mission

Shrimati Rekha Verma 613

(vi) Need to provide relief and compensation to farmers whose land has been utilized for fencing the border in Rajasthan particularly in Barmer Parliamentary Constituency

Col. Sonaram Choudhary 614-615

(vii) Need to expedite payment of arrears of wages of labourers engaged in the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in Madhya Pradesh

Shri Faggan Singh Kulaste 616

(viii) Need to restore the land of widows, military personnel and people belonging to weaker section allotted to them in Delhi under 20-point programme

Dr. Udit Raj 616

(ix) Need to provide adequate compensation for injury and loss of human lives as well as damage to crops by wild animals in Kheri Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Ajay Mishra Teni 617

(x) Need to accelerate the pace of construction of broadgauge railway line from Macherla to Nalgonda

Shri Gutha Sukhender Reddy 618

(xi) Need to implement the One Rank One Pension Scheme for ex-servicemen

Shri Deepender Singh Hooda 619

(xii) Need to continue National Agriculture Insurance Scheme beyond the financial year 2014-15

Shri G. Hari 621

(xiii) Need to provide separate fund for Saansad Adarsh Gram Yojana

Shri V. Elumalai 622

(xiv) Need to provide adequate funds under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme particularly in West Bengal

Prof. Saugata Roy 623

(xv) Need to allot land for construction of the building for Paradip Marine Police Station in Paradip Port, Odisha

Dr. Kulamani Samal 624

(xvi) Need to improve BSNL mobile service and fill up the vacant post of General Manager in Parbhani and Jalna districts of Maharashtra

Shri Sanjay Haribhau Jadhav 625

(xvii) Need to start operation of flights from Kolhapur Airport in Maharashtra

Shri Dhananjay Mahadik 626

(xviii) Need to take urgent steps to start the ESI Medical College at Parippally in Kollam, Kerala

Shri N.K. Premachandran 626

(xix) Need to permit rearing of milch animals in Delhi

Shri Ramesh Bidhuri 627

PAYMENT AND SETTLEMENT SYSTEMS (AMENDMENT) BILL, 2014

Motion to Consider 628

Shri Arun Jaitley 628-631
662-666

Shrimati V. Sathyabama 636-638

Shri Jagdambika Pal 639-643

Prof. Saugata Roy 644-648

Shri Bhartruhari Mahtab 649-653

Prof. Ravindra Vishwanath Gaikwad 654

Shri Konda Vishweshwar Reddy 655-656

Dr. A. Sampath 657-659

Kumari Sushmita Dev 660-661

Clauses 2 to 5 and 1 665

Motion to Pass 666

DISCUSSION UNDER RULE 193 667-651

(i) Natural calamities in various parts of the country

Shri Radha Mohan Singh 675-677

(ii) Reported Dilution of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme

Shri Sankar Prasad Datta 682-686

Shri Hukmdeo Narayan Yadav 687-693

Shri K.H. Muniyappa 694-698

Shri V. Elumalai 699-701

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 728

Member-wise Index to Unstarred Questions 729-733

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 734

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 735

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Prof. K.V. Thomas

Shri Anandrao Adsul

Shri Prahlad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka`

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, December 09, 2014/Agrahayana 18, 1936 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

… (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अध्यक्ष जी, मैंने एडजर्नमेंट मोशन दिया था। पहले शुक्रवार को भी दिया था। मैं आपसे अनुरोध करने के लिए भी आया था, लेकिन समय के अभाव के कारण मिल नहीं सका। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है - Situation arising due to hike in excise duty on petrol and diesel raised by the Government of India through notification....(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, मल्लिकार्जुन खड़गे से पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में वृद्धि करने की अधिसूचना के बारे में प्रश्नकाल के स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यह मामला महत्वपूर्ण है, तथापि इसके लिए आज के कार्य में व्यवधान डालना अनिवार्य नहीं है। ये मामले अन्य उपायों के माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों की किसी भी सूचना को अनुमति प्रदान नहीं कर सकती हूं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अन्य सूचना दीजिए। I will allow the discussion during `Zero Hour'.

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: It has gone on record.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will allow in `Zero Hour', not now.

… (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप इसे कंवर्ट कर दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इस मुद्दे को जीरो ऑवर में उठाइए। मैं इस मुद्दे को उठाने के लिए मना नहीं कर रही हूं।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।...(व्यवधान) इससे महंगाई बढ़ेगी।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इस मामले को जीरो ऑवर में उठाइए।

...(व्यवधान)

11.04 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Q. No. 221, Shri C. R. Patil.

(Q. 221)

श्री सी.आर. पाटील : अध्यक्ष जी, इस वर्ष देश में कॉटन का रिकार्ड उत्पादन होने की सम्भावना है, क्योंकि कपास की खेती ज्यादा क्षेत्र में की गई है। दुनियाभर में कपास के दाम गिर रहे हैं और इस वर्ष हमारा एक्सपोर्ट भी 35 परसेंट कम होने की सम्भावना है। यह देखते हुए अभी तक कॉटन कारपोरेशन आफ इंडिया ने गुजरात में कपास खरीदने का काम शुरू नहीं किया है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कॉटन कारपोरेशन आफ इंडिया गुजरात में अपना केंद्र कब शुरू करेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया): माननीय संसद सदस्य ने किसानों के लिए चिंता व्यक्त की है और पूछा है कि गुजरात में सीसीआई ने अपना केंद्र नहीं खोला है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि गुजरात में सहायक केंद्र 20 दिनों से शुरू हो गया है। गुजरात में 95,04,023 घासड़ी की बेल की खरीदी भी हुई है।

श्री सी.आर. पाटील : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि हमारा देश कॉटन के प्रोडक्शन में किस नंबर पर है? पहले और दूसरे नंबर पर कौन-से देश हैं? प्रेस में यह आया है कि महाराष्ट्र में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से कहा गया है कि वह प्रत्येक किसान से केवल 25 क्विंटल ही कॉटन खरीदे तो क्या यह बात सच है? क्या इससे किसानों में असंतोष नहीं होगा? क्या गुजरात के किसानों के लिए भी ऐसे निर्देश दिए गए हैं, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि महाराष्ट्र से एक किसान से केवल 25 क्विंटल ही खरीदा जाएगा, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र के अकोला क्षेत्र में 1,21,613 बेल की खरीद हो गयी है और औरंगाबाद में 1,37,081 बेल की खरीद हो गयी है। इसका मतलब टोटल 2,58,694 बेल की महाराष्ट्र में खरीद हो गयी है।

माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न यह पूछा कि हम किस क्रम पर हैं तो विश्व में कपास उत्पादन में सबसे पहले क्रम पर चीन है। उसका उत्पादन 6.84 मिलियन घन टन है। दूसरे नंबर पर भारत है। उसका उत्पादन 5.82 मिलियन घन टन है।

डॉ. मनोज राजोरिया : महोदया, मंत्री महोदय ने कॉटन उत्पादन के क्षेत्र में देश में बढ़त का जो डेटा दिया है, इस बढ़त में देश में हमारा राजस्थान, जहां से मैं सांसद हूं, के कुछ जिले जैसे हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, नागौर, पाली इत्यादि में बी.टी. कॉटन का उत्पादन होता है। लेकिन, राजस्थान में आज तक कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित नहीं हुआ है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या राजस्थान में कॉटन उत्पादन को बढ़ाने के लिए कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने की उनकी कोई योजना है? यदि ऐसा है तो वे कब तक इसे स्थापित करेंगे?

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो राजस्थान में कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने की बात कही, तो राजस्थान में अभी दो सेंटर खुले हैं। एक सेन्टर बांसवाड़ा, उदयपुर में और दूसरा सेन्टर गंगापुर में है। वहां कॉटन का कम खर्च में कैसे अच्छे तरीके से उत्पादन हो, इसके लिए राजस्थान के दो सेन्टर्स में अभी काम हो रहा है।

श्री रवनीत सिंह : मैडम, आज सारी दुनिया में कॉटन के दाम निरंतर गिर रहे हैं और देश में भी हमारे कॉटन के फार्मर्स को बहुत नुकसान हो रहा है तो क्या इसके लिए सरकार या मिनिस्ट्री किसानों को बचाने के लिए वेयरहाउस रिसीट फिनांसिंग सिस्टम लाने के लिए कोई तैयारी कर रही है, जिससे हम किसानों को कोई फाइनैंस दे सकें ताकि वे गोदाम और वेयरहाउसिंग में अपने कॉटन को रख सकें और जब उसके अच्छे रेट्स हो तो उस समय वे अपना कॉटन मंडी में बेच सकें? क्या सेन्ट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम लाने जा रही है?

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया : माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो गवर्नमेंट ने जो एमएसपी तय किया है, उसी रेट पर अभी कॉटन की खरीद हो रही है। किसानों को कॉटन के अच्छे दाम कैसे मिलें, इसके बारे में सरकार सोच रही है।

SHRI B. VINOD KUMAR : Madam, the hon. Minister in his reply in para (b) and (c) had stated that the prices of cotton in most cotton producing States have declined during the current season, that is, 2014-15 mainly on account of worldwide cotton glut resulting in lower exports. I would like to know from the hon. Minister whether the Ministry of Commerce is taking any remedial measure with regard to exports. Further, the Minister had also stated that the Cotton Corporation of India is purchasing cotton from the farmers while they are in

distress. At present, MSP is Rs.4,050. Is the Government going to increase the price to Rs.5,000? If yes, when?

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया : अध्यक्ष जी, हमने एम.एस.पी. के बारे में बताया कि अभी एम.एस.पी. 4,050 रूपए है, उसे बढ़ाने की जो बात कही, उसके लिए हम विचार कर रहे हैं कि किसानों को कैसे अच्छा दाम दिया जाए। दूसरा, देश में कॉटन का बहुत प्रोडक्शन होने के बावजूद यहां से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इसके दाम गिर रहे हैं और सरकार किसानों के लिए चिन्ता कर रही है।

SHRIMATI SUPRIYA SULE : Madam Speaker, NAFED is the agency which does the entire procurement of cotton in the country. NAFED, right now, has a huge financial crunch and the cotton production in Maharashtra and the entire country has been exceptionally good even this year. Is the Government of India looking at paying up Rs. 300 crore which is pending with NAFED since the Cotton Corporation of India is helping the Government of Maharashtra for procurement of cotton? But the MSP has become a huge problem. So, what intervention is the Government is making towards addressing the NAFED issue?

श्री राधा मोहन सिंह : नैफेड महाराष्ट्र में फेडरेशन के माध्यम से खरीद करती थी। अभी महाराष्ट्र के अन्दर जो फेडरेशन है, वह सीधे खरीद कर रही है। पिछली बार नैफेड ने फेडरेशन के माध्यम से 54 क्रय केन्द्र खोले थे और इस बार 64 क्रय केन्द्र खोलकर फेडरेशन अपना यह काम कर रही है।

(Q. 222)

श्री रामा किशोर सिंह : महोदया, जो उत्तर आया है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। आज मिलावट पूरे देश के लिए बहुत गम्भीर चुनौती बन गई है। चाहे दूध में मिलावट हो, चाहे खाद्य पदार्थ में मिलावट हो, चाहे पेय पदार्थ में मिलावट हो, उसके कारण आदमी का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। यह बहुत गम्भीर विषय है। उसके बावजूद भी जो कार्रवाई होनी चाहिए और जो व्यवस्था होनी चाहिए, आज वह हमारे देश में नहीं है।

हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के हाल के परामर्श के आलोक में खाद्य और पेय पदार्थों में मिलावट को रोकने हेतु कठोर दण्ड यानी आजीवन कारावास की सजा देने का कानून बनाने का कोई विचार है? यदि हाँ, तो कब तक?

श्री राम विलास पासवान : महोदया, जहाँ तक खाद्य पदार्थ का मामला है, यह एफ.एस.एस.ए.आई. के द्वारा डील होता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के माध्यम से हम लोग स्टैंडर्ड तय करते हैं। जैसा कि हमने जवाब में कहा है, हमारे पास तीन साल का आंकड़ा है। यह आँकड़ा हम हेल्थ मिनिस्ट्री के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा लेते है। बी.आई.एस. हमारा है, हमारी मिनिस्ट्री एक सेन्ट्रल एजेंसी नहीं है। अलग-अलग मंत्रालय में अलग-अलग काम होते हैं, मिसलीडिंग एडवरटीजमेंट का काम अलग होता है, खाद्य का अलग होता है। हमारी जानकारी के मुताबिक जो जांच किए गए नमूने वर्ष 2011-2012 में थे, वे 64,593 थे, उसमें 8,247 सही पाए गए। प्रोसीक्यूशन 6,845 हुए और जो सजा हुई, वह 764 में हुई। वर्ष 2012-2013 का भी आंकड़ा है, वर्ष 2013-14 का लेटेस्ट आंकड़ा है कि जो सैंपल जांच किए गए, उनकी संख्या 72,200 थी, उनमें से 13,571 सही पाए गए। प्रोसीक्यूशन 10,235 का हुआ और सजा 3,845 को हई।

श्री रामा किशोर सिंह : महोदया, आज हमारे देश में जांच की एजेंसी एफ.एस.एस.ए.आई. है, उसके अधीन 151 प्रयोगशालायें हैं। इनमें से 68 प्रयोगशालायें एफ.एस.एस.ए.आई. से मान्यता प्राप्त हैं और शेष 83 प्रयोगशालायें एन.ए.बी.एल. द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं। जो आंकड़े मिलावट के सामने आए हैं, उसमें जो दोषी पाए गए हैं, मैं बिहार का ही उदाहरण देता हूं, वहां 251 मामले क्रिमिनल और सिविल कोर्ट में गए हैं। वहां एक केस में भी कोई दोषी सिद्ध नहीं हुआ और कोई पकड़ा नहीं गया। सही ढंग से जांच नहीं होने के कारण ऐसा हुआ। यहां तक कि वहां अधिकारियों की भी कमी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या देश में मिलावटी खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों की जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की समूचित तैनाती, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का नियमित

आधुनिकीकरण, केन्द्रीय स्तर पर नियमित रूप से मिश्रण का डेटा एकत्र करने और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु एक प्रभावी तंत्र की स्थापना करेंगे?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदया, उन्होंने पहले प्रश्न के 'बी' पार्ट में सजा की बात कही है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक दो तरह के फूड्स होते हैं - एक अनसेफ फूड और दूसरा खराब क्वालिटी का फूड । जो अनसेफ फूड होते हैं, that does not result in injury जिनसे नुकसान नहीं होता है उसके लिए 6 माह की जेल और 1,00,000 रुपए का जुर्माना है। जो नॉन ग्रिवियस इंज्यूरिज हैं उनके लिए 1 साल की जेल और 3,00,000 रुपए का जुर्माना है, जो ग्रिवियस इंज्यूरिज हैं उनके लिए 6 साल की जेल और 5,00,000 रुपए का जुर्माना है। जो रिजल्ट इन डेथ है, उसमें कम से कम 7 साल की जेल है, आजीवन कारावास और 10,00,000 रुपए का जुर्माना है। जो खराब क्वालिटी का खाना है उसके सबस्टैंडर्ड में 5,00,000 रुपए का जुर्माना है, मिस ब्रांडेड फूड में 3,00,000 रुपए का जुर्माना है, मिसलिडिंग एडवर्टिजमेंट के लिए 10,00,000 रुपए तक का जुर्माना है, food extraneous materials के लिए एक लाख रुपए का जुर्माना है। जो पजैशन ऑफ एडलट्रेंट है उसमें नॉनइंज्यूरियस के लिए 2,00,000 रुपए का जुर्माना है और इंज्यूरियस के लिए 10,00,000 रुपए का जुर्माना है। हमारे पास में फूड टेस्टिंग लेबोरेट्रिज हैं। सेफ्टी स्टेट का मामला है, चूंकि सारा का सारा काम स्टेट के पास है। हमको यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई भी चीज नहीं है। वहां स्टीयरिंग कमेटी, स्टेट फूड सेफ्टी कमिशनर, उसके अधीन कमेटी होनी चाहिए, जिला स्तर पर डेजिगनेटड ऑफिसर्स होने चाहिए, कहीं कुछ नहीं है। इस देश में 125 करोड़ कंज्यूमर्स हैं। राष्ट्रपति जी से लेकर चपरासी तक सब कंज्यूमर्स हैं। सबको कुछ न कुछ खरीदना पड़ता है। इस बात से हम स्वयं संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास कोई अथॉरिटी नही है। उन्होंने एफ.एस.एस.ए.आई के संबंध में कहा है।

हम आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि दूसरे देशों में फूड एडलट्रेशन का मामला बहुत गंभीरता से लिया जाता है, लेकिन हम उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। मैं राज्य सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जो उसके लिए कानून है, अगर उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है तो वे उसमें संशोधन करें। भारत सरकार उसमें हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा की ही व्यवस्था न की जाए, जो लोग भी उसमें दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारे पास में सजा का प्रावधान है। हम पिछले 10 दिनों से जानकारी मांग रहे हैं कि कितने लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है।

PROF. K.V. THOMAS : Madam Speaker, we have two very effective legislations for food safety and standards. But the implementation of these Acts is done by State Governments. Even though the Government of India has enacted these two legislations, my request to the hon. Minister is that we should intervene with State Governments so that these laws are effectively implemented and there should be effective awareness campaigns so that consumers know what their right is.

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदया, जैसा मैंने पहले कहा है कि फूड एडलट्रेशन ऐक्ट 1954 के मुताबिक चलता था। वर्ष 2006 में फूड सेफ्टी एण्ड स्टैंडर्ड ऐक्ट बना उसके अधीन वर्ष 2011 में रूल्स एण्ड रेगुलैशंस बने, उसी के अंदर अथॉरिटी भी बनाया गया है। माननीय सदस्य, जो पहले मंत्री भी थे, ने कहा है तो उसमें दिक्कत यह है कि यह मामला हेल्थ मिनिस्ट्री से संबंधित है। हम लोगों ने एक इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी बनायी है उसमें किसी भी डिपार्टमेंट का मामला हो, कम से कम उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। एक डिपार्टमेंट का मामला दूसरे डिपार्टमेंट पर नही छोड़ कर, कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए, उसके लिए हम स्वयं प्रयत्नशील हैं। अगर आवश्यकता होगी तो अपने हेल्थ मिनिस्टर से कहेंगे कि राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ बैठक बुलायें और वह देखें कि कैसे उस कानून को मजबूत किया जा सकता है, उन पर कैसे कार्रवाई की जा सकती है।

श्री शरद त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदया, प्रश्न संख्या 222 के कॉलम 'ख' के अंतर्गत, जो खाद्य पदार्थों के संबंध में है, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए जो भी पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ बहुत दिनों तक रखे जाते हैं, उनके प्रिजर्वेशन के लिए अब तक सोडियम बाय कार्बोनेट का प्रयोग होता आ रहा है। आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा भी प्रिजर्वेशन की व्यवस्था है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ समन्वय बनाकर भारतीय पद्धति, आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा प्रिजर्वेशन की व्यवस्था के लिए कोई नीति निर्धारण करने का कष्ट करेंगे?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उसे हम पास आन कर देंगे।...(व्यवधान) रामा किशोर सिंह जी ने बिहार के संबंध में एक सवाल पूछा था, यह दुख की बात है कि बिहार में न ही अभी तक स्टियरिंग कमेटी बनी है और न ही मामले पर विचार करने के लिए कोई ट्राइबुनल है।

श्री सुल्तान अहमद : अध्यक्ष महोदया, फूड एडल्ट्रेशन और विजाल के मामले में मंत्री महोदय ने कहा कि सूबे या राज्यों के हाथ में क्षमता दी गई है और केन्द्र सरकार भी फूड लेबोरेटरी के तहत यह काम करती है। उन्होंने कहा कि विदेश में विजाल के खिलाफ जबरदस्त कानून है, वहां एक्शन होता है, लेकिन हमारे देश में नहीं होता। दो लाख रुपये से लेकर दस लाख रुपये तक फाइन, लेकिन चाहे तेल में हो, दूध में हो या खाने की चीजों में हो, विजाल पाया जाता है। क्या सरकार सोच रही है कि कुछ ऐग्ज़ैमप्लरी पनिशमैंट, कड़ी से कड़ी सजा के लिए कोई कानून बनाया जाए जिससे विजाल को रोका जा सके? इसका अफैक्ट, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हैल्थ मिनिस्ट्री, फूड प्रोसैसिंग, लेकिन देश के 125 करोड़ कनज्यूमर्स को एडल्ट्रेशन से कैसे सुरक्षा दे सकते हैं? क्या आप ऐसे किसी कानून के बारे में सोच रहे हैं?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्षा जी, जैसे मैंने कहा एक लाख रुपये से लेकर आजीवन कारावास तक भी सजा है। लेकिन मैं पार्लियामैंट में एक चीज बार-बार कहता हूं कि एक्ट अलग है, फैक्ट अलग है और टैक्ट भी अलग है। इसलिए कानून में कोई कमी नहीं है, कानून को कैसे कार्यान्वित किया जाए, इसकी जवाबदेही केन्द्र सरकार के पास नहीं है, राज्य सरकार के पास है। हमारा फैडरल स्ट्रक्चर है। उसमें हम इससे ज्यादा नहीं जा सकते।

(Q. 223)

श्रीमती नीलम सोनकर : अध्यक्ष महोदया, हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ के दशहरी और बनारस के लंगड़ा आम विश्व प्रसिद्ध हैं। इनकी मिठास दुनिया के अन्य किसी आमों में नहीं पाई जाती। क्या माननीय कृषि मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों आमों के उत्पादन को बढ़ाने और इनके संरक्षण के लिए कोई नीति बनाई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : अध्यक्ष महोदया, सबसे बड़ी बात है कि उत्पादन की कमी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार आम के एक्सपोर्ट की समस्या रही है। बीस कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें आम नहीं जा पा रहा था। उनमें लगातार बात चल रही है कि आम का एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें आम का एक्सपोर्ट जारी है। सरकार की तरफ से उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास होते रहते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा भी है कि पहले वे आम खिलाएं।

...(व्यवधान)

डॉ. संजीव बालियान : बारहवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार का ध्यान मेनली उत्पादकता बढ़ाने के ऊपर है। इसके लिए अच्छी वैरायटी के बीज, पुराने बाग-बगीचों का पुनरुद्धार और उन्हें बचाने के लिए अच्छी किस्म की दवाईयां, इन पर लगातार रिसर्च चलती रहती है और प्रयास जारी है।

श्रीमती नीलम सोनकर : अध्यक्ष महोदया, देश के फल उत्पादक किसानों के जीवन बीमा और फलों के बीमा के लिए क्या सरकार ने कोई नीति बनाई है? क्योंकि हमारे देश में फल उत्पादक किसान सूखा, बाढ़ और ठंड से हर साल प्रभावित होता है, यहां तक कि आत्महत्या कर लेता है, इसके लिए अगर कोई योजना हो तो, बताएं?

डॉ. संजीव बालियान : अध्यक्ष महोदया, पूर्व में ही मौसम आधारित कृषि बीमा योजना देश में लागू है, उसी के आधार पर चाहे फसल हो, चाहे बागवानी हो, उनका बीमा कराया जा सकता है। जहां तक बात माननीय सदस्य पूछा है कि क्या बागवानी करने वाले किसानों के लिए भी कोई योजना है, बागवानी के क्षेत्र में जो किसान काम कर रहे हैं उनके लिए कोई अलग से कोई बीमा योजना सरकार द्वारा शुरू नहीं की गई है।

SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN : Madam Speaker, we are extremely happy to note that India is the largest producer of fruits in the world. The fruits, especially, mangoes and bananas from India are favourite ones in the international market. But it has been distressing to note that huge consignments of Indian fruits, which have been exported to European countries, have been rejected owing to the presence of pesticides and insecticides. Under these circumstances, I would like to know from the hon. Minister as to what stringent measures have been taken by the Government to see that the presence of pesticides and insecticides is being removed from these fruits. I would also like to know as to whether the ICAR is looking seriously into the matter.

डॉ. संजीव बालियान : अध्यक्ष महोदया, कृषि उत्पाद के निर्यात के प्रोत्साहन के लिए विदेशी बाजार विशेष रूप से यूरोपीयन यूनियन की तरफ से समस्याएं थीं, हमारे देश से जो यूरोप में फल जाते हैं, उनको सुनिश्चित करने के लिए पादप स्वच्छता संबंधी तकनीकी दस्तावेज उन देशों को उपलब्ध कराए गए हैं। निर्यात होने वाले कृषि उत्पादों, कीटों, व्याधियों आदि से मुक्त रखने के लिए उनकी कड़ी जांच और प्रमाणन की व्यवस्था की गई है। यूरोपीय देशों को भेजे जाने वाले कृषि उत्पादों के लिए एक विशेष स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसिजर तैयार किया गया है ताकि उन देशों के जो मापदंड हैं उसके अनुरूप ही निर्यात हो जिससे नो कम्पलाएंस जिससे हमारे उत्पादों का होता है वह न हो, इसके साथ साथ एपिडा द्वारा जो एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कामर्स में जो कृषि उत्पादों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को देखती है उसके द्वारा लगातार कुछ चीजों पर काम किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर एपिडा ध्यान दे रहा है। जिसमें छंटाई, ग्रेडिंग सुविधाएं, पैक हाऊस, कचरा उपचार का प्लांट, वॉटर सेफ्टी मेजर्स, फ्यूमिगेशन है, दूसरा मार्केट डेवलपमेंट का काम है क्योंकि जब तक मार्केट डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक एक्सपोर्ट के लिए नहीं जा सकते, उसमें पैकेजिंग किस तरह की हो, जो विदेश में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं वह किस तरह की हो, तीसरी चीज क्वालिटी डेवलपमेंट की है, प्रयोगशाला इस तरह की बनाई जा रही है जिसमें गुणवत्ता संबंधी जांच हो सके। हम लगातार एपिडा की तरफ से ट्रांसपोर्ट असिंसटेंस भी दे रहे हैं।

SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN : Madam Speaker, I am sorry, I am not satisfied with the answer given by the hon. Minister. I would like to know whether the ICAR is looking seriously into the matter.

श्री राधा मोहन सिंह : माननीय सदस्य ने निश्चित रूप से आम के संबंध में पूछा था, उसके निर्यात पर अभी रोक है, यह रोक कुछ वर्षों से चल रही है। हमारे मंत्री जी ने भी बताया है कि कुछ कीड़ों के प्रकोप के कारण इसे रोका गया था, कई वर्ष पहले रोका गया था, मैं अगले दो-तीन महीने के अंदर उससे मुक्ति दिलाने वाला हूं, उस दिशा में हमारा तेजी से प्रयास चल रहा है और शीघ्र हम आम का निर्यात करेंगे।

SHRI V. ELUMALAI : Madam Speaker, the import of mangoes was banned by the European Union in May last. What action has the Government taken to solve this issue? I would like to know whether the export of mangoes will begin again. Has the Government given any compensation to the affected mango merchants?

डॉ. संजीव बालियान : इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है, पहले भी मैंने बताया था कि यूरोपीयन यूनियन के साथ जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। जहां तक निर्यात रुकने के कारण नुकसान का सवाल है, उस पर कम्पनसेशन का विचार सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है।

SHRI SIRAJUDDIN AJMAL : Respected Madam, in a developing country like ours, where lion's share of the population are farmers, it has been seen that from the day of Independence till today, no visionary planning has been done as far as the farmers' most vital factor affecting their economy, that is, sustainable system of marketing, is concerned.

It has also been seen in my Constituency Barpeta and also Mankachar that vegetables and jute have been thrown on the streets by the farmers. Now, I would request the hon. Minister to kindly inform the House whether any long-term planning is being done so that these farmers can sell their produce in the open market very easily and do not have to throw vegetables on the road.

डॉ. संजीव बालियान : माननीय अध्यक्ष महोदया, केन्द्र सरकार द्वारा लगातार प्रदेश सरकारों को ए.पी.एम.सी. एक्ट में संशोधन करने के लिए लिखा गया है, जिससे किसान अपना उत्पाद कहीं भी, बिना किसी रुकावट के बेच सके। इसमें करीब 12 प्रदेश सरकारों की तरफ से सहमति आ चुकी है और उन्हें मंडी सुदृढ़ीकरण के लिए निर्देश भी जारी किये जा चुके हैं। कृषि मंत्रालय ने एक पहल यह की है कि एक मंडी दिल्ली में ही स्थापित की जा रही है, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन्स को स्थान एलॉट किये जायेंगे। इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। मंडी में ही कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसेज की व्यवस्था की

जायेगी, जिनमें उन्हें स्थान एलॉट किये जायेंगे। केन्द्र सरकार की तरफ से लगातार यह प्रयास हो रहा है कि सब प्रदेश सरकारें इसमें सहयोग करें और ए.पी.एम.सी. एक्ट में संशोधन करें, जिससे किसान कहीं भी अपना उत्पाद बिना किसी कठिनाई के बेच सके। केन्द्र सरकार द्वारा लगातार ये प्रयास किये जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र कश्यप।

मंत्री जी, आपने मैंगो की बात सुनी, अब एप्पल की बात सुनिये।

श्री वीरेन्द्र कश्यप : अध्यक्ष महोदया, देश में सेब के उत्पादन में जम्मू-कश्मीर नम्बर वन है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी सेब काफी पैदा किया जाता है। हम कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि बाहर से सेब बहुत आयात हो रहा है, जिसकी वजह से हिन्दुस्तान का सेब उत्पादक बहुत परेशानी में है। अटल जी की सरकार के समय सेब उत्पादकों को कम्पैनसेट करने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर 50 परसेंट किया गया था। पिछले कुछ वर्षों से यू.पी.ए. सरकार में लगातार इम्पोर्ट ड्यूटी घटा दी गयी थी।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में एप्पल प्रोड्यूर्स को सहायता देने के लिए क्या सरकार के पास इम्पोर्ट ड्यूटी को सौ प्रतिशत करने की कोई योजना है?

डॉ. संजीव बालियान : अध्यक्ष महोदया, यह सही है कि कुछ फल ही हम विदेशों से आयात करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से सेब, काजू आदि हैं। पिछले कुछ दिनों से, चाहे जम्मू-कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश हो, सबसे ज्यादा काम स्टोरेज फैसीलिटीज, रीफर वेन्स या पैक हाउसेज में हुआ है, वह सेब के मामले में हुआ है, जिसकी वजह से सेब का इम्पोर्ट कुछ कम हुआ है। अभी सेब पर 35 परसेंट इम्पोर्ट ड्यूटी है। अभी तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं है कि इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया जाये। आज की डेट में 35 परसेंट इम्पोर्ट ड्यूटी सेब के ऊपर मौजूद है।

श्री एस.एस.अहलुवालिया : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि देश में पाइनएप्पल का सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वहां पर उसकी कोई भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है, जिस कारण फार्मर्स का एक्सप्लायटेशन बहुत ज्यादा होता है। वहां पर दूसरा उत्पादन संतरे का होता है, जो दार्जिलिंग में होता है। दार्जिलिंग क्षेत्र नेपाल, भूटान और बंगलादेश से जुड़ा हुआ है। वहां से संतरा नेपाल को निर्यात होता है। बंगलादेश ने अपनी कस्टम ड्यूटी में दार्जिलिंग का संतरा, मतलब यदि वहां भारत का संतरा इम्पोर्ट होता है, तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगा दी है जबकि भूटान का संतरा ड्यूटी फ्री रखा है। इस कारण हमारे दार्जिलिंग के किसानों को बहुत तकलीफ होती है।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय दूसरे विभागों से चर्चा करके वहां के किसानों की रक्षा करने के लिए कोई उपाय ढूंढेगा?

डॉ. संजीव बालियान : अध्यक्ष महोदया, यह बात सच है कि कुछ फैसिलिटीज नार्थ ईस्ट में कम हैं चाहे वे प्रोसेसिंग की हों या स्टोरेज की हों। इस बारे में कृषि मंत्रालय और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री द्वारा कई स्कीम्स जारी की गयी हैं, लेकिन उनमें अभी उतना काम नहीं हुआ, जितना सांसद महोदय ने बताया है। सरकार का मूलभूत सुविधाओं पर लगातार ध्यान है, चाहे वह स्टोरेज हो या प्रोसेसिंग हो, क्योंकि माननीय सदस्य को मालूम है कि वहां पर ट्रांसपोटेशन खर्च बहुत आता है। जब तक प्रोसैस नहीं होगा, तब तक फल खराब हो जायेगा। ...(व्यवधान) आप पश्चिम बंगाल के बारे में कह रहे हैं। यह ठीक है कि देश में इन चीजों की कमी है, लेकिन इन पर लगातार काम चल रहा है। दोनों मिनिस्ट्रीज मिलकर इस पर काम कर रही हैं। ...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : बांग्लादेश जो जा रहे हैं, उसके बारे में बताएं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसके बारे में बात कर लेंगे।

...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : इस बारे में संबंधित लोगों से चर्चा कर लेंगे।

(Q. 224)

श्री राघव लखनपाल : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष एक ऐसा विषय रखना चाहता हूं जिसके बारे में शायद इससे पहले भी सदन में चर्चा हुई है। हम सब जानते हैं कि ओलम्पिक, कॉमन वैल्थ या एशियाड खेल होते हैं, तो भारत की जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से मैडल टैली में हम बहुत नीचे का स्थान पाते हैं। हमें शर्म भी आती है कि हमारे देश के किसी शहर से छोटे देश ज्यादा मैडल पाते हैं। पिछली सरकार की नीति कहीं न कहीं खेल को लेकर गलत रही है या मानिटरिंग मैकेनिज्म की कमी रही है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या नई सरकार कोई ऐसा मानिटरिंग मैकेनिज्म बनाने का विचार कर रही है जिससे जूनियर, मिडल या सीनियर लैवल पर स्कूलों और कॉलेजों में खेलों को प्रोत्साहन दिया जाए? इसके साथ यह भी देखा जाए कि जो बजट खेलों के लिए एलोकेट हो रहे हैं, क्या उसका खर्च सही तरीके से हो रहा है?

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Madam, the hon. Member has brought a very, very important question to his House. This is a very serious matter for all of us. As you know, sports is a State subject and to promote sports and its development, both the State and the Centre must go hand-in-hand. In this regard, whatever policy that has been framed, is aimed to promote and develop sports in the country. Particularly, our hon. Prime Minister has given a lot of emphasis for the promotion of sports in the country. That is why, in the last Budget there was an additional allocation of resources.

As you know, particularly to target medals in the international events, we have to prepare from the grassroots, that is, from the school level. At the same time, now-a-days sports science and sports medicine have become an integral part of the entire exercise. That is why, physical fitness is very essential for all the school children to develop their ability in different disciplines of sports.

As you know, the subject of sports in school comes under the domain of the Ministry of Human Resource Development. We have been working with them to closely integrate sports and physical education with school education. From our side, SAI has always been conducting sports talent contest at different levels. Even

through our Rajiv Gandhi Khel Abhiyan we conduct rural sports, woman sports, backward region sports and North-Eastern Region sports. Also, of late, we have included one more scheme, that is called Himalayan Region Sports. These are aimed to cater to our school children for a better tomorrow.

I would like to inform the hon. Member of Parliament that this Government has decided to launch a new scheme in the next year, that is, National Sports Talent Search Scheme for children between the age of 8 and 12. This particular talent search scheme will be conducted at the block and district levels in every State. After completion of this particular test, a number of talented school going children will be selected and groomed accordingly. At the State level, junior sports academies and sport hostels equipped with better training facilities and better exposure will also be started for them. This is the target we have fixed for the future sports in India.

श्री राघव लखनपाल : माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे देश में ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर या जो बड़ी जनसंख्या वाले गांव हैं, वहाँ स्पोर्ट्स सेन्टर्स खोलने के लिए या जो स्पोर्ट्स से संबंधित फैसिलिटीज हैं, जैसे मेरे लोक सभा क्षेत्र सहारनपुर में हर वर्ष कबड्डी की एक बहुत प्रतियोगिता होती है, उसमें विभिन्न क्षेत्रों से लोग आते हैं। लेकिन वहाँ के जो खिलाड़ी हैं, वे अपने आप ही किसी तरह से पैसा इकट्ठा करके या चन्दा करके उसका आयोजन करते हैं। सरकारों की तरफ से उनको कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। मेरा यह कहना है कि ग्राम स्तर पर हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, उस प्रतिभा को और उभारने के लिए सरकार कोई विशेष योजना तैयार करेगी?

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Madam, we have a scheme, that is, Rural Sports Competitions. We give financial assistance to the States and the Union Territories. At block level we give Rs.1 lakh per block, at district level Rs.4 lakh per district, at State level Rs.2 lakh per district and at national level Rs.10 lakh per discipline. This is mainly to groom talent in the countryside.

I would like to make a sensible request to the hon. Members of this august House to help these four competitions to grow and develop, namely, Rural Sports Competitions, Woman Sports Competitions, North East Games and Sports Competition for Left Wing Extremism affected areas. If we could organize these competitions perfectly, then definitely our talents in villages will get a chance to prosper distinctly.

HON. SPEAKER: Shri J.C. Divakar Reddy – Not present.

Shrimati Ranjeet Ranjan.

श्रीमती रंजीत रंजन : माननीय अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी खुद भी खिलाड़ी हैं, हम लोग पूर्व में क्रिकेट भी खेलते थे। आपने उत्तर में जो आर.जी.के. स्कीम का ब्यौरा दिया है, ग्राम पंचायतों में खेल मैदानों का विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय के महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत किया जाएगा। लेकिन हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि अभी साढ़े चार सौ जिलों में चल रही मनरेगा योजना को आप दो सौ जिलों में करना चाह रहे हैं। पंचायतों और ब्लॉक्स में जो पहले से राजीव गांधी खेल प्राधिकरण के तहत चल रहा था तो आपने जो उत्तर दिया और जो लिखित रूप में है, उसमें बहुत अंतर है। जैसा कि माननीय सांसद कह रहे थे कि गांव लेवल पर आप किस प्रकार से डेवलप करेंगे। आपने उसका उत्तर दे दिया, लेकिन जो लिखित में है- ग्रामीण स्तर पर खेल मैदानों का विकास, ग्रामीण व मनरेगा स्कीम के अंतर्गत शुरू किया जाना था क्योंकि एम.जी.आर.वाई. अधिनियम का प्रमुख हिस्सा केवल श्रम विकास के लिए था, इसलिए मंत्रालय ने अधिक बजट के साथ ब्लॉक लेवल पर खेल के अवसंरचना के विकास पर ध्यान दिया। अब आपने पाँच लाख से 1.6 लाख कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कितने ब्लॉक्स और पंचायतों में यह स्कीम पहले से चल रही थी, कितने ब्लॉक्स और पंचायतों में अभी तक इसका लाभ हुआ है। आप छः महीने का ही बता दें, क्योंकि मनरेगा का मई महीने से ही पेमेंट नहीं हुआ है। स्कीम थी कि पंचायतों में खेल का मैदान देंगे, ब्लॉक में स्टेडियम देंगे और बच्चों का भत्ता जो ब्लॉक लेवल पर मात्र पाँच हजार रुपए का है, उसकी राशि बढ़ाएंगे। एक व्यक्ति व बच्चे का भत्ता दो सौ साठ रुपए है, उसमें उसका किराया भी है, यह जो मिनिमम रिक्वायर्ड राशि है, क्या आप इसे और बढ़ाएंगे? माननीय सांसद जो पूछ रहे थे, क्या इसके इम्प्लीमेंटेशन में करप्शन घटेगी ताकि बच्चे की प्रतिभा आगे आ सके।

SHRI SARBANANDA SONOWAL : Madam, I would like to let the hon. Member know that the Rajiv Gandhi Khel Abhiyan (RGKA) has started from this year. Till February, it was PYKKA and later on PYKKA was replaced by RGKA. So, through this scheme, we will definitely reach to all the blocks in the country, and the Gram Panchayats will also develop playgrounds for all children to play.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। खेलों के बारे में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आज यहां रखा गया है। मुझे लगता है कि आज भी भारत में बहुत कम ऐसे परिवार होंगे जो सोचते होंगे कि उनके बच्चों का भविष्य खेलों में है। खेलों के माध्यम से रोजगार नहीं मिलता है, अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद भी उन लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है, एक बड़ी समस्या यह है। दूसरे, जब कोई व्यक्ति खेलना शुरू करता है, तब आधारभूत ढांचा अच्छा नहीं होता और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कम पैसा खर्च होता है। दुनियाभर के देशों में ज्यादा से ज्यादा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च किया जाता है कि खिलाड़ियों की क्षमता को कैसे अच्छा बनाना है, जिससे वे ज्यादा से ज्यादा मेडल्स जीतें। वहां क्वांटिटी के साथ-साथ क्वालिटी पर काम किया जाता है। लेकिन कई वर्षों से भारत सरकार ने ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं चलाया जिससे मेडल्स जीतने के लिए ज्यादा प्रयास किए जाएं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सरकार ऐसा करने जा रही है जिससे वर्ष 2016 और 2020 के ओलम्पिक्स में हम ज्यादा से ज्यादा मेडल्स जीतें, इसके बारे में सरकार की क्या योजना है?

SHRI SARBANANDA SONOWAL : Madam, we have constituted a Committee called the Target Olympic Podium (TOP). This Committee comprises many veteran players of the country who have brought so many laurels to the country from international events. So, this Committee will select elite athletes, a minimum of 150, and this group of athletes will be groomed and they will be given all possible support by our Government so that they can bring medals from the Olympics.

DR. MRIGANKA MAHATO : Respected Madam, it has been found that different sports are popular in different parts of India like football is popular in Bengal, North-East and Goa, and archery and athletics is popular in Jharkhand and several other States. So, my request to the Central Government is that the Central Government should concentrate on specific sports; target specific areas; and set-up

sports academies so that those sports can be developed in that area and grooming can be done properly.

SHRI SARBANANDA SONOWAL : Yes, I do agree with you, and for your information, we are going to start so many academies in the coming years so that we could facilitate our sportspersons to have better training facilities.

श्री मोहम्मद सलीम : मैडम, कई प्रश्नों के जवाब आए हैं, लेकिन करीब दो दशक पहले जब संसद की पहली एचआरडी संसदीय समिति बनी थी, उसने खेल-कूद के बारे में सरकार को कुछ मशविरा दिया था। उसके बाद कई सरकारें आईं, कई खेल मंत्री आए, उस रिपोर्ट को खेल-खेल में लिया गया, सीरियसली नहीं लिया गया और आज भी वही बात हो रही है। मंत्री जी स्वयं पूर्वोत्तर भारत से आते हैं। आज बड़े शहरों के बजाय छोटे-मझोले शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से टैलेंट खेल के मैदान में आ रहा है, लेकिन हम इवेंट्स के ऊपर जोर देते हैं जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स। सरकार उसके लिए पैसे देती हैं, खर्च होते हैं, स्पाँसरशिप आती है, उसमें कई लोग जेल में जाते हैं, कई लोग बेल पर रहते हैं, कई लोग खेल में रहते हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सलीम जी, प्रश्न पूछिए। आप खेल-खेल में बहुत कुछ कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : जो बेल पर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री मोहम्मद सलीम : मैं स्पष्ट कह रहा हूं। ग्रामीण क्षेत्र में सब-डिवीजन लेवल और तालुका लेवल पर अगर आप स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, कई स्कीम्स हैं, वे खेलना चाहते हैं और इसके लिए उनको शहरों में आना पड़ता है। आजकल प्राइवेट एकेडेमीज आ रही हैं। उस टेलेंट को क्या आप ज्यादा स्कॉलरशिप देंगे, जिससे उन्हें ज्यादा खुराक मिले, यातायात और रहने की सुविधा मिले। लोग सांसदों के पास आते हैं कि हमारे पास ट्रेन का किराया नहीं है, हम कैम्प में जा नहीं सकते हैं। इसलिए ये स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड जो जिला लेवल के टेलेंटेड युवा हैं उन्हें सीधा-सीधा देंगे या नहीं?

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Madam, this is a very, very important suggestion which the hon. Member has given. For the talented sportspersons, the Government will definitely try to find some way to help them out.

श्रीमती संतोष अहलावत : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहती हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में खेल के सुदृढ़ मैदान नहीं हैं। क्या ग्रामीण क्षेत्र में लुप्त होते हमारे परम्परागत खेलों के संवर्धन के लिए भी मंत्री जी कोई योजना बनाना चाहते हैं?

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Madam, as I have already said, through Rajiv Gandhi Khel Abhiyan, we will develop playfields at *Gram Panchayat* levels which could accommodate our boys and girls in the villages. The target is to reach the villages. We have got so many villages in the country. Our Ministry's target will be to reach the remotest villages so that we could detect talented sportspersons, bring them on to the right platform and give them the best possible facilities to play for India in the future.

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदया, खेल के सवाल का समाधान, केवल प्रश्न-उत्तर से होने वाला नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : आप इस पर चर्चा मांग लीजिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि देश की संसद इस पर ईमानदारी से चर्चा करे और एक खेल नीति बने। मैं आपके माध्यम से इस सवाल पर ही एक सवाल करना चाहता हूं। मैं कुश्ती का खिलाड़ी रहा हूं और मैं जानता हूं कि कुश्ती के खिलाड़ियों को क्या-क्या दिक्कतें रही हैं, कितनी परेशानियों से उन्हें गुजरना पड़ता है। यह कोई राजनीति का सवाल नहीं है, यह सवाल देश की मर्यादा का है। पहले तो यही तय नहीं हो पाता है कि मैडल किस खेल से मिलता है।

अध्यक्ष महोदया, क्रिकेट के खिलाड़ियों का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन लगता है कि क्रिकेट के खिलाड़ी को ब्रह्मा खुद बनाते हैं और ग्रामीण खेल के खिलाड़ियों को उसके कारिंदे बनाते हैं। हम लोग कुश्ती के खिलाड़ी हैं, माननीय मुलायम सिंह जी कुश्ती के खिलाड़ी हैं, हमारे गृह मंत्री जी बैठे हैं वह भी कुश्ती के खिलाड़ी रहे हैं। ये लोग जानते हैं कि ग्रामीण खेलों में केवल खिलाड़ी पैदा नहीं होते हैं, समाज में समरसता और समाज को सुदृढ़ करने की शक्ति उन खेलों के मैदानों में होती है।

माननीय अध्यक्ष : आप या तो प्रश्न पूछिये या फिर आधे घंटे की चर्चा मांगिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैं आपसे आधे घंटे की चर्चा मांग रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : लिखित में दीजिएगा।

...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मैडम, सरिता देवी बॉक्सर के बारे में पूछना चाहता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं सबकी भावना समझ रही हूं। आप भारतीय खेलों के बारे में लिखित में चर्चा मांग लीजिएगा, हम दे देंगे।

(Q. 225)

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु : अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार को गन्ने के हर खेत के एक-एक एकड़ से 20 हजार रुपये से 25 हजार रुपये की आमदनी टैक्स के रूप में मिलती है। हमारे देश में लगभग 640 शुगर इंडस्ट्रीज हैं और उनमें से पिछले साल 570 ही चली हैं। उनकी परिस्थिति देखें, तो केवल 20 इंडस्ट्रीज ही प्रौफिट में हैं। महोदया, एक अप्रैल तक 14 हजार करोड़ रुपये की किसानों की पेमेंट उन पर पैंडिंग है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हर शुगर इंडस्ट्री में शुगर-वेस्ट प्रोड्यूस होता है। क्या हम उस वेस्ट के ज़रिए रिन्यूबल एनर्जी प्रोड्यूस करना मेन्डेटरी कर सकते हैं? मेरा इसके साथ छोटा सा सजेशन भी है कि इससे हम रिन्यूबल एनर्जी को प्रोमोट करेंगे। यदि हम किसानों को सरकार की तरफ से दें तो वह किसानों और इंडस्ट्री को मदद देने वाला होगा। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या विचार कर रही है?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : महोदया, पूरे सदन को एप्रीशिएट करना चाहिए कि आंध्र प्रदेश से एक यंग सांसद इतनी अच्छी हिन्दी बोल रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : यह बहुत अच्छी बात है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बकाया के बारे में जो प्रश्न किया था उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2013-2014 में किसानों के कुल-मिलाकर 58,269 करोड़ रुपये बनते थे। इसमें से 54,621 करोड़ रुपये की पेमेंट हो चुकी है। अब सिर्फ 3,648 करोड़ रुपये ही बकाया बचे हैं। जिसमें से उत्तर प्रदेश का बकाया 1,157 करोड़ रुपये है। कर्नाटक का बकाया 1,725 करोड़ रुपये बकाया है। हमारे पास सभी राज्यों के बकाया का आंकड़ा है। महाराष्ट्र का 40.13 करोड़ रुपये बकाया है। मैं सभी राज्यों का बकाया बता देता हूं, तमिलनाडु का 363 करोड़ रुपये, बिहार का 98 करोड़ रुपये, उत्तराखण्ड का 199 करोड़ रुपये, गुजरात का 2.26 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश का 36 करोड़ रुपये, तेलंगाना का जीरो, मध्य प्रदेश का जीरो, पुड्डुचेरी का 15 करोड़ रुपये, ओडिशा का जीरो, पश्चिम बंगाल का 4.92 करोड़ रुपये, पंजाब का जीरो, हरियाणा का जीरो, गोवा का जीरो और छत्तीसगढ़ का जीरो बकाया है।...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश में जिनके ऊपर बकाया है, उनमें बजाज मिल के पास 224 करोड़ रुपये, मोदी मिल के पास 299 करोड़ रुपये, मवाना के पास 364 करोड़ रुपये और सम्भावली के पास 155 करोड़ रुपये हैं।

जहां तक सरकार का प्रश्न है, सरकार दोनों के लिए चिंतित है। हम मिल मालिक के लिए भी चिंतित हैं और किसानों के लिए भी उतना ही चिंतित हैं। इस संबंध में जब मामला आया, उस समय उत्तर प्रदेश की समस्या ज्यादा विकट थी। हम लोगों ने एक बैठक बुलायी थी, जिसमें कलराज मिश्र जी, मेनका गांधी जी, गडकरी जी, बालियान जी, राधा मोहन जी और सीतारमण जी थीं। हम लोगों ने बैठ कर के इस पर गम्भीरता से विचार किया और विचार करने के बाद, जो हमने प्रश्न के जवाब में भी दिया है कि मिल मालिक की तरफ से हमारे पास चार सुझाव आए थे, उसमें पहला था कि इम्पोर्ट ड्यूटी को 15 से बढ़ाकर 40 कर दिया जाए। हमने इसे 25 कर दिया, क्योंकि जब 10 में ही इम्पोर्ट नहीं हो रहा है और 15 और 25 में भी कुछ इम्पोर्ट नहीं हुआ, इसलिए 40 तक बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं था। दूसरा, एक्सपोर्ट इनसेंटिव्स के लिए था। एक्सपोर्ट इनसेंटिव वर्ष 2013-2014 और 2014-2015 के लिए बढ़ाया गया था। सितम्बर महीने में वर्ष 2013-2014 खत्म हो गया है। इस पर हम पुनर्विचार कर रहे हैं। तीसरा, सॉफ्ट लोन के बारे में था। इसमें 66 सौ करोड़ रुपये दिए गए, जिसमें से 64 सौ करोड़ रुपये बांटे गए। चौथा, इथेनॉल का था। इथेनॉल जो दो परसेंट था, उसको दस परसेंट तक बढ़ाने के लिए कहा गया, जिसे हमने मान लिया है और दस परसैन्ट तक बढ़ाने का हम लोगों ने काम किया।

जहां तक इन्होंने वेस्ट रीन्युएबल इनर्जी के संबंध में कहा है, उस संबंध में इनका जो सुझाव है, उस संबंध में हम सोचेंगे।

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु : अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया था कि पांच परसैन्ट मेन्डिंग ऑफ एल्कोहल मैनडेटरी है और अगर हम अभी ग्राउंड लैवल में परिस्थिति देखें तो ऐसा नहीं चल रहा है। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो ई.बी.पी. स्कीम है, इसे ऑनर नहीं कर रहे हैं तो इसकी वजह से शुगर इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा प्राब्लम हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि आपका इसके बारे में क्या विचार है?

श्री राम विलास पासवान : जो मिल मालिक है, वह एक परसैन्ट कर रहा है, कोई जीरो परसैन्ट कर रहा है। इसलिए हमने कहा कि पांच परसैन्ट कम्पलसरी है, लेकिन यदि कुल मिलाकर कोई 5% नहीं कर रहा है, दूसरा दस परसैन्ट तक कर सकता है। हमारी समझ से इथनोल मिल मालिक के लिए सबसे ज्यादा

लाभदायक चीज है और उसे जिस दिन दस परसैन्ट तक का पैट्रोल में मिश्रण कर दें, अभी यह सबसे ज्यादा शराब में जाता है, कैमिकल्स में जाता है, शराब वाला सीधे जाकर खरीद लेता है, कैमिकल्स वाला भी खरीद लेता है। पैट्रोल के लिए सरकार का नियम है, उसमें टेंडर वगैरह का नियम है। इसलिए जो इथनोल वाला मामला है, वह बहुत महत्वपूर्ण मामला है और हम उसे इंडस्ट्रीज में भी प्रोत्साहन देने के लिए तैयार हैं।

12.00 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be Laid on the Table.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : अध्यक्ष महोदया, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1)(एक) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library, See No. LT 1039/16/14)

(2)(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जातियां वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जातियां वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library, See No. LT 1040/16/14)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Madam, on behalf of my colleague Shri Prakash Javadekar, I beg to lay on the Table:

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under Sections 3, 12 & 13 of the Environment (Protection) Act, 1986:-

(i) S.O. 1680(E) published in Gazette of India dated 2nd July, 2014, making certain amendments in Notification No. S.O. 1174(E) dated 18th July, 2007.

(ii) S.O. 2003(E) published in Gazette of India dated 6th August, 2014, making certain amendments in Notification No. S.O. 1174(E) dated 18th July, 2007.

(iii) S.O. 1880(E) published in Gazette of India dated 22nd July, 2014, making certain amendments in Notification No. S.O. 93(E) dated 29th January, 1998.

(Placed in Library See No. LT 1041/16/14)

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 26 of the Environment (Protection) Act, 1986:-

(i) The Environment (Protection) (Fifth Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 612(E) in Gazette of India dated 25th August, 2014.

(ii) The Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014 published in Notification No. S.O. 1033(E) in Gazette of India dated 4th April, 2014.

(Placed in Library See No. LT 1042/16/14)

(3) A copy of the Forest (Conservation) Second Amendment Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 713(E) in Gazette of India dated 10th October, 2014 under sub-section (2) of Section 4 of the Forest (Conservation) Act, 1980.

(Placed in Library See No. LT 1043/16/14)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): महोदया, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1)(एक) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library See No. LT 1044/16/14)

(2)(एक) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library See No. LT 1045/16/14)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI G.M. SIDDESHWARA): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(1) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Heavy Engineering Corporation Limited, Ranchi, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Heavy Engineering Corporation Limited, Ranchi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library See No. LT 1046/16/14)

(2) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Andrew Yule and Company Limited, Kolkata, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Andrew Yule and Company Limited, Kolkata, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library See No. LT 1047/16/14)

(3) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the National Bicycle Corporation of India Limited, Mumbai, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the National Bicycle Corporation of India Limited, Mumbai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library See No. LT 1048/16/14)

(4) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Sambhar Salts Limited, Jaipur, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Sambhar Salts Limited, Jaipur, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library See No. LT 1049/16/14)

(5) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Hindustan Salts Limited, Jaipur, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Hindustan Salts Limited, Jaipur, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library See No. LT 1050/16/14)

(6) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Bharat Heavy Electricals Limited, New Delhi, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Bharat Heavy Electricals Limited, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library See No. LT 1051/16/14)

(7) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Engineering Projects (India) Limited, New Delhi, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Engineering Projects (India) Limited, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library See No. LT 1052/16/14)

(8) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Hindustan Cables Limited, Kolkata, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Hindustan Cables Limited, Kolkata, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library See No. LT 1053/16/14)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the 44th Annual Assessment Report (Hindi and English versions) regarding Programme for accelerating the spread and development of Hindi and its progressive use for various official purposes of the Union and its implementation for the year 2012-2013.

(Placed in Library See No. LT 1054/16/14)

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 77 of the Disaster Management Act, 2005:-

(i) The National Institute of Disaster Management Employees (Recruitment and Other Conditions of Service) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 600(E) in Gazette of India dated 21th August, 2014.

(ii) The Disaster Management (Term of Office and Conditions of Service of Members of the National Authority and Payment of Allowances to Members of Advisory Committee) Second Amendment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 669(E) in Gazette of India dated 18th September, 2014.

(iii) G.S.R.668(E) published in Gazette of India dated 18th September, 2014, containing corrigendum to the Notification No. G.S.R.544(E) dated 30th July, 2014.

(Placed in Library See No. LT 1055/16/14)

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under Section 389 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994:-

(i) S.O.2238(E) published in Gazette of India dated 5th September, 2014, relating to the dissolution of the New Delhi Municipal Council.

(ii) S.O.2239(E) published in Gazette of India dated 5th September, 2014, constituting New Delhi Municipal Council and consisting of members, mentioned therein.

(Placed in Library See No. LT 1056/16/14)

(4) A copy of the Central Reserve Police Force, Pioneer Cadre (Group B Combatised Posts) Recruitment Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 639(E) in Gazette of India dated 9th September, 2014 under sub-section (3) of Section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949.

(Placed in Library See No. LT 1057/16/14)

(5) A copy of Notification No. S.O. 2648(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 16th October, 2014, exempting the 'International Union for Conservation of Nature and natural Resources' an international organization from the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 issued under sub-section (1) of Section 2 of the said Act.

(Placed in Library See No. LT 1058/16/14)

(6) A copy of the Andhra Pradesh Reorganisation (Removal of Difficulties) Order, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 725(E) in Gazette of India dated 15th October, 2014 under sub-section (1) of Section 108 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014.

(Placed in Library See No. LT 1059/16/14)

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) :

महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : -

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे :-

(क)(एक) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library See No. LT 1060/16/14)

(ख)(एक) एम.पी. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एम.पी. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library See No. LT 1061/16/14)

(ग)(एक) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library See No. LT 1062/16/14)

(घ)(एक) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library See No. LT 1063/16/14)

(3)(एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library See No. LT 1064/16/14)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : महोदया, मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 39 की उप-धारा (3)के अंतर्गत खाद्यान्न की कम आपूर्ति हेतु राज्य सरकारों के लिए निधियों की व्यवस्था नियम, 2014 जो 27 अक्टूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 743 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(Placed in Library See No. LT 1065/16/14)

HON. SPEAKER: Shri Vijay sampla -- Not present.

12.02 hrs

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

(i) "In accordance with the provisions of Rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 8th December, 2014 agreed without any amendment to the Textile Undertakings (Nationalisation) Laws (Amendment and Validation) Bill, 2014 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 1st December, 2014."

(ii) "In accordance with the provisions of Rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 8th December, 2014 agreed without any amendment to the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2014 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 27th November, 2014."

12.03 hrs

STANDING COMMITTEE ON LABOUR
Statments

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : -

(1) " फिरोजाबाद के कांच और चूड़ी कर्मकारों का कल्याण " के बारे में 32वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार की-गई-कार्रवाई संबंधी 45वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 36वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार की-गई-कार्रवाई संबंधी 39वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-अग्रेत्तर कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(3) श्रम और रोज़गार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 35वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार की-गई-कार्रवाई संबंधी 41वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-अग्रेत्तर कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(4) " इलाहाबाद बैंक के अस्थायी ड्राइवरों का आमेलन/नियमितिकरण " के बारे में 31वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार की-गई-कार्रवाई संबंधी 43वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(5) " मऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में बुनकरों का कल्याण-एक मामलापरक अध्ययन " के बारे में 38वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार की-गई-कार्रवाई संबंधी 46वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-अग्रेत्तर कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

12.04 hrs

STATMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 57th Report of the Standing Committee on Agriculture on National Institute of Food Technology, Enterpreneurship and Managment (NIFTEM), pertaining to the Ministry of Food Processing Industries*

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): महोदया, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता वृत्ति और प्रबंध संस्थान (एनआईएफटीईएम) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 57वें प्रतिवेदन में अतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं।

मैं संलग्नक में दी गई सारी सामग्री पढ़कर सदन का मूल्यवान समय नष्ट नहीं करना चाहूंगी। मैं अनुरोध करूंगी कि इसे पढ़ा गया समझा जाए।

---

* Laid on the Table and also placed in Library. See No. LT 1067/16/14

12.05 hrs

ELECTION TO COMMITTEE

Welfare of Other Backward Classes

SHRI RAJEN GOHAIN (NOWGONG): I beg to move:

> "That the members of this House do proceed to elect, under sub-rule (3) of rule 254, two members from amongst themselves to serve as members of the Committee on Welfare of Other Backward Classes for the unexpired portion of the term of the Committee *vice* Sarvashri Bandaru Dattatreya and Hansraj Gangaram Ahir appointed Ministers."

HON. SPEAKER: The question is:

> "That the members of this House do proceed to elect, under sub-rule (3) of rule 254, two members from amongst themselves to serve as members of the Committee on Welfare of Other Backward Classes for the unexpired portion of the term of the Committee *vice* Sarvashri Bandaru Dattatreya and Hansraj Gangaram Ahir appointed Ministers."

The motion was adopted.

12.06 hrs

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Abduction of and harassment meted out to Tamil Fishermen by Sri Lankan Navy and steps taken by the Government in this regard

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Madam, I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and request that she may make a statement thereon:

> "The problem regarding abduction of and harassment meted out to Tamil Fishermen by Sri Lankan Navy and steps taken by the Government in this regard"

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं माननीय सदस्य डा.पी.वेणुगोपाल, श्री पी.कुमार, डा.सत्यपाल सिंह, डा.जयकुमार जयवर्धन और डा.के.गोपल द्वारा श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिल मछुआरों के अपहरण एवं उन्हें प्रताड़ित किये जाने से उत्पन्न समस्या तथा इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदम के संबंध में रखे गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर उत्तर देना चाहती हूं।

प्रारम्भ में मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि भारतीय मछुआरों की सुरक्षा एवं उनके कल्याण को सरकार उच्च प्राथमिकता देती है। हम इस समस्या को एक मानवीय समस्या के तौर पर देखते हैं, जिससे हमारे मछुआरा समुदाय का जीवनयापन जुड़ा हुआ। जब भी हमारे मछुआरों पर हमलें की घटनाएं होती हैं और इसके फलस्वरूप श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा उन्हें पकड़ने की घटनाएं प्रकाश में आती हैं, हमारी सरकार राजनयिक माध्यमों के जरिये उन्हें तुरंत श्रीलंका सरकार के साथ उठाती है। साथ ही सरकार यह सुनिश्चित भी करती है कि श्रीलंकाई अधिकारी संयम बरतें और हमारे मछुआरों के साथ मानवीय व्यवहार करें और उन्हें जल्द से जल्द रिहा करें।

हमारी सरकार ने इस मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए इसे श्रीलंका सरकार के साथ उच्च स्तर पर उठाया है। माननीय प्रधान मंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति महेन्द्र राजपक्षे के साथ मई 2014 में हुई उनकी पहली बैठक में इस मामले को उठाया था। दोनों नेताओं ने हाल ही सितम्बर, 2014 में न्यूयार्क में और नवम्बर, 2014 में काठमांडू में अपनी मुलाकात के दौरान भी इस समस्या के स्थाई समाधान की जरूरत पर

जोर दिया और मैंने भी श्रीलंका के विदेश मंत्री, श्री जी.एल.पीरिस की 11 जुलाई, 2014 की नई दिल्ली यात्रा के दौरान उनके साथ इस मामले पर विस्तार से चर्चा की थी।

माननीय सदस्यों को यह ज्ञात होगा कि हाल ही में 5 भारतीय मछुआरों को 30 अक्टूबर, 2014 को कोलंबो उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड सुनाने से जो उनकी समस्या उत्पन्न हुई थी, हमारी सरकार ने अपने सतत प्रयासों से सफलतापूर्वक उसका समाधान किया है। 19 नवम्बर, 2014 को श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा इन सभी 5 मछुआरों की सजा पूरी तरह समाप्त कर दी गई। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इसमें हिन्दी अनुवाद अंग्रेजी से थोड़ा फर्क हो गया था, इसलिए मैंने सही पढ़ा है। मैं अंग्रेजी में इसे पढ़ देती हूं -

"On 19th November 2014, the President of Sri Lanka granted full remission of the sentence to all five fishermen. These five fishermen have since returned back to their families in India."

19 नवम्बर, 2014 को श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा इन सभी 5 मछुआरों की सजा पूरी तरह समाप्त कर दी गई और ये पाचों मछुआरे अब भारत में अपने परिवारों के पास वापिस आ गये हैं।

माननीय सदस्य इस बात पर गौर करेंगे कि अक्बर, 2008 में भारत और श्रीलंका के मछुआरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा (आई.एम.बी.एल.) को लांधने से उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए आपसी समझ बनाई थी। इसके बाद किए गए व्यावहारिक उपायों से इस प्रकार की घटनाओं में काफी कमी आई है। अप्रैल, 2011 से अब तक किसी भारतीय मछुआरे के श्रीलंकाई समुद्री क्षेत्र में मार जाने की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है। हमारी सरकार के सतत् प्रयासों से वर्ष 2014 में अब तक श्रीलंका की पकड़ से 706 भारतीय मछुआरों को रिहा करवाया गया है। आज की तिथि में 38 भारतीय मछुआरे और उनकी 82 नावें मत्स्यन संबंधी उल्लंघनों के कारण श्रीलंकाई सरकार के कब्जे में है। हम इन सभी की जल्द रिहाई और इनको भारत वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं।

भारत-श्रीलंका के मत्स्यन प्रबंधन पर बने संयुक्त कार्यदल की चौथी बैठक जनवरी 2012 में कोलंबो में हुई थी। इस बैठक में दोनों पक्षों ने अपनी सरकारों की ओर से दोनों देशों के मछुआरों की सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी। दोनों देश इस बात पर सहमत थे कि किसी भी हालत में ताकत के इस्तेमाल को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। दोनों पक्षों ने सभी मछुआरों के साथ मानवीय व्यवहार किए जाने पर भी जोर दिया। हाल ही में मत्स्यन प्रबंधन पर नवगठित संयुक्त कार्यसमिति की पहली बैठक 29 अगस्त 2014 को नई दिल्ली में हुई। इसके अलावा, मछुआरों की एसोसिएशन के स्तर पर भी 2014 में दो बार बातचीत

हो चुकी है। पहली बातचीत जनवरी 2014 में चेन्नई में और दूसरी बातचीत 12 मई 2014 को कोलंबो में हुई थी।

मैं सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप आए बदलाव का दिनांक 26 नवंबर 2014 को हुई एक घटना के माध्यम से उल्लेख करना चाहूंगी। इस दिन तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के तीन मछुआरे खराब मौसम में भटक कर अपनी टूटी नौका के साथ श्रीलंकाई समुद्र तट पर जा पहुंचे। इन मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा बचा लिया गया और उनकी मत्स्यन नौका की मरम्मत के लिए भी सहायता की गई। ये तीनों मछुआरे 8 दिसंबर 2014 को यानि कल वापस भारत पहुंच गए हैं।

मैं माननीय संसद सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगी कि सरकार संबंधित पक्षों के साथ आपसी सहयोग से इस समस्या के दीर्घकालिक समाधान पर भी कार्य कर रही है। इसमें एक अहम कदम हमारे मछुआरों द्वारा गहरे समुद्र में जा कर मछली पकड़ना यानि डीप-सी फिशिंग होगा। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगी कि सरकार ने ई.ई.जेड. में मत्स्यन को ले कर स्पष्ट और आसान दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिससे हमारे मछुआरों को मछली पकड़ने में सुविधा हो सके।

हमारे मछुआरों की सुरक्षा के संबंध में एक राष्ट्रीय स्वचालिक पहचान नेटवर्क (नेशनल ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन नेटवर्क) विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत छोटी मछली पकड़ने की नौकाओं में ए.आई.एस. ट्रांस्पोंडर्स लगा कर उनके जरिए उन पर निगरानी रखने का भी प्रावधान है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में एक पूर्व चेतावनी तंत्र स्थापित करने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।

भारत सरकार श्रीलंका सरकार के साथ सतत् बातचीत में है, जिससे दोनों देशों के मछुआरे एक सुरक्षित वातवरण में अपना जीवन-यापन कर सकें।

DR. P. VENUGOPAL : Hon. Speaker Madam, I want to raise some queries about this statement. The highhandedness of the Sri Lankan Navy with brutal and violent attacks our Indian fishermen on the high seas around our coastal areas of Tamil Nadu are on the increase. It has become a sad tale continuing unabated.

The small boats and trawlers are captured and are taken away by the Sri Lankan Navy personnel every now and then.

Recently five fishermen against whom false cases being foisted were sentenced to death by a higher court of Sri Lanka. From November 2011, the legal case of these five innocent Tamil Nadu fishermen from Rameswaram is being attended to by the compassionate Government of Tamil Nadu led by our beloved leader, Amma. At every stage during the proceedings, financial assistance was extended for both legal expenses and survival of their families. Totally, a sum of Rs 63.85 lakh has been spent on these fishermen families. All the five families were paid Rs.7,500 per family and in 2012, Rs. 2 lakh was given to every family of these five fishermen who were languishing in the Velikada prison, Colombo. The gracious Government of Tamil Nadu released Rs.20 lakh at the time of appeal before the Sri Lankan Supreme Court, arguing for the cancellation of the death sentence. At the instance of our leader, Amma, the Centre took it up with the Sri Lankan Presidium to get our innocent fishermen freed finally.

So far, there had been more than 500 attacks and 50 instances of capturing of boats of fishermen in the last two decades. More recently, 38 fishermen with 82 fishing vessels have been taken into custody by Sri Lanka from our international waters. Every time, the Government of India is doing a lip service that they are taking up the matter with that friendly country. Only when a lasting solution is found, in the form of retrieving Katchatheevu, the fishermen can freely go for their traditional occupation of fishing in and around our coastal areas.

I know that the matter of getting back Katchatheevu is before the courts of law. It is time for the Government of India to earnestly place before the supreme judicial body of the country, all the relevant documents pertaining to the original rights vested with the local rulers of Ramanathapuram at the time of Independence and for many years before that. The previous Governments have erred in judgment and they are shying away now, as they have handed over that small island without getting it ratified in the Parliament of India.

In the name of maintaining friendly relations, our Government must not lose sight of the strategic importance of that small island. When Shrimati Indira Gandhi was in the national scene and when our founder leader Bharat Ratna Dr. MGR was a tall statesman in the south, our security concerns were attended to properly. For instance, we opposed the setting up of a naval base of a super power in the Indian Ocean from Diego Garcia to Trincomalee. Now also, our visionary leader, Amma has pointed out to the presence and movements of the Chinese men in uniform in the coasts of Sri Lanka. The threat perception has been brought to the notice of the Union Government.

So, I would like to know from the Union Government whether they would try to understand the true feelings of the Tamils and try to find out a permanent solution to the vexed problem of our fishermen being attacked time and again. Will it not be possible to set up our own naval base in the vicinity of Palk Straits and the Gulf of Mannar after retrieving Katchatheevu?

I call the attention of the Government to the urgent need to save our fishermen and our country, and I would like to know whether any concrete action would be taken now to put an end to the sorry plight of the fishermen and whether the traditional fishing rights would be restored to our fishermen. Thank you.

SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): Madam Speaker, just now my leader has explained in detail, the problems that the Tamil fishermen are facing.

So, without going into all the details, I would restrict myself to say that the attacks on Tamil fishermen have become very frequent, and has become a regular feature.

HON. SPEAKER: You have to put only one clarificatory question.

SHRI P. KUMAR : Okay, Madam. I will come to the question. In the statement of the hon. Minister, there was no mention about Katchatheevu.

It is already said that Katchatheevu was originally owned by the Raja of Ramanathapuram. Historically it belonged to India and it is a part of Indian Territory. The island always had a strategic importance and a special significance to Tamil Nadu fishermen for fishing operations in that area. But over the years, Sri Lanka started claiming the territorial rights over the island, without any justification. Notwithstanding their claims, it continued to be a part of India.

But through two agreements in 1974 when Shri Karunanidhi was the Chief Minister of Tamil Nadu, and in 1976, the Island was ceded and it is unconstitutional. In the Berubari case, the Supreme Court made it clear that if any part of Indian Territory is to be ceded to any other country, it should be ratified by the Parliament by way of Constitutional Amendment. But nothing like this was done in this case.

Madam, the Tamil Nadu Assembly, under the leadership of hon. Puratchi Thalaivi Amma, passed a Resolution for retrieval of Katchatheevu. Hon. Amma had filed a case in the Supreme Court in this regard. Hon. Amma has also made the Revenue Department, a party to this dispute. When Tamil Nadu Government under the able leadership of Amma, is taking very good efforts in this regard, there seems to be no action from the Centre.

Only retrieval of Katchatheevu will give a permanent solution to the problems that the Tamil Fishermen are facing frequently. So, will the Government take steps to retrieve the Katchatheevu Island so that Tamil fishermen, without fear of being captured and harassed, go for fishing in the seas? Thank you.

SHRI SATYAPAL SINGH (SAMBHAL): Thank you Madam for giving me the opportunity to speak.

At the outset, I would like to congratulate and compliment our hon. Prime Minister and hon. External Affairs Minister for their laudable efforts to redress the grievances of Tamil Nadu fishermen.

We, as a nation, as a Party and as a Government, are deeply committed to the welfare, safety and security of our fishermen whether on Tamil Nadu coast or elsewhere. There are two-three main issues. My friend was mentioning about the Katchatheevu Island. We have had Agreements with Sri Lanka in 1974, 1976 and 2008 but there appears to be some confusion in these Agreements. I would like to submit that perhaps, there is a need to revisit these agreements so that no confusion is left.

Our two friendly neighbours are increasing their influence in the region of Bay of Bengal, especially near Sri Lanka. The hon. Minister has already mentioned it but there is a need to identify not only our boats but also to have transponders, smart cards for the crew and registration of the boats. There is a need to use our remote sensing agency to identify the exact locations of the known Indian ships and boats in that area. There is a need to do more homework to have better forensic analysis because there have been allegations of Sri Lankan Navy assaulting our fishermen. Can we find out the make, mode and origin of the ammunition and bullets used as it will help us to identify and pinpoint the culprit?

As it is a question of livelihood of thousands of fishermen in that area, can the Government think of allowing our fishermen and their fishermen to fish at least 25 km. deep in our waters and their waters? Thank you.

DR. J. JAYAVARDHAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Speaker, Madam, five innocent Tamil Nadu fishermen were arrested under false charges of drug trafficking by the Sri Lankan Navy. The Government of Tamil Nadu, under the dynamic leadership of hon. People's Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma,

provided relief measures and court expenses totaling Rs. 63,85,000. However, no relief measures were provided by the Central Government.

Let us look on the other side. According to the Marine Products Export Development Authority of India (MPEDA) Tamil Nadu fishermen contribute several thousands of crore in terms of foreign exchange to the Government of India through export of marine products. Has the Government of India done anything in return to the Tamil Nadu fishermen who contribute so much of revenue to our country?

While replying, the hon. Minister mentions about migration of our fishermen to deep sea fishing. In this context, it is necessary to accentuate the fact that a number of issues have been highlighted by our former hon. People's Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma in a Memorandum submitted to hon. Prime Minister, namely:

1. Comprehensive special package of Rs.1,520 crore and a recurring grant of Rs.10 crore per annum for maintenance and dredging
2. Diversification of bottom trawlers into Deep Sea Tuna Long Liners at a cost of Rs.975 crore over three years
3. Rs.80 crore for assistance for Mid Sea Fish Processing Park
4. Reimbursement of central excise duty on high speed diesel for mechanised boats
5. Rs.9 crore per year to ensure motorisation of traditional crafts
6. Rs.420 crore for creation of infrastructure deep sea fishing facility at Mookaiyur, Rameswaram and Ennore Fishing Harbours.
7. Rs.10 crore per year for dredging of harbour and bar mouths but all of these things are still pending before the Government of India.

In regards to the capsized boats of TN fishermen by Srilankan Navy, they are kept off shore. They are damaged by wind and rain and on return they are in

an unusable condition? Is there something on the mind of the Government of India to provide relief measures for repair of these boats?

Lastly, Hon. Speaker Madam, can't a clear, unequivocal, unambiguous message be sent to the Sri Lankan side that these hostile acts against Tamil Nadu fishermen will not be tolerated and that this should cease forthwith? Why can this message not be sent?

DR. K. GOPAL (NAGAPATTINAM): I would like to ask the Minister to take stringent action against the Sri Lankan Navy to stop the harassment and abduction of the Tamil fishermen who are fishing near the Katchatheevu.

It was originally under the ownership of the Raja of Ramanathapuram, for which there is sufficient documentary proof, that the Indian fishermen enjoyed traditional fishing rights in and around the Island of Katchatheevu. As per the agreements entered into in 1974 and 1976, Katchatheevu was ceded to Sri Lanka and the fishermen of Tamil Nadu were deprived of their fishing rights around Katchatheevu ever since then.

As per the order of the Supreme Court of India in the Berubari case of 1960, a part of any territory owned by India can be ceded to another country only through a constitutional amendment. However, Katchatheevu was ceded to Sri Lanka without a constitutional amendment and hence the ceding is unlawful and it is not valid. The unconstitutional ceding of the Island and the fishing grounds in the vicinity have emboldened the Sri Lankan Navy to resort to frequent attacks on our innocent fishermen who fish in their traditional fishing grounds.

Hence the Government of India should take active steps to abrogate the 1974 and 1976 agreements and retrieve Katchatheevu and restore the traditional fishing rights of the fishermen of Tamil Nadu.

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, हमारे पांच साथियों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, सभी साथियों ने अपनी बात सदन के सामने रख दी है। इनमें से चार साथियों ने लगभग एक जैसे मुद्दे उठाए हैं। डॉ. सत्यपाल जी ने जी.पी.एस. का केवल एक मुद्दा और जोड़ा है, इसलिए मैं सभी का उत्तर एक साथ दे देती

हूं। जैसा श्री पी. वेणुगोपाल ने कहा कि अम्मा जी के नेतृत्व में, यानी मैडम जयललिता के नेतृत्व में मछुआरों की बहुत मदद की गई, उन्हें लीगल असिसटेंस के लिए पैसा दिया गया। उन्हें कहा कि 63.8 लाख रुपए दिए गए। इस बात को वे मछुआरे एक्नोलेज करते हैं और हम भी एक्नोलेज करते हैं, जो उन्होंने किया है। लेकिन इसके बावजूद भी सच्चाई यह है कि इतना करने के बाद भी वे उन्हें सजा से मुक्त नहीं कर पाए और उन्हें मृत्यु दंड की सजा मिली, फांसी की सजा मिली। लीगल असिसटेंस देने के बाद भी, लीगल असिसटेंस का पैसा देने के बाद भी उन्हें मृत्यु दंड मिला। आज मैं यहां खड़े हो कर कह सकती हूं कि मृत्यु दंड को माफ कराने के लिए सर्वोच्च स्तर पर हमारे यहां से प्रयास हुआ है और उस कारण वे छूट कर आए हैं। इसलिए जहां आप अम्मा को लीगल असिसटेंस के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, वहां कम से कम सरकार को भी धन्यवाद दे दीजिए, जो उन्हें वहां से निकाल कर लाई है।

DR. P. VENUGOPAL : Madam, Tamil Nadu Assembly has passed a resolution thanking the hon. Prime Minister in this regard.

श्रीमती सुषमा स्वराज : धन्यवाद। दूसरी बात डॉ. के. गोपाल बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने इतना पैसा खर्च किया, लेकिन सरकार ने उन्हें किसी तरह की फाइनेंशियल असिसटेंस नहीं दी। इस बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि ये केस वर्ष 2011 से चल रहा है। वर्ष 2011 से 2014 तक वर्तमान सरकार नहीं थी इसलिए अगर किसी ने असिसटेंस नहीं दी, तो वह पुरानी सरकार उसके लिए जिम्मेदार है, आज की सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जहां तक हमारी सरकार का सवाल है हमने फांसी के बाद भी उन्हें बचाकर उनकी पूरी सजा माफ करवा कर लाए हैं।

मैं दूसरी बात कहना चाहती हूं कि यह बात ठीक है कि " फ्रिक्वेंट " शब्द सही है। फ्रिक्वेंट घटनाएं हो रही हैं। हमारे आने के बाद भी 22 घटनाएं हुई हैं, लेकिन अब बहुत बड़ा अंतर आया है। पहले जब ये गिरफ्तार किए जाते थे तो कभी 50 दिनों बाद, कभी 60 दिनों बाद, कभी 68 दिनों बाद छूटते थे। मैं आज सदन में खड़े हो कर बताना चाहती हूं कि हमारे आने के बाद ये घटनाएं 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 12 दिन में सुलझ रही हैं।

अध्यक्ष जी, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जो एक टोन एण्ड टेनर हम श्रीलंका के प्रति, श्रीलंकन नेवी के प्रति रखते थे, आज मैं यह कह सकती हूं कि इस नयी सरकार के आने के बाद भारत के प्रति श्रीलंका के रवैये में बहुत बदलाव आया है। उस बदलाव के दो उदाहरण मैंने अपने स्टेटमेंट में दिए। एक उदाहरण यह कि पांचों को फांसी की सजा से मुक्ति दिलाकर उनकी पूरी सजा को समाप्त करने का काम वहां के राष्ट्रपति ने किया और दूसरा यह कि जब जब हमारे मछुआरे भटक कर उनके तट पर पहुंच

गए तो वे उन्हें पकड़ सकते थे। जैसे वर्ष 2011 से पहले वे उन्हें गोली मार देते थे, वैसे वे मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ह्यूमैनिटैरियन ग्राउंड पर उन मछुआरों को डूबने से बचाया। वे मछुआरे डूब रहे थे, उनकी नौका टूट गयी थी। उन्होंने उनकी टूटी हुई नौका को सुधरवाया और उन्हें वापस भेज दिया। वे लोग भी कल सुबह वापस आ गए। यह जो उनका बदला हुआ रवैया है, उसके प्रति हमारे टोन एण्ड टेनर में भी थोड़ी कमी और थोड़ा बदलाव आना चाहिए।

अध्यक्ष जी, जहां तक कच्छतिवू का सवाल है, तो इस पर हमारे चार साथियों ने कहा और हमारे सत्यपाल जी ने भी कहा है। लेकिन, मैं आपके माध्यम से यह बता दूं कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। स्वयं मैडम जयललिता की एक रिट पेटीशन वहां पड़ी है। आप जानती हैं कि ऐसे विषय पर, जो ऑलरेडी सब-ज्यूडिस हो, उस पर कुछ भी कहना नियमों के विपरीत होगा। इसलिए मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी।

इन चार माननीय सदस्यों के अलावा सत्यपाल सिंह ने जो जीपीएस के बारे में बात की, तो मैंने अपने स्टेटमेंट में ही कहा है कि हम नेशनल ऑटोमैटेड इंटेग्रेशन आइडैंटिफिकेशन सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। यह इतना अच्छा सिस्टम है कि यह नौका पर ही लगा होगा और ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से इससे हम 50 किलो मीटर तक अपने मछुआरों को ट्रैक कर सकेंगे। केवल इतना ही नहीं, जब वे हमारी समुद्री सीमा लांघेंगे तो इस ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से एक सायरन बजेगा, जो उन्हें पूर्व चेतावनी दे देगा कि अब आप भारतीय सीमा को लांघ कर श्रीलंका के वाटर्स में जा रहे हैं और वहां मत जाइए। यह एक अलार्म का काम करेगा, जो उन्हें अपनी सीमा में रोक लेगा और श्रीलंका की सीमा में उनके जाने से पहले उन्हें चेतावनी दे देगा। मैं यह भी बता दूं कि गुजरात कोस्ट पर यह सिस्टम लगा हुआ है और यह बहुत ही अच्छे तरीके से वहां काम कर रहा है। वही सिस्टम हम यहां भी देना चाहते हैं।

जहां तक डीप-सी फीशिंग की बात है तो मुझे यहां यह कहते हुए खुशी है कि डीप-सी फीशिंग के प्रोसीज़र्स बहुत जटिल थे, बहुत ज्यादा जटिल थे। भाई राधा मोहन सिंह जी यहां बैठे हैं। इनके मंत्रालय के नीचे एनीमल हस्बैंडरी, डेयरिंग और फिशरीज़ का विभाग आता है। अभी दिनांक 12 नवम्बर को कई मीटिंग्स हुईं। मेरे लेवल पर मीटिंग हुई, पी.एम. के लेवल पर मीटिंग हुई, इनके लेवल पर मीटिंग हुई। अभी 12 नवम्बर को हमने उस पूरी प्रक्रिया को इतना सरल और इतना पारदर्शी बना दिया कि अब हमें लेटर ऑफ परमिट लेने के लिए केवल दो चीज़ें चाहिए - रजिस्ट्रेशन नम्बर, मतलब आपकी बोट रजिस्टर्ड होनी चाहिए और एक फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। बस केवल इन दो चीज़ों के बाद आपको डीप-सी वाटर फिशिंग का परमिट मिल सकता है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के पास जितने भी रजिस्ट्रेशन वगैरह के काम थे,

वह भी उन्होंने डेलिगेट करके स्टेट एजेंसीज को दे दिए। अब तमिलनाडु और पुड्डुचेरी के मछुआरे इस नयी प्रक्रिया का लाभ उठा कर डीप-सी फिशिंग पर जा सकते हैं। इसका पूरा समाधान होगा। जो मैं कह रही हूं, यह तात्कालिक समाधान है, लेकिन वह दीर्घकालिक समाधान होगा।

मैं अपने साथियों को यह भी बता दूं कि फिशरमेन के साथ मैं बार-बार मीटिंग कर रही हूं और मुझे अच्छा लगा कि मेरी पिछली मीटिंग में सारे के सारे एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स आए। सब ने कहा कि हम भी यह मानते हैं कि जो फाइनल सॉल्यूशन है, वह डीप-सी फिशिंग का है और हम उसके लिए तैयार भी हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी एक पैकेज बनाकर मुझे 45 दिनों में देंगे। अगर उनका पैकेज आ जाता है तो हम उस पैकेज को, और जिस मैमोरैण्डम की बात डॉ. के. गोपाल ने की, वह मैमोरैण्डम हमारे पास आ गया है, उसके आधार पर हम एक नयी नीति भी तैयार करेंगे। हमने डीप-सी फिशिंग की प्रक्रिया को इतना सरल और पारदर्शी बना दिया है कि हमारे मछुआरों के लिए डीप-सी फिशिंग का हमेशा-हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा, जो बात हमें रोज-रोज चिंतित करती है।

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam, I know the rules and I know that it is against the rules. But still I want to say something, on this issue.

HON. SPEAKER: I am giving you special permission.

DR. M. THAMBIDURAI : As it relates to Tamil Nadu fishermen, I want to raise certain things. Some contradiction is there in what the hon. Minister of External Affairs has said. As regards the release of fishermen who were given death sentence, our hon. Prime Minister intervened in the matter and we are thankful for that. At the same time, my leader Puratchi Thalaivi Amma put in a lot of efforts to see that they are released. Our Ministry of External Affairs also took up this matter with Sri Lanka and told them that the cases against five fishermen of T.N. are false cases. ...* Sri Lankan Government also knew that they are false cases and Mr. Rajapakshe President Sri Lanka somehow managed to give some kind of exemption. That is why, he did it.

Even though he was persuaded, yet our Embassy said that this was a false case and therefore the death sentence was not at all necessary. The President of Sri

* Not recorded.

Lanka has done this because elections are approaching in Sri Lanka and he is contesting for the third term and to get the Tamil votes he has done this. The President of Sri Lanka has not shown any sympathy for our fishermen. Legally it was not correct.

The second point is about Katchatheevu issue. Parliament is the supreme body and it has the right to discuss this matter. Therefore we cannot escape by saying that this matter is in the Supreme Court and hence we cannot discuss this issue. Katchatheevu is part and parcel of the Indian territory. My leader hon. Amma has written so many letters to the hon. Prime Minister about this. When the agreement took place it did not strictly follow the rules and regulations of the Parliament. Now, for handing over a territory to Bangladesh, the Government is proposing to bring in a Bill for seeking approval of the Parliament. When an area is being ceded to Bangladesh from the Eastern region, the Government of India proposes to bring in a Bill but I would like to know if such a Bill was brought before Parliament when Katchatheevu was ceded to Sri Lanka. That is why I am saying that still that area is part of the Indian territory. Our fishermen traditionally went for fishing in that area because fishes were available there. Knowing that well and knowing that Katchatheevu is a part of Indian territory, Sri Lanka somehow managed to get it under their control. First they agreed that our fishermen can go for fishing in that area but the present Sri Lankan President has violated all the terms of the agreement. Therefore, it is a serious issue and the Government should see that serious action in the matter is taken. That is what the people and especially, the Tamil Nadu fishermen there are demanding… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No names should be taken. किसी का नाम लेकर कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाती है।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया, मुझे जीरो ऑवर में बोलना है।

माननीय अध्यक्ष : एक विषय रह गया है, उसके बाद जीरो ऑवर होगा।

(Placed in Library, See No. LT 1068/16/14)

12.37 hrs

MOTION RE: EIGHTH REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Madam, I beg to move:

> "That this House do agree with the Eighth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 8th December, 2014 subject to modification that the recommendation regarding item at serial number 2 already disposed of by the House be omitted."

HON. SPEAKER: The question is:

> "That this House do agree with the Eighth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 8th December, 2014 subject to modification that the recommendation regarding item at serial number 2 already disposed of by the House be omitted."

The motion was adopted.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, on last Friday I wanted to raise this question but the House was not in order. We were also not present in the House because of the past incident, which I do not want to raise here, I could not raise the matter.

At present, on 2nd December, 2014, Government raised Excise Duty on petrol by Rs. 2.25 per litre and diesel by Re. 1 per litre. Oil firms decided to absorb the duty change for the time being and retail pump rates has not been increased thereby there is no impact on the consumers. The oil firms are absorbing the Excise Duty increased for now. They are keeping track of the changing scenario and will take appropriate steps as the situation warrants at the next revision.

Madam, as you know international prices of crude oil have come down from 120 US dollars to 65-70 US dollars. As per deregulation rules you have to pass on the benefits whatever is due owing to reduction of prices. So, instead of passing it on to the consumers, the Government is raising the excise duty and keeping it with them. They are going to get a benefit of nearly Rs. 15,000 crore to Rs. 16,000 crore out of this. This amount of Rs. 15,000 to Rs. 16,000 crore has to go to all the consumers who are using crude oil, petrol, diesel, etc.

एक तरफ आप डिरेगुलेशन की बात करते हैं कि जैसे इंटरनेशनल मार्केट में उनके प्राइस कम होंगे तो उनके प्राइस कम करेंगे। जब उनकी कीमत बढ़ती है तो आप उनकी कीमत बढ़ाते हैं। जब उनकी कीमत घट रही है तो आप उनकी कीमत क्यों नहीं घटा रहे हैं, यह मुझे समझ में नही आ रहा है। दूसरी चीज, दस से पन्द्रह हजार करोड़ रुपए की कोई कमी नहीं है तो आप बजट डेफिशिएट फिल-अप करने के लिए अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो कल आप हर चीज पर इनडायरेक्टली टैक्सेज लगा कर, इनडायरेक्टली एक्साइज ड्यूटी लगा कर, पैसे कलेक्ट कर अपने डेफिशिएट को पूरा करना चाहते हैं तो यह ठीक नहीं है। कंज्यूमर्स को यह पास-ऑन करना चाहिए। उनको प्रति लीटर 3 रुपया 25 पैसे टोटली बेनिफिट मिलना चाहिए, वह पास-ऑन नहीं हो रहा है।

एक और प्रचार चल रहा है कि नई सरकार के आने बाद सब चीजों के प्राइस घट गए हैं। ...(व्यवधान) जब इंटरनेशनल मार्केट में चीजों के दाम घटते हैं तो ऐटोमैटिकली यहां रिडक्शन होता ही है। ...(व्यवधान) यह भी प्रचार चला कि प्रधानमंत्री जी कई देशों में गए। ...(व्यवधान) वह अमेरीका, आस्ट्रेलिया, जापान, कई देशों में गए।...(व्यवधान) उन्होंने सारे देश के लोगों को कन्विन्स किया है, इसिलिए प्राइसेज घट गए है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Everybody will not be allowed to speak on this issue. You can associate with him, if you want. I know that your name is there in the list. You can associate with him.

… (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अगर ऐसी चीजें होती हैं तो वह ठीक नहीं है।...(व्यवधान) यह कंज्यूमर्स को जाना चाहिए।...(व्यवधान) अगर कंज्यूमर्स का पैसा कोई आयल कम्पनी लेती है तो यह ठीक नहीं है।..(व्यवधान) इस संबंध में स्पष्ट स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए।...(व्यवधान) हमें बताएं कि वे क्या करने वाले हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे, श्री बी.वी.नाईक, श्री बी.एन.चन्द्रप्पा, श्री डी.के.सुरेश, श्री आर. ध्रुवनारायण, श्री पी.करुणाकरन, श्री गौरव गोगोई, प्रो. सौगत राय, कुमारी सुष्मिता देव, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, श्री पी.के.बिजू और श्री जोस के. मणि को श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I have allowed him to speak in the 'Zero Hour'. Whosoever wants to associate with him, they can give their names.

… (*Interruptions*)

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): अध्यक्ष महोदया ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप चर्चा के लिए नोटिस दे दें तो में एलाउ करूंगी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एसोशिएट करें। जब आप चर्चा के लिए नोटिस देंगे तो उस समय हम सोचेंगे।

…(व्यवधान)

श्री एस.एस.अहलुवालिया : अध्यक्ष महोदया, मैं पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग लोक सभा से निर्वाचित हो कर आया हूं। मैं इस सदन में एक गंभीर मसला उठाना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam Speaker, I am on a point of order … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, जीरो अवर में प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको मैंने एसोशिएट करने का अवसर दिया है। अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। I am sorry, everybody cannot speak.

…(व्यवधान)

श्री एस.एस.अहलुवालिया : महोदया, पश्चिम बंगाल के हरेक मंच पर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नाम पर ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई चर्चा होगी तो मैं आपको बोलने का अवसर दे दूंगी। मैंने आपको बोलने का अवसर दे दिया है लेकिन सबको यह अवसर नहीं मिल सकता है।

…(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : His voice should be heard, Madam.… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह कोई डिसकशन नहीं है।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : कृपया इनकी बात दो मिनट में सुन लें। ...(व्यवधान) अब तक आप इनकी बात सुन लेतीं तो यह खत्म हो गया होता।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam Speaker, I am on a different point. I fully endorse and associate the views expressed by hon. Kharge Ji but I am raising a point of order also in this respect. Or it may be a point of clarification.

The point is, two notifications have issued. One was issued on 12th November, 2014 and another one was issued on 2nd December, 2014. Madam, you may kindly peruse the record.

The first notification which has not been laid before this House and increasing the excise duty, without getting the knowledge and concurrence of Parliament, taking the Parliament for granted, it is not fair as far as rules and procedures are concerned. … (*Interruptions*)

Secondly, this enhancement of excise duty is under Section 5(a) of the Central Excise Act. Section 5(a) is for exemption or reducing the duty but the Government is deliberately using Section 5(a) so as to enhance the duty but limiting within 14 per cent. It has to be enhanced under Section 3 of the Central Excise Tariff Act, 1985. For this, I am seeking a clarification from the Government. Without submitting and placing the notification before the House, two consecutive notifications, enhancing the excise duty, have been issued. This benefit has to go to the consumers. Unfortunately, this has not been done. Parliament is being taken for granted. It is the right of the Members and Parliament to know as to why it is being enhanced and what is there in notification. I am seeking clarification on these from the Government. … (*Interruptions*)

12.43 hrs

SUBMISSION BY MEMBER

Re : Derogatory remarks made by a Member during a public rally in Kolkata

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): महोदया, जैसे मैंने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल का सांसद हूं। पश्चिम बंगाल में आए दिन विभिन्न मंचों पर वर्तमान प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नाम पर और पूर्व प्रधान मंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर वहां के सत्ता पक्ष के सांसद अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ सांसद यह प्रोत्साहन पाते हुए अपने नेतृत्व से यदा-कदा जहां पर भी, अभी परसों भी एक रैली को ऐड्रैस करते हुए ये सांसद जो अभी सदन में उपस्थित हैं, इन्होंने वहां उनके परिवार के नाम पर और वर्तमान प्रधान मंत्री जी के नाम पर अश्लील भाषा का प्रयोग किया। इस परम्परा को बंद करने की जरूरत है। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि वहां के सत्ता पक्ष तृणमूल कांग्रेस के सांसद सदन से और सदन के माध्यम से देश से माफी मांगें अन्यथा सदन से एक प्रस्ताव पास किया जाए कि किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वर्तमान प्रधान मंत्री के नाम पर या भूतपूर्व प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर विभिन्न तरह की अश्लील भाषाओं का प्रयोग वहां जिस तरह सरेआम सड़कों, चौराहों और मंचों पर किया जा रहा है, हम वर्तमान सरकार के युवा समाज और आने वाली पुश्तों को क्या देना चाहते हैं कि 'जय जवान जय किसान' के द्योतक लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर यदा-कदा कोई भी उठकर कुछ भी बोलता है और यह बर्दाश्त किया जाएगा। राष्ट्र इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।

महोदया, मेरी आपके माध्यम से मांग है कि जिस सांसद ने परसों कोलकाता में यह बात कही, वह सदन और सदन के माध्यम से देश से माफी मांगें अन्यथा उनके खिलाफ इस सदन में निन्दा प्रस्ताव लाने की जरूरत है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No clarification.

… (*Interruptions*)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : महोदया, मैं इस बारे में एसोसिएट करना चाहूंगा। यह बहुत गंभीर मामला है। इस सदन की परम्परा रही है कि जब भी किसी सदस्य का कंडक्ट, मिसकंडक्ट unbecoming of a Member of Parliament होता है तो या तो स्पीकर की तरफ से इसे रैपरिमैंड किया जाता है या सदन के नेता या संसदीय कार्य मंत्री एक प्रस्ताव लाते हैं। अगर यह लंबित रहता है तो दुस्साहस बढ़ जाता है।

पहले लोग किसी के नाम पर या बाप के नाम पर या फिर नाना-दादी के नाम पर कहना शुरू कर देते हैं। आखिर इससे पूरे सदन की मर्यादा धूमिल होती है। हमारे मंत्री महोदय कभी-कभी भाषण में रैफर कर देते हैं कि ...* ने ऐसा किया, सीपीएम के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार की बात कही। हमने आपको चिट्ठी लिखी, लेकिन वह आज तक लंबित है। आपको साहस करके इस विषय में सदन में फैसला लेना पड़ेगा तभी ऐसे दुस्साहस को रोक पाएंगे। नहीं तो हम सबका चेहरा बिगड़ जाएगा कि हम ऐसे लोगों के साथ इस सदन में हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस बारे में हर सदस्य नहीं बोलेगा। आप लोग सहयोगी बन जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसे नहीं बोलना चाहिए लेकिन यह बार-बार हो रहा है।

...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : महोदया, मेरी आपके माध्यम से पूरे सदन और कन्सर्न्ड सदस्य से विनती है कि वर्तमान प्रधान मंत्री जी के बारे में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, कहा गया --- "In 2019 people would slap Modi and send him to a jail in Gandhi Nagar, from where he would never be able to come out"..... (*Interruptions*) यह गंभीर मामला है। एक देश का प्रधान मंत्री और इतना लोकप्रिय प्रधान मंत्री, पूरे देश और विदेश में उनकी प्रशंसा हो रही है। किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग करना गलत है, आपत्तिजनक है, दूसरा पूर्व प्रधानमंत्री जिनको हम सब लोग इतना आदर करते हैं, जिन्होंने जय जवान, जय किसान का नारा दिया, उस समय उन्होंने एक आदर्श प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, If Lal Bahadur Shastri was alive, and knew he had a grandson like him, then, he would have never married. This man has never participated in any political movement, and has come this far, riding..... I am not here to score political points against anybody or trying to corner any particular party. It would be better in the interest of that Party, and that hon. Member to rise, and express unconditional apology so that the image and prestige of the House will go up. मुझे सलीम भाई बता रहे थे, कुछ साहस दिखाएं, साहस दिखाना, प्रस्ताव लाना और प्रस्ताव पारित करके किसी को बाहर करना यह बहुत आसान है, मैं कर सकता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि वह संसद

* Not recorded.

सदस्य और अन्य लोग जो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अपना पश्चाताप् व्यक्त करें, तो एक अच्छा प्रिसिडेंट होगा और हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो बाद में तय करेंगे कि आगे क्या करना है, यह स्वस्थ्य परंपरा होगी। मैं आपके द्वारा श्री कल्याण बनर्जी को जिनके नाम पर यह सब वक्तव्य अखबारों में आया, एक नहीं, दो नहीं, तीन बार आया, वह इसको स्वीकार करके पश्चाताप करें तो अच्छा होगा और देशवासी भी खुश हो जाएंगे और बंगाल वाले भी खुश हो जाएंगे। बंगाल में एक परंपरा है We always used to respect all the traditions and culture of Bengal, which are very great. Keeping that in mind, I would appeal to the Member, Shri Kalyan Banerjee to understand the sentiments of the people and also the House, and please express regrets so that we can leave this matter, and move forward.

माननीय अध्यक्ष : इस पर चर्चा क्यों कराते हों, यह कोई अच्छा विषय थोड़े है, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप क्यों बोल रहे हों, यह आपके ऊपर थोड़े आरोप है आप क्यों बोलोगे प्लीज।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: What statement?

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I am referring to the statement made by the Parliamentary Affairs Minister. … (*Interruptions*) Please Madam, give me two minutes. He mentioned the Member by name.

HON. SPEAKER: No, he has not mentioned the Member by name.

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY : Shri Venkaiah Naidu mentioned the name of Shri Kalyan Banerjee. He has mentioned Shri Kalyan Banerjee's name. It is the custom of this House that if you want to make any allegation against the Member, then you have to give the Member previous notice. This House has been exercised over the comments made by the Sadhvi Niranjan Jyoti.. … (*Interruptions*) We have resolved that problem. … (*Interruptions*) He has not given any notice to Shri Kalyan Banerjee and above a statement,

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोसिजर फॉलो करूं, मैं प्रोसिजर फॉलो करूंगा, नोटिस दूंगा, फिर प्रस्ताव लाऊंगा, क्या आप इसके लिए तैयार हैं, मैं वह करना नहीं चाहता,...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : I am not allowing all this.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठिए सौगत राय जी, यह कोई नियम से कुछ नहीं है और किसी के खिलाफ कोई निंदा प्रस्ताव भी नहीं आया है। बैठिए उन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरा आप सबसे इतना ही निवेदन है कि पश्चाताप करना कोई आर्डर से बात नहीं होती। किसी को आर्डर देने से पश्चाताप नहीं हो सकता या किसी को मैं यहां से बोलूं कि आप पश्चाताप करो, ऐसा भी नहीं होता है। मेरा आप सबसे इतना ही निवेदन है कि आजकल यह पद्धति बहुत ज्यादा चल रही है। पार्लियामैंट मैम्बर्स यहां बोलें या बाहर कहीं इससे ज्यादा बोला जाता है, हम सब अगर अपनी मर्यादा समझें, हम लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और यहां बैठकर पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं चाहूंगी कि हम सब लोग थोड़ी मर्यादा का पालन करें। अगर अपनी बातों को थोड़ा सोचकर सामने रखेंगे तो अच्छा होगा। किसी को यह कहना कि पश्चाताप करो और किसी को माफी मांगने के लिए कहो तो इसके लिए किसी से जबरदस्ती नहीं की जायेगी। अगर कोई अपने आप ही बोले कि मेरे से गलती हो गयी तो वह उनके मन के लिए भी ज्यादा ऐक्सैप्टेबल हो जाता है और सबके लिए भी हो जाता है।

...(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam Speaker, hon. Saugat Royji has taken objection and quoted Kaul & Shakdhar's Practice and Procedure Book for my taking the name of the Member. If he wants to proceed in that manner, I will definitely give notice or our Members will give notice. ... (*Interruptions*) Madam, I agree with the suggestion of Saugat Royji. Our Members will give notice and we will proceed further.

माननीय अध्यक्ष : ऐसा कुछ न हो।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि सब लोग अपने आप ही समझदार बनें तो वह देश के विकास की दृष्टि से अच्छा रहेगा।

...(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY : After the Speaker has spoken, why did you speak?... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, आपस में ऐसी चर्चा नहीं होती।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप चुप रहिए। आपने कहा कि दे देंगे, तो दे सकते हैं, लेकिन नोटिस देना, फिर किसी बात की चर्चा करना, माफी मंगवाना ठीक नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि माफी अपने आप ही मांगी जाती है। अगर अपना मन करे कि मैंने कुछ गलती की है तो फिर सुधार की तरफ जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।

...(व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): अध्यक्ष महोदया, सामान्य तौर से संसदीय कार्य मंत्री ने आग्रह किया है और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि यदि सदस्य सदन के समक्ष माफी मांग लेते हैं तो हमारी कोई कठिनाई है लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर माफी नहीं मांगते तो उनसे जबरदस्ती नहीं की जा सकती।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : सदन में वह सदस्य पूरी बात सुन रहे हैं और एक हठ के रूप में अपनी बात पर अडिग हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किसी से जबरदस्ती नहीं की जा सकती।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : इसलिए सदन में सरकार के लिए मजबूरी हो जायेगी ...(व्यवधान) उनके खिलाफ हमें प्रस्ताव लाना पड़ेगा। ...(व्यवधान) महोदया, यह हमारी मजबूरी है। ...(व्यवधान) अभी भी हम उनसे कहेंगे कि भारत के प्रधान मंत्री के प्रति उन्होंने जो उच्चारण किया है, उसके लिए वह माफी मांगे, अन्यथा हम सदन की तरफ से बाधित हो जायेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस पर जबरदस्ती थोड़े ही हो सकती है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.00 p.m.

12.58 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.03 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Three Minutes past Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, Matters Under Rule 377; Shrimati Kirron Kher.

(i) Need to allocate a coal mine for setting up of a dedicated power plant for Chandigarh

SHRIMATI KIRRON KHER (CHANDIGARH): Hon. Deputy Speaker, the Union Territory of Chandigarh has no power generation of its own. Currently, the power availability from firm share and unallocated quota from Central Generating Stations is about 200-270 MW. But the demand is ever increasing. In peak summers, it goes up to 275 to 350 MW, and the Chandigarh Administration is buying power from the open market to meet the demand supply gap. Per capita consumption of power in Chandigarh is also expected to increase.

To fulful the demand of the domestic and commercial sectors, Chandigarh needs to have its own power generation system. The Government of India must allocate a Coal Mine to Chandigarh, so that the UT Administration can set up a captive power plant of about 330 MW at Pithead. I request the Government to make the allocation through competitive bidding, so that the people of Chandigarh don’t have to face power outages in future.

(ii) Need to set up parking fee collection cabin within the Parking Area of vehicles at Ahmedabad Airport

श्री डी.एस.राठौड़ (साबरकांठा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अहमदाबाद एयरपोर्ट (घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय) के परिसर में यात्री आने और जाने के समय अपने निजी वाहन का उपयोग करते हैं। यहां दोनों जगह 'पे पार्किंग' (मूल्य भुगतान) होता है। इसके लिए पार्किंग एरिया में 'फी कलेक्शन केबिन' की व्यवस्था होती थी (एंट्री एवं एक्सिट स्थल)। कुछ समय पूर्व दोनों जगह पार्किंग के लिए नए कांट्रेक्ट दिए गए हैं। पार्किंग कॉन्ट्रक्टर द्वारा इस बार वास्तविक पार्किंग जगह से करीब एक किलोमीटर आगे अर्थात 'की एयरपोर्ट' एंट्री पर पार्किंग केबिन रास्ते में लगाए गए हैं और 15 मिनट अवधि में बाहर जाने का समय दिया गया है जिसकी वजह से यात्रियों को बड़ी असुविधा रहती है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट में वाहनों की पार्किंग एरिया में ही वाहन चालकों की सुविधानुसार पार्किंग शुल्क कलैक्शन केबिन स्थापित किए जाएं।

(iii) Need to run Garib Rath Express (Train No. 12211/12212) between Delhi and Muzaffarpur (Bihar) daily and also provide a stoppage of the train at Bagaha in Bihar

श्री सतीश चंद्र दुबे (वाल्मीकि नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र वाल्मीकिनगर (बिहार) का एक लोक महत्व का विषय संसद के समक्ष रखना चाहता हूँ। ट्रेन संख्या 12211/12212 गरीब रथ एक्सप्रेस आनन्द विहार (दिल्ली) से चलकर मुज़फ्फरपुर जाती है। यह सप्ताह में सिर्फ एक दिन चलती है। इस क्षेत्र के रेल यात्रियों की संख्या अत्यधिक होने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः इस ट्रेन के फेरे बढ़ाकर इसे प्रतिदिन चलाये जाने की आवश्यकता है ताकि जनता को लाभ मिल सके तथा मेरा एक आग्रह यह है कि उक्त रेलगाड़ी बगहा स्टेशन पर नहीं रुकने के कारण यहाँ के यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त ट्रेन को बगहा स्टेशन पर ठहराव की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

(iv) Need to run Amritsar Express (Train No. 11057/11058) from Dadar, Mumbai

श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगाँव) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने आम जनता और महाराष्ट्र के जनप्रतिनिधियों के अनुरोधों के बाद भी आम जनता को जोड़कर रखने वाली रेल अमृतसर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 11057/11058 जो दादर रेलवे स्टेशन से निकलकर अमृतसर जाती थी, उसे अभी लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन से निकालने का निर्णय लिया है। इसका पिछले कई दिनों से जनता लगातार विरोध कर रही है। इस संबंध में सरकार को काफी पत्राचार किया गया परन्तु सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया।

हमने जनहित में मांग की थी कि इस महत्वपूर्ण रेलगाड़ी को लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन से नहीं चलाया जाए क्योंकि आम जनता हो या जनप्रतिनिधि हो अथवा सरकारी अधिकार, सभी इसी रेलगाड़ी से सफर करते हैं। यह रेलगाड़ी नियमित समय पर रहने के साथ-साथ मुम्बई का केन्द्र बिन्दु कहे जाने वाले दादर रेलवे स्टेशन से गुजरती है। इस रेलगाड़ी से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के गरीब किसान तथा मजदूर रोजी-रोटी की तलाश में मुम्बई शहर में आते हैं जो इस गाड़ी से यात्रा करते हैं। यहाँ से चलने से इन यात्रियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उनका व्यवसाय ठप्प हो गया है। प्रतिदिन लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन से दादर या मुम्बई स्टेशन आने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जब रात को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के गरीब किसान और मजदूर लोगों को गाड़ी पकड़ने में लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ियों में भीड़ होने के कारण दादर स्टेशन पहुंचने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और मुम्बई या दादर से इस समय को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के छोटे-छोटे गांवों को जोड़ने वाली कोई भी गाड़ी उपलब्ध नहीं है। इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए लगातार इस विषय को उठाते रहे हैं।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस ट्रेन को लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन से हटाकर दादर या मुम्बई सेन्ट्रल स्टेशन से शुरू किया जाए।

(v) Need to enhance the rate of honorarium to Accredited Social Health Activists engaged under the National Rural Health Mission.

श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आशा बहू एक घरेलू सामाजिक महिला है। एन.आर.एच.एम. कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक 500 की न्यूनतम आबादी पर एक आशा का चयन किया जाता है। इनका कार्य समाज के बच्चों तथा महिलाओं को विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराना, टीकाकरण, आयरन की गोलियाँ वितरित करना, मोतियाबिन्द का ऑपरेशन, प्रसव आदि में सहयोग करना तथा ऐसे कार्य जो घरेलू महिलाओं के स्वास्थ्य सेवा के साथ-साथ सामाजिक रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाते हैं, से जुड़ा है। इनके बदले में उनका पारिश्रमिक कार्य के अनुसार काफी कम 50, 100 अथवा 200 रुपये है। इस कारण इनका मनोबल कम हो जाता है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आशाओं को एक निश्चित मानदेय देने हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं ताकि इनका उत्साह, आत्मविश्वास एवं मनोबल बना रहे।

(vi) Need to provide relief and compensation to farmers whose land has been utilized for fencing the border in Rajasthan, particularly in Barmer Parliamentary Constituency

COL. SONARAM CHOUDHARY (BARMER): Mr. Deputy-Speaker, Sir, after India-Pakistan partition following freedom of the country, the boundary was demarcated by erecting pillars. Therefore, in the year 1994-95 onwards, keeping in view, the security considerations, the Government of India installed barbed wire fencing at a distance of 150 yards, e.g., 450 feet away from the pillars on the Indian border. After the partition in the year 1947 and till the fencing in the year 1994-95, the concerned land owner peasants were cultivating their lands. As per the need of land for fencing, the Ministry of Defence, Government of India and Revenue Department acquired the requisite land. The peasants of Jammu and Kashmir, Punjab, Haryana, Ganganagar, Hanumangarh in Rajasthan, who were vigilant and literate, were able to get the right of passage at a distance of every three to four kilometers for cultivating their lands with the permission of the Army and the Administration. However the peasants of Bikaner, Jaisalmer and Barmer districts who were illiterate, did not take any initiative to get the right to cultivate their ancestral lands.

When the farmers became alive to their hardships, they approached all concerned in the State Government, Home Ministry of the Government of India, BSF, etc., through letters as well as personal meetings but unfortunately, they did not get justice. In this connection, I would especially draw your kind attention to several families, whose entire ancestral lands have been utilized for fencing. Having failed to get justice, at last, after 20 years, 10 peasants approached the hon. High Court. While terming the demand of the farmers as justifiable, it gave its judgment on 28.01.2013 stating that the Home Ministry of the Government of India, Revenue Department of Rajasthan Government and BSF to take decision on the demand of the farmers within two months. However even after the lapse of

about two years, no action has been taken in this regard. The peasants also protested during this period.

Sir, I submit the demands of those peasants whose lands fall between the pillars and the fencing as under:

(a) They should be provided passage/gates at a distance of one kilometer each to cultivate their lands like the permission granted to the farmers of Hanumangarh and Ganganagar; or

(b) They should be given alternative land in the same revenue village/nearer village; or

(c) They should be given compensation on market rate.

Sir, therefore, I urge upon the hon. Prime Minister through your good offices to allow the affected farmers to cultivate their lands who have been deprived of their sole source of income for the last 20 years.

Thank you.

(vii) Need to expedite payment of arrears of wages of labourers engaged in the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in Madhya Pradesh

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) में काम करने वाले लाखों मजदूरों का भुगतान लगभग आठ महीनों से लम्बित पड़ा है। इनमें से ज्यादातर एस.सी., एस.टी. तथा ओ.बी.सी. वर्ग के हैं और मजदूरी भुगतान के लिए पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि मध्य प्रदेश में मनरेगा में काम करने वाले लाखों मजदूरों के लम्बित पड़े मजदूरी भुगतान को शीघ्र करवाने के लिए आदेश देने की कृपा करें।

(viii) Need to restore the land of widows, military personnel and people belonging to weaker section allotted to them in Delhi under 20-Point Programme

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Scheduled Castes, widows, OBCs, military personnel and poor people were allotted land for housing and agricultural purposes under 20-Point Progremame in NCT of Delhi U/S 74(4) of D.L.R. Act, 1954 in the year 1970 and 1976. They have been deprived of their legitimate rights of Bhumidhari for the last 38 years. To make it specific, a case in point is that between 1987 and 1989, 27 people of Daryapur Kalan, Delhi – 39, were allotted land for housing from Khasra No. 63 (1/2) but they were deprived of the land; and in 1996, the land was used for construction of a park. These beneficiaries have all relevant documents like map and other papers and yet their grievances have not been redressed; and the authorities are trying to falsify their claim.

(ix) Need to provide adequate compensation for injury and loss of human lives as well as damage to crops by wild animals in Kheri Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित है जिसके आसपास (लखीमपुर, खीरी) गांव बसे हैं तथा जंगल से लगी जमीन पर हजारों एकड़ भूमि पर कृषि होती है।

हाथियों आदि जंगली जानवरों द्वारा फसलों का जो नुकसान तथा जनहानि होती है उसके लिए वन विभाग द्वारा गन्ना की फसल पर 3000 रुपये प्रति एकड़, धान, गेहूं, तिलहन पर 2500 रुपये प्रति एकड़ तथा अन्य समस्त फसलों पर 1200 रुपये प्रति एकड़ एवं जंगली जानवरों द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु पर मात्र एक लाख रुपये, गंभीर घायल को 20,000 रुपये, साधारण घायल को 10,000 रुपये तथा जानवरों के मरने पर मात्र 2500 रुपये प्रति जानवर दिया जाता है, जो बेहद कम है।

किसानों की फसलों व जानमाल की सुरक्षा हेतु, पूर्व में जंगल के किनारे 2 मीटर चौड़ी व 3 मीटर गहरी खाई खोदी जाती थी, जिससे जंगली जानवर जंगल से बाहर नहीं आ पाते थे, परन्तु अब यह कार्य व्यवहार में नहीं लिया जाता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि गन्ना की फसल नुकसान पर 30,000 रुपये प्रति एकड़, धान, गेहूं व तिलहन पर 25,000 रुपये प्रति एकड़ तथा अन्य फसलों पर 20,000 रुपये प्रति एकड़ की तथा मानव मृत्यु पर 20 लाख रुपये, गंभीर घायल को 5 लाख रुपये, घायल को 1 लाख रुपये तथा जानवरों की मृत्यु पर बाजार कीमत के अनुसार मुआवजा दिया जाये तथा जंगल के सीमावर्ती क्षेत्र में 2 मीटर चौड़ी, 3 मीटर गहरी खाई खुदाई जाये, जिससे लोगों के जान-माल व फसलों की रक्षा हो सके तथा नुकसान की स्थिति में प्रभावी क्षतिपूर्ति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Ramesh Bidhuri – Not present.

(x) Need to accelerate the pace of construction of broad gauge railway line from Macherla to Nalgonda

SHRI GUTHA SUKENDER REDDY (NALGONDA): I would like to draw the kind attention of this august House to a matter regarding the dire need to complete the new railway broad gauge line from Macherla to Nalgonda having a stretch of more than 80 kilometres, which pertains to my Nalgonda Parliamentary Constituency in Telangana. The project cost amounts to Rs.481 crore.

This new railway line project has been pending since 1997-98 and less funds were allotted to complete this project, that is, Rs.1 lakh every year, which leads to slow pace of work. It would not be out of place to mention that the detailed estimate was sanctioned by the Railway Board and also notified as Special Railway Project two years back within the ambit of the Railways (Amendment) Act, 2008. The then hon. Minister of State for Railways also inspected the project on 30.3.2012 accompanied by railway officials and he also said that Rs.410 crore was allotted for this purpose by the Centre. During the last year and in the current year, Rs.5 crore each was released. A portion of land is available for this project and tenders should be called for without further delay. Even though there is a huge demand from the local people since long, this project has been neglected and also running at a snail's pace for the reasons not known to me. If this line is executed, the Railways would generate additional revenue.

In view of the demand of the local public for train connectivity, I request the hon. Minister of Railways to complete this new railway line immediately.

(xi) Need to implement the One Rank, One Pension scheme for ex-servicemen

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): The One Rank One Pension (OROP) Scheme for the ex-servicemen of our country was approved by the UPA Government in February 2014. This scheme has widespread support from all political parties including from our Prime Minister, who has repeatedly promised to implement this scheme. Yet this One Rank One Pension Scheme is yet to be implemented, despite nine months having passed since it was announced in February. I am told that one of the sticking issues remains the 'exact definition of OROP'. In February, while announcing the scheme, the UPA Government had accepted the Koshiyari Committee's recommendation on the definition of OROP. The Koshiyari committee, which was a Petition Committee of Rajya Sabha, had members from all parties. It had unanimously agreed on the definition of OROP, which was then accepted by the UPA. To implement this definition around Rs. 9,500 crores allocation was estimated. But now it seems that some Government bureaucrats are trying to change the definition of OROP itself, causing grave concern amongst 32 Lakh ex-servicemen awaiting the implementation of this scheme. The ex-servicemen fear that it was due to this bureaucratic hurdle that the present Government provided only Rs. 1000 crore as budgetary allocation in the final Budget under the scheme for the whole year as against over Rs. 9000 crores estimated as per Koshiyari Committee definition of OROP. The Government must clarify its stand at the earliest and must not delay in implementing the OROP Scheme in the name of either falling into a bureaucratic trap or wanting to maintain the fiscal deficit target of 4.1% of the GDP. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Let the Matter under Rule 377 be finished. Only two-three persons are left.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): I want to say that instead of only raising and leaving this issue here, it is better you have Half an Hour Discussion for this.… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You can give notice in this regard.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Around 32 lakh soldiers are concerned about this. A notice is already given. … (*Interruptions*) Some time should be fixed for it. It is important that some response should come from the Government.… (*Interruptions*)

(xii) Need to continue National Agriculture Insurance Scheme beyond the Financial Year 2014-15

SHRI G. HARI (ARAKKONAM): Agriculture is the mainstay of our economy and Tamil Nadu goes about in a big way as it has got traditional cultivation methods since time immemorial. The Government of Tamil Nadu takes keen interest in promoting agricultural production and ensuring protection to farmers affected by various factors. As far as the Centre is concerned, crop Insurance is the only protection made available to crores of our farmers. Under this scheme, both the Governments, Centre and States, are paying the insurance premium so far either fully or partly. As far as Tamil Nadu is concerned, our hon. Chief Minister is in favour of taking the burden of premium payment by the State Government itself. The hon. chief Minister of Tamil Nadu had also written to the Union Government that National Agriculture Insurance Scheme (NAIS) must be continued and it was approved by the Union Government for 2014-15. Now contrary to it, Union Agriculture Ministry has indicated that a new Crop Insurance Programme based on crop yield and income would be rolled out shortly. I urge upon the Union Government that the Government of Tamil Nadu may be permitted to continue with the implementation of NAIS during next year also on the existing pattern of sharing premium subsidy and compensation.

(xiii) Need to provide separate fund for Saansad Adarsh Gram Yojana

SHRI V. ELUMALAI (ARANI): Hon. Prime Minister has recently announced 'Saansad Adarsh Gram Yojana' as an integrated development programme to be taken up by the Members of Parliament adopting a village in their respective constituencies.

Union Government may note that a similar scheme is being implemented in Tamil Nadu as envisioned by our hon. Chief Minister, right from 2011 as 'Tamil Nadu Village Habitation Improvement (THAI)' scheme. This flagship programme is aimed at providing minimum basic infrastructure.

For implementing this scheme, Rs. 680 crores was spent in 2011-12 to benefit 25,335 habitations in 2020 villages. It was 750 crores in 2012-2013 to benefit 2,250 villages and a similar sum in 2013-2014 to benefit 2,500 villages. Now, the hon. Prime Minister wants the Members of Parliament to take up this adoption programme from the MPLADS funds.

It is needless to say that MPLADS funds need to be spent on various development works for the entire constituency, and the amount allocated for the purpose needs to be enhanced. While this being the ground reality, expecting MPs to adopt villages to develop them as model villages without separate fund allocation will be difficult. Hence, I would urge upon the Union Government to provide extra funds to carry out this ambitious programme, which is being taken up by the Government of Tamil Nadu in a big way.

(xiv) Need to provide adequate funds under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, particularly, in West Bengal

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) is a demand-driven, but instead of responding to rural demands for work, the Union Government wants to make it allocation based. As opposed to a demand for Rs. 60,000 crores for implementing MGNREGS in 2008, the UPA Government allotted Rs. 40,000 crores, which it reduced to Rs. 33,000 crores in 2010. The Union Government propose to further restrict who gets work and where by restricting it to only 200 districts. They propose to change the labour and material ratio from 60:40 currently to 51:49, which will cut funds for wages.

In response to an RTI, we have got the information that the Central Government has denied MGNREGS funds to Bihar, Chhattisgarh, West Bengal despite demand for work under MGNREGS. Secretary, Rural Development, Bihar had written to Ministry of Rural Development in August saying that the State had received Rs. 256.4 crores against the State's request for release of Rs. 1,082.4 crores. Earlier this year, in March, West Bengal Minister had written to the Ministry pointing out that though West Bengal had achieved, over 11 crore person days between January and March, the State received Rs. 2,394 crores instead of its request for Rs. 3,838 crores.

I, therefore, urge the Government to take remedial steps in this regard. Earlier this week, rights groups at a gathering of 15,000 people have demonstrated in the capital. They demanded that the rights earned under Food Security Act, Forest Rights Act and MGNREGA should be preserved. The Central Government should take note of this.

(xv) Need to allot land for construction of the building for Paradip Marine Police Station in Paradip Port, Odisha

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): Sir, after completion of the first phase of the Coastal Security Scheme, the second phase was started from April 2011. In the first phase, the Ministry of Home Affairs of the Union Government had sanctioned five Marine Police Stations for Odisha including one in Paradip. I would like to mention that all the Marine Police Stations except Paradip were made operational in their own State Government buildings. But Paradip Marine Police Station has been functioning in the accommodation provided by Paradip Port Trust Authority on rent. In this regard, the State Government had requested Paradip Port Authority to handover one acre of port land to the State Government for construction of the building in respect of Paradip Marine Police Station. The Board of Trustees of Paradip Port Trust, keeping in view the requirement of the State Government, decided to allot the land of Paradip Port in favour of the Home Department (Police), Odisha at a concessional rate of 25 per cent of the cost. However, the decision of the Central Government is still awaited.

Hence, I urge upon the Ministry of Shipping to kindly look into the matter and expedite allotment of one acre of land of Paradip Port for construction of the building of Paradip Marine Police Station in order to strengthen the marine security along the seacoast of Odisha.

(xvi) Need to improve BSNL mobile service and fill up the vacant post of General Manager in Parbhani and Jalna districts of Maharashtra

श्री संजय हरिभाऊ जाधव (परभणी) : महोदय, महाराष्ट्र के परभणी और जालना जिलों में बी.एस.एन.एल. की मोबाइल सेवाएं पिछले कई वर्षों से ग्रामीणों तक सुचारू ढंग से नहीं चल रही हैं। उक्त जिलों में टावरों की कमी के कारण मोबाइल सेवाएं सही नहीं चल रही हैं। मोबाइल ग्राहकों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ टावरों का विस्तारीकरण करने की जिलों में अत्यन्त आवश्यकता है। बी.एस.एन.एल. के कार्यालयों में महाप्रबंधक के पद रिक्त हैं तथा अन्य कर्मचारियों की कमी तथा प्रबंधक व्यवस्था की कमी के कारण ग्राहकों की शिकायतों का निवारण भी नहीं किया जा रहा है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि उक्त जिलों में शीघ्र महाप्रबंधक के रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएं तथा नए मोबाइल टावरों की स्थापना की जाए जिससे उक्त जिलों की मोबाइल सेवाएं सुचारू ढंग से कार्य कर सकें।

(xvii) Need to start operation of flights from Kolhapur Airport in Maharashtra

श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर): महोदय, मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि वह कोल्हापुर एयरपोर्ट, महाराष्ट्र में हवाई सेवाएं शुरू करने की दिशा में आवश्यक एवं शीघ्र कदम उठाएं।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Member, the approved text only will go on record and there are only two lines in the approved text. You are reading some other things, but you cannot say anything more than what is in the approved text.

(xviii) Need to take urgent steps to start the ESI Medical College at Parippally in Kollam, Kerala

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, ESI Corporation invested about Rs. 500 crore for infrastructure development of ESI Medical College at Parippally in Kollam, Kerala. MCI conducted inspection for the academic year 2014-15 and found certain deficiencies. The deficiencies are the non-appointment of teaching and non-teaching staff and infrastructure development of departments essential for 1st year MBBS course as per norms. November-December is the time for inspection by MCI for 2015-16. No effective steps have been taken by the ESI Corporation to rectify the deficiencies. If the deficiencies are not rectified before the inspection of MCI, the admission during the next academic year is also not possible. There will be delay in availing of the opportunity by ESI beneficiaries in terms of better treatment and medical education of their children. The huge amount spent on this will not serve any purpose.

Hence, I would urge upon the Government to initiate urgent action to rectify the defects and start the ESI Medical College at Parippally in Kollam, Kerala immediately.

(xix) Need to permit rearing of milch animals in Delhi

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, सन् 1970 के बाद भारतीय डेयरी विकास निगम द्वारा "श्वेत क्रांतिं की ऐतिहासिक सफलता के बाद दूध के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। परन्तु दुर्भाग्य से हमारी दूध पर आत्मनिर्भरता और दूध की भारी वृद्धि के बावजूद सिंथेटिक दूध का अवैध उत्पादन बढ़ता चला गया व लगातार जारी है। डेयरी उद्योग भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। चिकित्सकों के अनुसार सिंथेटिक दूध के उपयोग से लीवर, गुर्दे और आँखों में सूजन हो सकती है। यह दूध एक मीठा जहर है, जो धीरे-धीरे शरीर को बीमारियों के लिए उपजाऊ बनाता है तथा यह दूध हृदय रोगियों और गर्भवती महिलाओं के लिए और भी खतरनाक है। दिल्ली की अधिकांश आबादी (लगभग 85 प्रतिशत) को शुद्ध पौष्टिक दूध उपलब्ध नहीं हो पाता है। गाय के दूध में विटामिन "ऐं है, जो शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसी प्रकार भैंस के दूध में मट्ठा प्रोटीन होता है, जो कि विकृतीकरण गर्मी के लिए प्रतिरोधी है। आज राजधानी दिल्ली में गाय-भैंस पालना दुश्वार हो गया है। दिल्ली में आपको कुत्ते, बिल्ली पालने की इजाजत तो है, लेकिन आप दुधारू मवेशी नहीं पाल सकते हैं। दिल्ली के सरकारी विभागों, वेटरनिटी विभाग के लोग आवारा जानवरों को तो पकड़ते नहीं, लेकिन गाय व भैंसों को लोगों के घरों व उनकी जमीनों से खोलकर ले जाते हैं। आज एक भैंस की कीमत 1 से डेढ़ लाख रूपए है, जो बहुत से परिवारों के भरण-पोषण का स्रोत भी है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि राजधानी दिल्ली के लिए एक अध्यादेश लाकर नागरिकों को एन.डी.एम.सी. क्षेत्र से बाहर यह अधिकार दिए जाएं, जिसमें 100 गज व उससे ज्यादा जमीन रखने वाले व्यक्ति को एक गाय व भैंस पालने की इजाजत हो ताकि अधिक से अधिक आबादी तक शुद्ध व पौष्टिक दूध उपलब्ध हो सके। जिससे हम स्वस्थ भारत की ओर एक कदम और बढ़ सकें तथा बहुत से परिवारों के भरण-पोषण में मदद मिल सके।

14.37 hrs

PAYMENT AND SETTLEMENT SYSTEMS (AMENDMENT) BILL, 2014

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we will take item No. 17.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): May I raise a point of order at this stage.

HON. DEPUTY SPEAKER: No, first I will call the Minister, then you raise your point of order.

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I beg to move:

> "That the Payment and Settlement System (Amendment) Bill, 2014 be taken into consideration."

Sir, I have gone through the provisions of the Amendment and I have a written note which is ready and I could read out to explain what the amendment is about. But on the first reading, it looks like somewhat complex. But upon a simplistic explanation and I think I am going to be in hon. House in simple language to explain what this subject matter is entirely about?

Sir, the Payment and Settlement system in commercial transactions is the backbone of all financial transactions. I issue a cheque in favour of somebody. It goes through a clearing house from my banker to the recipient bankers and therefore, there is a payment and settlement system involved in this. Prior to 2007, this was all being managed through an executive notification and authorities created under that. In 2007, the Government at that time, and rightly so, enacted the Payment and Settlement Systems Act 2007. I would just read from the preamble of that Act one sentence. It will be clear as to what the purpose of that Act was.

> "An Act to provide for regulation and supervision of payment systems in India and to designate the Reserve Bank of India as the authority, for that purpose and for the matters connected therewith and incidental thereto. "

So, the payment systems are to be regulated by the Reserve Bank of India. Now, what does the Act say? The principal Act after definition say that it is only Reserve Bank and whoever has an authorization from the Reserve Bank, he can run a payment system. In a payment system, you can have two kinds of actors involved. One is a system participant. My bank will be a system participant. In a private transaction, just as for instance today, this radio taxi service controversy is going on, how does a consumer pay for these radio taxies which are currently in controversy? These are not governmental transactions or banking transactions. Earlier, the system was that he would register himself with the private taxi company and he would come on their Whatsapp. He would give his credit card number. Once he gave his credit card number, every time he wanted to hire a taxi, he would just press the Whatsapp of that taxi. They would locate where the passenger is and then they would pick him up. When he would leave the taxi, he would not pay, but it will be credited to his account. Now, a violation was discovered that the payment gateway was outside India. So, the Reserve Bank told them to bring it within India. So, from 1st December this year, it appeared in the newspapers that Paytm, a local wallet has been created by one of these companies which is in controversy. The payment is deposited in advance through a credit card or cash into that wallet. Every time you use the service, you have already paid in rupees. So that wallet becomes the service provider.

When this original Act was enacted, there is a provision that under Section 7, the Reserve Bank will permit an authorisation to any person. It could be a State agency; it could be a non-State agency. But without authorisation of the Reserve Bank, you cannot become a service provider. That is a designated authority. That is how, the commerce in this area is evolved. If you default, what are the consequences etc., the Act provides for it.

There is a provision under Section 23. Section 23 says and since Prof. Saugata Roy was raising a point of order, I could quite anticipate what he wanted to say. The amendment is very simple, though it is couched in a very complicated phraseology and unless you understand this commerce, it looks a little complicated. I myself yesterday had spent a lot of time before I could understand it simply. … (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): If we read the Objects and Reasons, we will not be able to understand it.

श्री अरुण जेटली : इसीलिए मैं सरल भाषा में समझा देता हूँ।

So far, I think, I am putting very simply. Our lady colleague and I just discussed along with Shri Deepender Singh Hooda. It took them two and a half to three minutes to follow as to what it is all about. Section 23 says: "What if the system participant…" That is, suppose, I have to give money to somebody. What happens if either the recipient or I become insolvent? Now the sanctity of commercial transaction is to be respected. So, either of us becomes insolvent under ordinary law of the land and those for whose behalf we are transacting, that is, the bank becomes insolvent. Then under the Banking Regulations Act or the Companies Act, they owe money to me. I will have to stand in a queue. The old Companies Act had a provision under Section 529. First, the taxation authorities get the money after insolvency and liquidation. Thereafter, the workmen will get the money; thereafter, the secured creditors will get the money and in the last, the unsecured creditors will come. So, they are holding my money but I will stand last in the queue. So, the original Act has a provision under Section 23. If a system participant became insolvent, then Companies Act and the Banking Regulations Act will not apply. Under this Act, you first pay to the person on whose behalf you are holding the money. If anything else is left, then that procedure for the rest of the land will apply. At the cost of repetition, I would just translate it in. अगर कोई सिस्टम पार्टिसिपैन्ट इसमें इनसॉल्वैन्ट हो जाता है, उसका दीवालिया हो जाता है तो सामान्य देश के कानून

में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में या कंपनीज़ एक्ट में पहले पैसा टैक्सेशन अथॉरिटीज़ को जाता है, फिर लेबर को जाता है, फिर सिक्योर्ड क्रैडिटर्स को जाता है और उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रैडिटर्स को जाता है। इस एक्ट में सैक्शन 23 में कहा कि यह प्रक्रिया नहीं चलेगी। जिनके बिहाफ पर आप ट्रांसैक्शन कर रहे थे, ताकि कामर्शियल ट्रांसैक्शन चलती रहे, पहले उसका पैसा उसको मिलेगा और उसके बाद जो सामान्य देश का कानून है, उसके तहत लोगों को मिलेगा।

So, the Act in 2007 envisaged this. But the Act did not envisage a situation where not the participant but what if the system provider itself becomes insolvent. If the system provider becomes insolvent, the Companies Act will apply; if the system provider is a bank, the Banking Regulation Act will apply. So, we go back to the same problem. This amendment entirely is that even if the service provider, which is the clearing house, becomes insolvent, then first pay the money to those whose money you were clearing, and if anything is left, then the rest of the procedure will apply. This is entirely the amendment in simple language.

There are some editorial corrections in the original Bill in the language of this section. And then Section 23 is being replaced with those editorial language corrections to say that the procedure of insolvency which applies to the system participants will also apply to the system provider. That is entirely the Bill.

With these few comments, Sir, I commend this Bill to this House for consideration.

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill to amend the Payment and Settlement Systems Act, 2007, be taken into consideration."

PROF. SAUGATA ROY : Sir, I am on a point or order.

HON. DEPUTY SPEAKER: Under what rule?

PROF. SAUGATA ROY : I am raising the point of order with reference to Rule 31(e)

The functions of each of the Standing Committees will be (a) to consider the Demands for Grants etc., (b) to examine such Bills pertaining to the concerned Ministries/Departments as are referred to the Committee by the Chairperson, Rajya Sabha or the Speaker as the case may be and make report thereof.

Ever since this rule has been brought in, it has been the practice in this House to refer any Bill that is important to the Standing Committee. Sometimes for small amendments, minor amendments, we overlook this clause.

HON. DEPUTY SPEAKER: The Bill was already introduced yesterday, discussion has started now, and you are also going to speak during the discussion. On referring this kind of things to the Standing Committee, yesterday also many members spoke. These issues could be raised during the discussion and not in the form of a point of order.

PROF. SAUGATA ROY : Sir, let me complete my statement and then you give whatever ruling you wish to.

All I want to mention is that I agree that this Bill was placed in the Business Advisory Committee and the Business Advisory Committee included it in the Business of the House. The name of the Bill was mentioned and two hours were allotted by the Business Advisory Committee for discussion. But what happened in the Business Advisory Committee was that a copy of the Bill was not given. So, the Business Advisory Committee members thought that it is a minor Bill and the Finance Minister wanted it to be passed. But after it was decided, the BAC Members did not realize that this is such a complicated thing.

A lawyer of Mr. Jaitley's eminence had to spend hours to understand the implications of it. How do you expect such a complicated Bill to be discussed and

passed in this House within two hours? He is introducing two new concepts – trade depositories and legal entities. My point of order is simple. There can be several motions after a Bill is placed, a Bill can be taken into consideration and it can also be referred to the Standing Committee.

HON. DEPUTY SPEAKER: Is that your point of order?

PROF. SAUGATA ROY : Sir, my suggestion is that the Bill be referred to the Standing Committee on Finance so that we can go through it thoroughly and submit a report to the House. This is a serious Bill. You also study it; it will take you hours.

HON. DEPUTY SPEAKER: It is correct that the hon. Finance Minister said that he took a lot of time. But he said it is a simple thing and that is what he explained to you. If you are not satisfied, in the discussion you can speak and the Minister will reply to your points.

Hon. Minister, do you want to say anything?

SHRI ARUN JAITLEY: Let me say that this is not a kind of Bill which has any kind of partisan character between previous Government or this Government or next Government. Because of the global financial order, in various international forums including G-20, to add to the credibility of the global financial system these negotiations started during the UPA Government and they concluded under the UPA Government. They felt that to maintain the sanctity of the financial system, the backbone of the financial system has to be strengthened. One of the gaps that they noticed in some of the countries including India is that if the central counter party, which is the service provider in this case, becomes bankrupt or insolvent, the whole transaction will collapse. Therefore, most countries are making their laws up-to-date.

It is literally a one-section amendment and the practice has been that if it is a significant amendment, it shall go to the Standing Committee; if it is a marginal amendment, and in one sentence the only amendment is that the original law

envisaged insolvency of the system participant, it did not envisage the insolvency of the service provider. As per the amendment, what applies to the insolvency of the participant will also apply to the insolvency of the service provider. Therefore, as I am saying it, initially when you read this, it does take time to understand the commercial nature of transactions in the first instance, but translated in simple language this is the entire Bill.

Therefore, we have to bring our law at par with the international community. After all this affects our credibility in the global financial system as to when payments are promised from India, there has to be some credibility of that promise itself, there has to be some legitimacy. Therefore, there is an element of urgency. I would urge the hon. Members to consider this so that the Bill can be passed right away. There are no trans-party different opinions with regard to a proposition like this.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Of course this is the amendment to the previous Bill of 2007. You are amending nearly 3 sections- Section 2, 23 and 34A. As you have explained to this House, this is also going to affect the workers' dues and also your own taxes. Government will not have first priority to recover it. These two priorities will go and the service provider will get the first priority as per your amendment.

श्री अरुण जेटली : उपाध्यक्ष जी, मैं खड़गे जी का प्रश्न समझ गया, आपका कंसर्न भी समझ गया। इसमें जो तीन सेक्शंस हैं, उसमें पहले वाले प्रोवीजन में, सेक्शन-2 में सिर्फ डेफिनिशंस का अमेंडमेंट है। इसमें केवल दो डेफिनिशंस ऐड हो रहे हैं। सेक्शन-23 जो था, उसमें पहले वाले में यह भाषा थी कि अगर कोई पार्टीसिपेन्ट इन्सॉल्वेंट होता है तो कम्पनीज एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट एप्लाई नहीं करेगा, लेकिन पहले पेमेन्ट क्रेडिटर को जाएगा। मान लीजिए कि एक बैंक है, वह पार्टीसिपेन्ट है और वह बैंकरप्ट हो जाए तो अगर मेरा पैसा उस बैंक में जमा है तो सबसे पहले मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा। अगर हम यह नहीं करेंगे तो लोग हमारे साथ फिनैंशिएल सिस्टम में ट्रांजैक्ट करने में रिलक्टेंट होंगे। अब उस सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करके इसके साथ जो परिभाषा ऐड हुई है कि अगर सिस्टम प्रोवाइडर बैंकरप्ट हो जाए तो वही प्रक्रिया फॉलो होगी। That is all.

इसके अलावा जो सेक्शन 34 है, जैसे रिजर्व बैंक ने एक क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया बनायी हुयी है, जो रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी है, जो क्लियरिंग्स करती है। अगर उसके साथ कोई तकलीफ आएगी, तो जिनके चेक्स या पेमेन्ट उसके थ्रू ट्रांजैक्ट हो रहे हैं, पहला अधिकार पेमेन्ट लेने का उनका होगा। उसके बाद फिर कंपनीज एक्ट और बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट की प्रक्रिया चलेगी।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): What is Clearing Corporation of India?

SHRI ARUN JAITLEY: It is a subsidiary of the Reserve Bank of India, through which commercial transactions take place. It is a clearing house, in a simple language. सेक्शन 34 में जो सेक्शन था कि यह एक्ट की ओवर राइडिंग कंसीड्रेशन होगी, उसको रीस्ट्रक्चर्ड लैंगुएज में ऐड किया गया।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : इतना समझाने के बजाए इसे स्टैंडिंग कमेटी को रेफर करिए। ऐटलीस्ट वहां पर विचार-विमर्श होता है, उसके बाद फिर यह आएगा। ...(व्यवधान) इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: I will give my ruling.

Hon. Members, as you are aware, referring or not referring a Bill to the Standing Committee under the Rules falls within the jurisdiction of the hon. Speaker. I may inform the House that the hon. Speaker, on a request made by the hon. Minister of Finance, and in view of the reasons cited by the Minister, has agreed to the request for not referring the Bill to the Standing Committee of Finance.

Now, Shrimati Sathyabama.

SHRIMATI V. SATHYABAMA (TIRUPPUR): Thank you, Mr. Deputy-Speaker.

At the outset, let me thank the Chair, most of all, our beloved leader, Amma and the people of my constituency, known for its global economic activity as a knitting town for having enabled me to speak on this important legislation.

In the globalized economic sense, accepting international norms has become necessary. That necessity has necessitated our Government now to propose certain amendments to the Payment and Settlement Systems Act, 2007 to increase transparency and stability of the Indian financial markets.

Based on the principles of safety, security, soundness, efficiency and accessibility, the RBI has been authorized to establish ordered growth of payment systems. Whether they are Government bodies of other countries or multi-national corporations and organizations or individual customers, their payments and receipts must be transparent and at the same time, safe and secure. In 2007-08, the global economy witnessed a meltdown and there was a huge global financial crisis which had its cascading effect on economies of many countries. Though India witnessed the negative impact a bit late, it became a great uphill task to overcome.

The ill-effects are affecting our economic growth rate even today. We cannot claim right now 'India is shining'. That is why, we are inviting foreign investors to come and 'make in India'. Such financial transactions have been reformed time and again. That is why, originally in 2007, this Act was enacted to regulate and supervise payment systems. After waking up to the reality that globalized economy has changed payment systems and mechanisms. The G-20 nations took measures to reform Over the Counter derivatives markets. This led to certain new initiatives like bringing about Trade Repositories that emerged as a new type of financial market infrastructure. These are growing in importance in the Over the Counter derivatives market.

15.00 hrs

The Reserve Bank of India has no specific legal provision to supervise the trade repositories in India. As these trade repositories are to comply with international norms, there needs to be a regulator with appropriate legal powers. India is a party to the G-20 commitment and has taken note of the global developments. So, the Reserve Bank of India has made a trade repository, the Clearing Corporation of India Limited. This was necessary because of our bad experience in facing difficulties when our banks and regulatory agencies were not able to identify the complicated business ventures. We need to establish connections between issuers and securities efficiently. This gave rise to the need for a standard uniform code. That is why the Legal Entity Identification System is brought forth as a new initiative. The G-20 countries have recognised the importance of a global identifier. This can be a key component of necessary improvement in financial data system. Now, through these amendments we want to give more powers to the Reserve Bank of India and the regulatory mechanism it may put in place as the globally compatible Legal Entity Identifier.

Clearing Corporation of India Limited has been selected by the Reserve Bank of India to act as a local operating unit to issue Legal Entity Identifier.

The amendments sought to be made in section 23 of this Act also calls for insertion of a new section 23A relating to protection of funds collected from the customers by the payment system providers. This is necessary because the participating banks have to run the risk of exposure of its other operations when the Clearing Corporation of India function take up its role as central counter party. A sound and enforceable legal basis for "netting' of bank exposures to the said Corporation is required to reduce the banks' exposure significantly.

All these amendments will provide financial protection in the event of insolvency, dissolution or winding up of a central counter party. This will also help individuals and various bodies to overcome legal difficulties in securing the

customers interests held in bank accounts in the event of insolvency or bankruptcy or prepaid instruments.

The LEI system is to be dependent on a vast computer network. I forewarn this Government that we must be beware of the computer hackers. Otherwise, country may have to face a huge financial loss as suffered by the Bank of America only recently. Even the Defence Ministries of the Governments all over the world are not free from hacking. Hence, we must ensure a viable security system while contemplating central counter party in India.

Thanking our hon. leader, Amma for enabling me to speak on this important Bill which has become necessary in the globalised economic sense, let me conclude. Thank you, Sir.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत द पेमेंट एण्ड द सेटलमेन्ट सिस्टम्स, अमैंडमेंट बिल - 2014 प्रस्तुत किया गया है, उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। माननीय मंत्री जी ने इस बिल को प्रस्तुत करने का उद्देश्य और उसमें जो अमैंडमेंट किया गया है, उसे बहुत सरल भाषा में पूरे सम्मानित सदन को समझाने का प्रयास किया है।

15.05 hrs (Shri Anandrao Adsul *in the Chair*)

अगर हम इस बिल के अमैंडमैंट्स को देखें तो साफ है कि सैक्शन 23 में जो अमैंडमैंट किया गया है, उसका खास मकसद है, खास उद्देश्य है कि protection of funds collected from the customers. जिसके द्वारा फंड जमा हो रहा है, उसे सिक्युरिटी देना, सुरक्षा देना बैंकिंग प्रणाली या किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक आवश्यकता है, वह इस बिल के माध्यम से वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। मैं उन्हें निश्चित तौर से बधाई देता हूं। जहां तक बिल के अमैंडमैंट का संबंध है, मैं समझता हूं कि उन्होंने उस पर भी रोशनी डाली है कि वर्ष 2007 और 2008 में जब रिसैशन आया, आर्थिक मंदी आई जिसके नाते जापान, यूएस के बड़े-बड़े बैंक बंद हो गए, उनमें छटनी शुरू हो गई, जिन कस्टमर्स के डिपॉज़िट थे, उनके पैसे की कोई सिक्युरिटी नहीं रह गई क्योंकि कोई लीगल प्रोविजन नहीं था। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों ने जी-20 में महसूस किया कि हमें कोई ऐसा रिफॉर्म करना चाहिए जो भारत में भविष्य में लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। आप देखेंगे कि इसीलिए सैक्शन 23 (ए) है --

> "The Reserve Bank may, in public interest or in the interest of the customers of designated payment systems or to prevent the affairs of such designated payment system from being conducted in a manner prejudicial to the interests of its customers, require system provider of such payment system to - …"

इससे साफ है कि इस बिल के लाने के पीछे उद्देश्य है कि बैंकों या फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन्स में आज जिस तरह लेन-देन हो रहा है, उसमें सुरक्षा दी जा सके, हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। यह साफ है कि अभी तक पेमैंट और सैटलमैंट दो तरह से होता था -- एक, सैंट्रलाइज़्ड सिस्टम था। उसमें रियल टाइम ग्रॉस सैटलमैंट होता था और दूसरा, नैशनल इलैक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता था। डीसैंट्रलाइज़्ड सिस्टम में इनडिवीजुअल बैंक एक-दूसरे से लेन-देन करते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं थी। वर्ष 2007 के उसमें जो सैंट्रलइज़्ड सिस्टम था, उसमें हमने नैशनल इलैक्ट्रॉनिक फंड

ट्रांसफर को रैगुलेट करने के लिए नैशनल पेमैंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाने का काम किया है। उससे उसे रैगुलेट करने में आसानी होगी और रियल टाइम ग्रॉस सैटलमैंट को आरबीआई रैगुलेट करता है। आरबीआई के पास ऐग्जीक्यूटिव आर्डर से ही अभी तक उसका रैगुलेशन था, लेकिन अब हम उसे मैनडेटरी लीगल प्रोविजन के माध्यम से लाकर कर रहे हैं जिससे उन डिपॉजिटर्स की सुरक्षा हो सके। इस दिशा में इसका प्रयास है। इसके लिए जो काम शुरू किया गया है, उसमें ओवर दी काउंटर मार्किट का है, उसमें दो अमैंडमैंट किए गए हैं - एक तो सबको पूरे ग्लोबल में लीगल ऐंटिटी आइडैंटीफिकेशन सिस्टम हो जिससे कम से कम पूरी दुनिया में पहचान हो सके। नहीं तो आज भी ऐसा होता है कि लोग एक बैंक से सौ, दो सौ करोड़ रुपये ले लेते हैं, दूसरे, तीसरे बैंक से ले लेते हैं। इसी तरह वर्ल्डवाइड होता है। आज जो ब्लैक मनी की चिन्ता कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इससे निश्चित तौर से जो बड़े बारोअर्स को जब आइडैंटीफिकेशन देंगे, बीस नम्बर का कोड देंगे तो पूरी दुनिया में एहसास होगा और इसकी जानकारी भी रहेगी कि जिस व्यक्ति को कोड दिया गया है, उसकी आइडैंटिटी क्या है और कितनी फेयरनैस है। इस दिशा में भी यह काम किया गया है।

जो क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात हुई है, यह एक तरह से ट्रेड रिपॉजिटरी के रूप में काम करेगी क्योंकि अभी तक न्यू टाइप ऑफ फाइनैंशियल मार्किट इन्फ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कोई लीगल प्रोविजन न होने के कारण आज उसमें भी एक प्रावधान किया गया है कि क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाएं। जैसे मंत्री जी ने कहा कि वह चैक या क्लीयरिंग हाउस की तरह काम करेगा। निश्चित तौर से इसकी जो शुरूआत हुई है, कुछ माननीय सदस्यों ने इस पर आपत्ति उठाई है। वे एस्क्रो अकाऊंट समझते हैं। एस्क्रो अकाऊंट में हम चाहे सेक्शन 23 की बात कर रहे हैं, सेक्शन 34 की बात कर रहे हैं, ऊपरी पेड कार्ड की बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन के लिए अगर हमने कंपनीज के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ या बैंक के साथ कुछ भी लेन-देन करते हैं इससे पूरे वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन मालूम होगी। इस तरह के जो अमेंडमेंट हुए है, जो फाइनेंनशिएल ट्रेंजेक्शन होते हैं, उसका हिसाब-किताब इस पेड-रिपोजिटरी में रखा जा सकता है। अभी तक इसका कोई हिसाब-किताब ही नहीं था, किस तरीके से रखें, अभी तक कोई क्लियरिंग कॉरपोरेशन ही नहीं था। आज पूरी दुनिया में इस तरह के लॉज अमेंड हो रहे हैं, जिससे एक पारदर्शिता आए। पारदर्शिता कैसे आएगी, पारदर्शिता के लिए एक आइडेंटिफिकेशन होगा, तो निश्चित तौर से वह ब्लैक मनी को कंट्रोल करने का भी काम करेगा। सबसे बड़ी चिंता ओवर द काऊंटरट्रांजेक्शन होते हैं, उसमें भी पारदर्शिता आएगी। जब से मोदी जी की सरकार बनी है, चाहे दुनिया का मंच हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे जी-20 का सम्मिट हो, हम निश्चित तौर से बधाई देंगे कि जी-20 में भी भारत के द्वारा उठाए गए

ब्लैक मनी को कर्ब करने का सीरियस नोट लिया गया, बल्कि पार्ट ऑफ नोट भी बनाया गया। निश्चित तौर से हमारी सरकार बधाई की पात्र है। अगर हम ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम जो चाहते हैं उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। आप जानते हैं कि बड़े-बड़े फाइनेनशियल इंस्टीटयूशंस या बैंकिंग या बारोअर द्वारा हजारों करोड़ों का लेन-देन होता है। इस बिल को लाने का मकसद यह है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट होने से निश्चित रूप से हर क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी। यह बिल न केवल कर्ब करेगा बल्कि रिफार्म भी करेगा। पूरी दुनिया में आर.बी.आई रेगुलेट करता था, अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर आप कुछ भी भेज रहे हैं, या एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन या बाहर, या बारोअर हो, या फॉरेन में भी हो, वे चीजें आर.बी.आई. द्वारा ही रेगुलेट होती थीं। इस बिल में जो अमेंडमेंट आ रहा है, निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा होगी, बैंकरप्ट के संबंध में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 23 के सब-सेक्शन में भी साफ लिखा है कि Where a system participant is declared by a court of competent jurisdiction as insolvent or is dissolved or wound up. If you go through the Bill, I think you will reach the conclusion यह बिल आर्थिक सुधार के लिए मील का पत्थर साबित होगा, आप इसको धन्यवाद देंगे। आप उस बिल को कम से कम पढ़ तो लीजिए। यह मंत्री जी की सदाश्यता है कि उन्होंने कहा कि पढ़ने में बहुत कम्पलेक्स है, इसलिए मैंने पढ़ा, यह बात नहीं भी कह सकते थे, जिस सरल ढंग से उन्होंने समझाया, आप समझ भी जाते। अगर मंत्री जी ने कह दिया कि पढ़ने में बहुत कम्पलेक्स लग रहा है, लेकिन पढ़ने में चाहे जितना कम्पलेक्स लग रहा हो, यह आर्थिक सुधारों के लिए सुरक्षा देने वाला बिल है। इस बिल को भी ...(व्यवधान) आप अगर बिल के ऑब्जेक्ट और रीजन पढ़ लिया होता तो शायद इस बिल के बारे में समझ में आ जाती, ज्योतिरादित्य जी सबको जरूर समझाने की कोशिश करेंगे, मैं बहुत थोड़ी बातें कहना चाहता हूं कि G-20 endorsed the development and maintenance of a global legal entity identified system. The legal identifier is a 20 character unique identity code assigned to entities which are party to a financial transaction and could be unique across the globe. पूरी दुनिया के लिए 20 अक्षर का कोड जारी होगा। इसे ट्वैन्टी करैक्टर भी कहते हैं। उस 20 अक्षर का यह कोड न केवल भारत में लागू होगा, बल्कि पूरी दुनिया में यह कोड रहेगा और एक दूसरे में सूचनाओं का आदान-प्रदान होगा, इन्फोर्मेशन्स का आदान-प्रदान होगा।

> "The use of the Legal Entity Identifier numbers is likely to be mandated for Over the Counter derivative transactions and large borrowers in a phased manner."

मैं समझता हूं कि यह बिल बहुत साफ और सिम्पल है। जाहिर है कि आज जो भी लेन-देन है, चाहे एक बैंक से दूसरे बैंक के इंडीविजुअल्स की बात करें, चाहे इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेज की बात करें, चाहे हम अब्रॉड के साथ जो भी लेन-देन करते हैं, उन्हें रेगुलेट करने के लिए एक कानून बनाने का काम हो रहा है। मैं समझता हूं कि यह बहुत सिम्पल अमेंडमैंट आया है। यह बिल तो वर्ष 2007 में पास हो गया था, लेकिन आज हम उसे एक लीगल कोडीफाई कर सकें, लीगल अधिकार दे सकें, जिससे कम से कम हमारी सरकार उन कस्टमर्स के हक-हकूक की हिफाजत कर सके। यह कदम अगर सरकार उठाती है तो निश्चित तौर से खड़गे साहब को बधाई देना चाहिए और यह कहना चाहिए कि हम इस बिल को सर्वसम्मत से पास करेंगे।

अभी प्रो. सौगत राय ने क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में सवाल उठाया। वैसे वह समझते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उनकी बात दूर तक जानी चाहिए, इसलिए वे खड़े होकर प्वाइंट ऑफ आर्डर भी उठाते हैं। वे जानते हैं कि जब बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो प्वाइंट ऑफ आर्डर या बिल को इंट्रोड्यूस न करने या स्टैंडिंग कमेटी में भेजने का अवसर कल ही था। वे प्रोफेसर हैं और हम लोग उनसे सीखते हैं। कल जब यह अवसर था तो उन्होंने उस अवसर का लाभ नहीं लिया। अब जब बिल पर डिस्कशन हो रही है तब प्वाइंट ऑफ आर्डर उठा रहे हैं। इसके बावजूद चेयर और हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं और उनको आपने बोलने का मौका दिया। मैं समझता हूं कि क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी आप देखिये।

> "The said Act, though providing for netting protection and settlement finality in the event of insolvency or dissolution of system participants, does not expressly contemplate a situation which may warrant netting on account of insolvency or dissolution of the central counter party itself."

मैं समझता हूं कि सैटलमैंट की बात को भी अमेंड किया जा रहा है। वह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पहले जिस तरीके से सैंट्रलाइज सिस्टम या डीसैंट्रलाइज सिस्टम से सैटलमैंट हो रहा था, उन दोनों सिस्टम में, यानी डीसैंट्रलाइज सिस्टम में भी अभी तक एक बैंक दूसरे बैंक के साथ कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करती थी तो वह आर.बी.आई. के थ्रू ही होता था लेकिन उनकी कोई लीगल एंटीटी नहीं थी। आज कम से कम लीगल एंटीटी, आईडेंटिफाईड जब उसे इश्यू किया जायेगा तो उससे एक लीगल एंटीटी हो जायेगी और व्यक्ति को एक कोड दिया जायेगा तो उससे निश्चित तौर से एक सुरक्षा होगी।

मैं समझता हूं कि वर्ष 2007-08 में एक स्थिति, जिसका वित्त मंत्री जी ने उल्लेख किया कि पूरी दुनिया में एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसेस हुआ। मैं कहूंगा कि उन परिस्थितियों में भी आज हम पहल कर रहे हैं। भारत पहल कर रहा है, भारत की बैंकिंग पहल कर रही है और भारत की सरकार पहल कर रही है। शायद यह दूसरे लोगों के लिए आदर्श होगा क्योंकि जब हम किसी इंटरनैशनल फोरम में हम कोई बात कहते हैं ...(व्यवधान) मैं एक-दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं इसलिए थोड़ा वक्त ले रहा हूं ताकि चीजें क्लीयर हो जायें, जो मंत्री जी के कहने के बाद रह गयी हैं। उसके बाद विपक्ष से कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी और निश्चित तौर से यह बिल पास हो जायेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बिल के संबंध में चीजें क्लीयर हैं। जिन तीन अमेंडमैंट की बात की। मैं समझता हूं कि खड़गे साहब ने एक टाइटल की बात कही, सैक्शन 23 की बात की। मैं समझता हूं कि उन्होंने अब बिल देख लिया होगा। सैक्शन 34 (a) की बात कही। मैं समझता हूं कि वे सारे बिल को देखें। मैं खड़गे साहब और विपक्ष के सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध करूंगा कि वे इस बिल को सर्वसम्मत से पास करें और इस सरकार को बधाई दें। धन्यवाद।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the Payment and Settlement Systems (Amendment) Bill, 2014.

This Bill seeks to amend the original Bill, the Payment and Settlement Systems Bill, 2007. As our hon. Finance Minister said, it mainly seeks to amend Clause 23 of the Bill. Amendment to clause 23 has different parts. There are also some amendments to clause 2 and clause 34. With my limited knowledge I felt that it could have been referred to the Standing Committee. In the Committee we could call the representatives of the Reserve Bank of India and the Clearing Corporation of India and then we would be able to study positive and negative aspects of the earlier payment system, which has been continuing since 2007. But since the Finance Minister felt that it was not necessary, I bow to his superior wisdom and I am taking part in the discussion over this Bill.

I have little knowledge of financial matters. I used to teach physics. I can understand difficult principles of quantum mechanics. I am not brilliant like hon. Shri Jagdambika Pal, who has been a former Chief Minister for three days and has been the ruling party Member both in the UPA as well as in the NDA regimes. Now, I do not have that superior wisdom and intelligence. He said it is very simple. But I still do not consider it to be simple.

The question that I want to raise in the House is that, why is the Finance Minister in a hurry to pass the Bill. He has stated in the Statement of Objects and Reasons that the G 20 countries feel that this system should be introduced in this country. Our Finance Minister attended the G 20 Finance Ministers' Conference before he fell ill in Cairns, if I am not mistaken. There they must have pressurised him saying, "Finance Minister of India, why don't you pass the Bill?" So, I can understand that there is an international pressure on him in this matter. But this is what is special about the First World countries. … (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: I have respect for my friend Prof. Saugata Roy. I always call him 'Dada'. He knows it. But I want to make just a point of correction, which

may alter his argument. I never attended the G 20 Conference, but the UPA Finance Minister did. What you are saying applies to them.

PROF. SAUGATA ROY : I made a slight mistake. The Cairns meeting was attended by Shri Chidambaram. But the Prime Minister attended the G 20 meeting in Australia. The pressure from there must have come to the Finance Minister.

Now, this is what is special about the First World countries. They first pollute the world as much as they can, emit all the carbons and then they pressurise, in the international fora, India to follow their emission norms. First, they totally botch up the system. Then, they pressurise us to follow their norms. See what has happened to America in 2008. They had this sub prime mortgage system. Sub prime mortgage system was a system due to which financial services firms like Lehman Brothers collapsed. They have not yet recovered fully from the meltdown of 2008. Now, they are after us, pressurising us to follow the G 20 norms. The Finance Minister is following their foot steps. I think, basically our financial system is stronger. Our regulator, the Reserve Bank of India, has looked after the financial system, especially the banks, better. There was no collapse of Indian banks during 2008. So, while we should follow international norms, the pride in the solidity of our financial system should also be there in the Finance Minister's mind. I find that missing because three times in the Statement of Objects and Reasons he has mentioned G 20 countries want it. We will do what is good for our country. We want to participate in the international trade. But because of the hurry that the G 20 countries have, we should not take recourse to any legislation or pass any legislation.

Basically, what is settlement? Shri Jagadambika Pal while reading from his note mentioned about different types of settlement. There can be two types of settlement. One is centralised and the other is decentralised. Decentralised settlement is, I buy something from you and you pay me money. But there can be centralised settlement, which is of two types. One is real time group settlement – you present a whole bunch of cheques from one bank to another, they pay you back. So, this is real time settlement. Settlement can also be in virtual world, electronic fund transfer system. That is more common and prevalent in these days. In both sorts of settlements, ultimately the controlling authority is the Reserve Bank of India (RBI). The Bill in 2007 also stated this. Here, there is a new concept. New concept is to set up trade depository. They have designated Clearing Corporation of India which as the Minister explained is a subsidiary of the RBI as the trade depository. Trade depository basically will deal with all tradings in the financial sector.

SHRI ARUN JAITLEY: There is a slight slip on my part. So, I would like to correct it since you have repeated it. I said that it is authorized by the RBI. I wrongly used the word `subsidiary'; it is authorized by the State Bank under Section 7 of this Act, its shareholding comprises essentially of financial institutions – State Bank, ICICI, Bank of Baroda, HDFC, STC, LIC, IDBI – it is these kinds of banking institutions which collectively hold it. It is not directly a subsidiary.

PROF. SAUGATA ROY : I thank the Minister for correcting himself. That is the sort of boldness and directness that we expect from Shri Jaitley.

As I was saying that this trade depository will basically keep the history of any instrument. Why is the trade depository necessary? It is necessary as it is mentioned for over the counter derivatives markets. I went to ask Shri Jyotiraditya Scindia, who was a finance man, worked in Mumbai, who explained to me as to

what exactly derivatives mean. He explained to me in simple terms like Shri Jaitley did. He said that if I have a foreign equity or foreign shareholding, and I want to take the risk of the foreign exchange part out. So, I would take a derivative. Once you take a derivative on an equity holding, then, you can trade the derivative over the counter. This new trade depository will act as the clearing corporation Am I right, Shri Jaitley?

SHRI ARUN JAITLEY: Yes.

PROF. SAUGATA ROY : Clearing Corporation will keep the history of all the instruments. Any time somebody wants to refer they can come to the Clearing Corporation and see as to what is the history of this instrument of this transaction. The new thing that is being added which is truly an international thing is what is called the legal entity identification system, that is, for any big transaction, you will get a 20 character unique identity code. Like in Aadhar Card, you get an identity code; here, for any transaction you would get a 20 character identity code. This is entirely a new thing. Immediately a transaction can be identified with this 20 character legal entity identifier issued. The same Clearing Corporation of India will issue this 20 character identity code. For any future transaction, you will have to refer to that identity code, if I am right.

Now Mr. Jaitley has already mentioned as to what happens in such cases. Previously in 2007, we had taken precaution against possible liquidation of the system participant. If the Clearing Corporation of India goes bust, what happens in that case? Then this law provides for that eventuality. Earlier we had Clearing Houses. The local Reserve Bank was the Clearing House and different banks used to send their instruments. They were divided and then the money was given. Now, the Clearing House has become the Clearing Corporation of India. With electronic fund transfer, the whole process has become very easy and even passing of actual instrument is not necessary. The whole thing can be done electronically now. So, the Bill takes care of the possible collapse.

This Bill takes care of another important thing. These days, we have, what is known, as the Gift Card. You may have a Gift Card for Rs. One lakh. With that, you can go and shop at various places. You may have paid for it and so you have got a Gift Card. Now, what happens if the bank, which has issued you a Gift Card, collapses? There will be an escrow account and the escrow account will refund the Gift Card holder for whatever losses he has suffered. The whole idea is to make the whole payment and settlement system easier, more transparent and international. With a 20-character identifier, you make it international so that international transactions can take place very easily.

So, I hope, with the passing of this Bill, when our present Minister goes to attend the next meeting of the Finance Ministers of G-20 countries, he will be lauded that he has done what they wanted him to do and say that India is now compatible with international norms. In that respect, I would like to commend the Minister of Commerce and Industry that against pressure in the WTO, she held out against the pressure to release our food stocks. Sometimes we should hold up against the big countries and not go by whatever they would like us to do.

Finally, since I have this great opportunity of speaking in the presence of the Finance Minister, I would like to know from him about the progress that has been made in the unearthing of black money stashed abroad. We are waiting with bated breath to know when we will know the names of black money holders. As we asked Mr. Jaitley in the last debate, when will the amount of Rs. 15 lakh come to our accounts?

With these words, I conclude my speech.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I thank you for permitting me to participate in this debate on the Payment and Settlement Systems (Amendment) Bill, 2014.

At the outset, as has been explained by the Finance Minister, this Bill seems to be a bit complex and complicated and as Mr. Kharge, Leader of the Congress Party, has mentioned because of the Statement of Objects and Reasons it has become more complex and complicated. I hope the ruling dispensation has taken his suggestion in good spirit and henceforth the Statement of Objects and Reasons would be explained in a simple manner so that it becomes easier for all of us to understand, especially financial matters. I would say, there are specifically, as has been said, two specific amendments that are being brought into. Amendment to Section 23 is in two parts and there is amendment to Section 23A where an insertion is taking place. Then it is to substitute sub-Section (4) of Section 23 of the Principal Act where a system participant is declared as insolvent or is dissolved or wound up, then the liquidator or receiver or assignee are going to play a role. But, before that, there is another sub-section (1) after the words "to a payment system" occurring at the end, the words "under section 7, or, such gross or netting procedure as may be approved by it under any other provisions of this Act" shall be inserted. I fail to understand, this first part of the insertion which is being made. I think, it needs a little bit of clarification in the first part of sub-section of Section 23.

Regarding the other two, there is very little issue to be understood. I would say, as there is no legal provision in any of the law administered by the Reserve Bank of India to regulate and supervise the trade repositories in India, it has become essential to bring this type of amendment. Currently, there is no legal provision under any of the laws administered by the Reserve Bank of India for regulation and oversight of the legal entity. Therefore, this amendment is essential.

I would say, the consumer banking frauds are on the rise. A Reserve Bank of India Group had suggested the use of public key infrastructure in order to ensure a safe and secure payment system in the country. The Central Bank has announced a series of initiatives to improve technological infrastructure to support payment and settlement system which are termed as PKI such as Real Time Gross Settlement, National Electronic Fund Transfer.

I remember in 2006-2007, when this Bill came up before the Standing Committee for deliberation, the basic question that was posed to RBI and also to other stakeholders who were witness before us is that electronic transfer is taking place. Plastic card has become the call of the day. As my friend Mr. Ahluwalia was telling me some days back, if somebody is going to rob you when you are walking on the street, they are not picking up your wallet; they are snatching your mobile telephone. It is because your wallet does not carry much money, much hard cash. It carries plastic cards. So that card cannot be used by robber or whoever who takes your wallet. He robs you of your mobile phone because it fetches him Rs. 500 or Rs. 3000, whatever may be the market price. But the question that arose there was, with this transaction of money, when I am giving a cheque, how long does it take to get reimbursed? In different States there are different clearing houses and are recognised by RBI. How long does it take? I come from Cuttack. Cheques are delivered to me or to certain institutions or firms from Bhubaneswar. It takes minimum three days with a distance of only 22 kilometres. The question that had arose in 2007 was that why should it take three days? If it is with Mumbai or with Delhi, the minimum time is eight days. Why should it happen? You are talking of electronic age. It should happen instantly. If I can do RTGS; if I can send money to my family members from the Parliament House Branch of the State Bank of India in Delhi, it reaches them within two or three or four hours and I get it confirmed that, yes, they have got it.

If I give a cheque, why can it not be transacted within a minimum time span? Why should it take seven or eight days' time? That is a question.

When we are discussing on this aspect, I think, it is necessary that we should also deliberate on the payment structure. The Payment and Settlement System Bill is getting amended today. Though it was passed in 2007, it came into operation, actually, in 2008. This new Bill seeks to amend certain parts of the Act to provide that if a system participant is declared as insolvent or is dissolved or owned up by an order of a court or an authority, it will not affect any settlement that has become final prior to such order or immediately after it. It also seeks to insert new sections including one on protection of fund collected from the customer by the payment system provider.

Sir, what is this term called 'payment system'? It is a term used by many but understanding the true depth is perhaps left to a few like Professor Saugata Roy and Jagdambikaji who directly come into contact with payment systems. A peep into the vast amount of literature available on this subject leaves one either stunned or confused depending on what one's perception had been earlier regarding this subject. It could be viewed, at the simplest level, as a means to transfer funds or a 'system' with all the accompanying connotations. Going by the latter, a comprehensive understanding of payment and settlement systems can be had by its definition. The definition says;

> "Payment and Settlement System refers to a set of rules and regulations, processes and procedures, instruments and institutions, and including the legal framework, which facilitate transfer of financial assets between the sender and the receiver". Our own Payment and Settlement Systems Act 2007 defines a payment system as 'a system that enables payment to be effected between a payer and a beneficiary, involving clearing, payment or settlement service or all of them, but does not include a stock exchange'."

Again, the perception about payment and settlement systems and its complexity depends on whether one is just a user of the payment system or a participant in the system or both. The instruments of payment itself may vary from being cash-based or non-cash based. An efficient functioning of payment system in any country is reflected by the ability of its financial sector, reduced cost of transaction, optimum utilization of financial resources and increased market liquidity. A safe and efficient payment system facilitates the smooth transmission of the Central Bank's Monitory Policy signals. Globally, payment systems have been undergoing a sea change in tune with the changes in technology.

Therefore, I would say on what Professor Saugata Roy said: "Do not go into the dictates of G-20." We are invited to G-20. We participate in the deliberations of G-20. We cannot keep our system away from the processes and the agreements that G-20 has agreed upon. To recover black money, it was G-20, who took the best steps forward. In that respect, I would agree and also support what has been mentioned here that we have to take up those methods which the developed countries have accepted and that is the right direction which we should proceed with.

In any system, its rules and procedures should be enforceable, simple and clear; and their consequences predictable. Illegal system would pose dangers to its participants if these things are not that clear.

Generally, contract law is the basic bedrock of any legal structure on which the enforceability of agreements that are used to establish the rights and obligations of system operators and participants that participate in a payment system are built. Such contractual arrangements must be enforceable and inviolable to ensure smooth conduct of operations under normal circumstances as well as during financial crisis.

Sir, with this Act in place, all these payment systems would be regulated by the RBI under the legislative framework. The Act has been effective from 12th

August, 2008, as I had mentioned earlier. I would say that the term 'payment system' is defined in Section 2(1) of the PSS Act. Before I conclude, I would just mention here that this Act is, indeed, a very positive legislation for the smooth conduct of the payment system as it recognises the concept of netting, gives finality of settlement to the transactions and protects the netted transactions settled through recognised and payment system from adverse impact of insolvency, recognition of loss allocations, etc. This piece of legislation not only imbues the system with a sense of protection but will also go a long way in promoting a healthy financial payment system in India.

I would say that with these two amendments, the Act is getting more strengthened; and it is expected that it would be a benchmark in the Indian payment system against international standards.

Thank you.

प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ (उस्मानाबाद) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मेरी एक विनती है कि देश में बैंक हैं, लेकिन जो बैंक कोऑपरेटिव सैक्टर में हैं, उनमें शेयर्स की जो रकम दी जाती है, उसका भुगतान इस देश में एक भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने आज तक नहीं किया। मेरा निवेदन है कि उसे भी प्राथमिकता दें। धन्यवाद।

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Hon. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on this important Bill.

With increasing globalization, there is a need to be consistent and to conform with the globally accepted standards as stated in the Objects and Reasons by the Minister. It is, indeed, welcome.

In today's world of commerce, the number of transactions are increasing exponentially so far. But with the implementation of the RuPay card and other things, it would not increase exponentially. It would increase in mathematical terms, hyperbolically, cube of the previous year. There is a need to increase the speed and efficiency of the transactions. Most importantly, Sir, there is a need to bring in a finality through the settlement, which is, again very, very important.

Claims of the previous financial years can crop up this year as ghosts from the past. I think, this Bill can potentially put an end to these claims from the previous financial years. The Bill helps, probably, in also reducing legal litigations in terms of unsettled claims.

The hon. Minister gave examples of how the Bill will protect unsecured vendors. I think, that is, indeed, welcome.

The amendments to the Payment and Settlement Bill are overdue. The amendments are welcome. On behalf of the Telangana Rashtra Samithi party, I stand to support the amendments to the Bill. However, Sir, I have a few clarifications from the hon. Minister. As per the proposed amendments, the decision of the court, tribunal or any authority will not impact the settlement which had become final prior to the issuance of the order. Now, I fail to understand and I need a clarification on this that if the matter is already *sub judice*, can an authorised settlement agency make the settlement in finality? That is my question. I have a few other small clarifications. The Minister did give the example of Uber and Paytm. Do they also come under the purview of this? Does

Paytm come under the purview of this Bill? Does the Indian Postal System, which offers cash on delivery to our parcels, come under the purview of this Bill? So, I have lot of such minor clarifications.

But I would like to agree with the Minister on one thing. The decisions and opinions on this discussion will definitely not be partisan because every Member here wants to facilitate this and make the transaction system more efficient. But, however, given the time, I, for one, could have had the opportunity to educate myself better and probably, one or two Members actually might have even given a good suggestion. So, I look forward to the clarification from the Minister. Thank you, Sir.

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Mr. Chairman, Sir, it is well said in English that finance is the engine of growth. I would like to appreciate our hon. Minister of Finance, Arun Jaitley Ji. I can read his lips because he is smiling as he has ensured that this House is in a mood to pass this Bill, I hope, within minutes. I do not know whether just because we are discussing a very simple Bill, this House very barely crosses the minimum number of MPs who should be present here. We are just across the quorum. This is a very serious Bill that we are discussing. Of course, we have quorum. I am not questioning because I cannot interrupt my own speech anyway. But this is an important Bill. Anyway, this is going to affect positively our financial sector. In this, I have certain doubts, maybe, because of my lack of knowledge or because of my ignorance.

The point which I would like to raise is that while we were students of economics, we had learnt about bills of exchange, the discount houses, clearing houses, etc. But in our nation, the clearing houses and the discount houses are not very strong. That is not in usage very much. Here I understand and if I am correct, the hon. Minister is intending to amend the principal Act, the Payment and Settlement Systems Act, 2007, in three matters--one is regarding Section 2, second is Section 23 and third is Section 34. These are the three Sections. Certain doubts have been raised by my colleagues here on these three Sections. I hope the Minister may clarify their doubts.

Sir, with your permission, here I may be permitted to read from the Statement of Objects and Reasons. What the Minister says in paragraph 4 is this.

"The legal entity identifier is a 20 character unique identity code assigned to entities which are parties to a financial transaction and would be unique across the globe.".

This is necessary in this era of globalization. But at the same time, you also very well know that in our nation, there still exists the barter economy; and there still exists a parallel economy consisted by black money. Now-a-days it has

become very easy for the flight of black money from this nation to abroad, to any other nation, and for the import of black money, a flight from abroad to India is also much speedier. We all understand that that happens in this nation. Even whatever the G-20 nations may say and whatever laws we make, always a mouse finds a hold somewhere. And, it happens. At the same time, the money or the legal tender, takes much time to reach to the recipient. So, this happens. How can this be overcome? I ask such a question because this is a very important Bill. Many of our colleagues have raised that point. We did not get much time to go through this Bill because only yesterday the hon. Minister introduced this Bill in the House and today the Bill is here for consideration and passing. I would say that they have raised a very pertinent point that this Bill should have been sent to the Parliamentary Standing Committee. The Standing Committee should have taken the initiative to collect evidence and have a discussion with various stakeholders.

Sir, the number of credit card holders is increasing in our country. Of course, it is a symbol of economic growth also. That also we can understand. At the same time, the frauds happen. You see it in the electronic media. That is also in the rise. It is rising disproportionately. I am not talking about any ponzi schemes. If I say something about Sahara, Satyam or Saradha, I am afraid that some of my colleagues may get irritated if not frustrated. But, it is true that behind the Satyam or Saradha or Sahara incident, the element of fraud was there. It was actually a cheating to the depositors, who have deposited their money.

While appreciating the initiative that has been taken by the hon. Minister, I want to know what measures we can undertake to check the fraud. Even if the Reserve Bank of India entrust these jobs to the Clearing Corporation of India, still these frauds will increase. So, this matter has to be looked into.

Regarding the provisions of the Indian Contract Act, I have a doubt. I do not get much time to speak on this matter. My doubt is that after some of the provisions of this Act get amended, will they not be in contradiction with certain

provisions of the Indian Contract Act. If that is so, who is the arbitrator and who will have the last word in that?

Sir, clause 4, section 23 *(1)(a),* mentions:

> "the deposit and keep deposited in a separate account or accounts held in a scheduled commercial bank; or *(b)* maintain liquid assets in such manner and form as it may specify from time to time, of an amount equal to such percentage of the amounts collected by the system provider….."

Anyway, I will support this. But, at the same time, take, for example, a corporate, I mean, a juridic personality. They are not natural personalities. There are always consortiums, subsidiaries and other agencies behind the veil. So, unless and until we have a provision to lift the corporate veil, we will not be able to identify as to who is behind these frauds and irregularities. How will we know about the money, which has been siphoned off? All these legal actions are to be taken by the concerned settlement corporation. How that can be taken into account; how that can be caught hold of? We cannot allow frauds of lakhs and lakhs of rupees being siphoned off by various companies and a natural person being in pity. When there is a battle between a corporate and a man, who may be a pensioner – sometimes we will also become pensioners like ex-MPs and others – that old man will be at peril. His life will be at peril. He will not be able to fight with the corporate and the corporate, maybe, by the time would have been wound up. Then, all the legal sanctities would be in vain. So, this thing should also be looked into. Thank you, Sir.

16.00 hrs

KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): Thank you, Chairman, Sir. Mr. Jaitley, before we started this debate, very briefly explained on the floor of the House as to why this Bill has been necessitated, and what is the Objects and Reasons of the Bill. He relegated his speech to just one aspect of the Bill, but in a hurry, I have seen the statement, as reported by PTI, where the hon. Finance Minister has himself stated that the amendment seeks to protect funds collected from the customers by the payment system providers and to extend the Act to cover trade repositories and legal entity, and identify issuers.

A legal entity identifier is a unique ID associated with a single corporate entity. But the main sections that I have seen relate to a proposed amendment where the decision of the court, tribunal or any authority vis-à-vis declaring a service provider insolvent will not be effective retrospectively. But what I would like to understand from the hon. Minister is that whereas we are trying to protect the customer from an insolvency order so that it will not affect a settlement that has already been finalized. Therefore, if somebody has already collected the owed money from a customer, then we are giving that customer priority, which the Companies Act, Section 529 is not giving. But the question is that in insolvency proceedings will something remain for that customer because it has already been declared insolvent? This is a query that comes to my mind.

I appreciate the fact that with the global economy merging and with the G-20 coming into the picture, we have to meet the international standards, but I would have been far happier if this Bill had been referred to the Standing Committee because this Bill seems to be significant, which will ensure financial prudence, transparency and accountability, and no one in this House can disagree with it. But the idea is that the Bill that most of the Parliamentarians here have not been able to decipher, I wonder that, as policy makers, are we acting responsibly

in allowing this Bill to be debated today and passed where we are showing concern for an ordinary customer not to be deprived, especially, in light of what has recently come in the news.

It was stated in today's '*Indian Express*' about the Uber Taxi Service that they initially had no such system in place. It is only recently that they have submitted to the wallet system.

I feel that, yes, no doubt that this Act is a significant one and it is bound to protect an ordinary customer, but I wish that we had spent a little more time in the Standing Committee discussing this for the simple reason that as responsible policy makers when we pass a Bill, we become answerable to the people.

I hope that you will enlighten us on the aspect that I had raised, which talks about the order not affecting a settlement that has already been finalized. Thank you.

SHRI ARUN JAITLEY : Sir, I am extremely grateful to a very large number of hon. Members who have spoken on various aspects of this law.

As the title itself indicates, it is a Payment and Settlement Systems Act. Therefore, for any form of financial transaction to be honoured or any form of commerce to have credibility, it is extremely important that commercial transactions are respected and honoured. You cannot have other devious methods or ploys by which commercial transactions are not honoured in the spirit with which they are maintained.

The reference to G-20 which was made by my friend, Prof. Saugata Roy; he is not here. He said that he has been a student of Quantum Physics. Now, Quantum Physics and real politics make a very interesting combination. Therefore, going by the best global practices where the intention of the world at large is that transparent transactions must be honoured, payments which are made must reach the payee, and in case they do not reach the payee, there must be a statutory mechanism to settle those payments. Therefore, the Payment and Settlements Act really came about to be legislated with this objective. If payments are made, payments must be respected, payments must be honoured and the settlements, in case there is some kind of an intervention which takes place, must be effected.

Now, the entire Act itself enables the Reserve Bank of India, as the functional regulator in this field, to give an authorization to third entities, and those third entities could be Governmental, could be non-Governmental, and they become the clearing agents.

16.07 hrs (Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

Now, several questions have been raised. The hon. Member Shrimati Sathyabama from the AIADMK spoke about the technological security to the entire electronic transactions. She is absolutely right. The Clearing Corporation of India has taken particular keen interest on this. Therefore, the international

standards have been provided for the technological security by the Bank for International Settlements. It is those standards which are being applied, as far as these clearing houses are concerned.

PROF. SAUGATA ROY : Will you introduce encryption?

SHRI ARUN JAITLEY: After all, as technology grows, I can check it up and get back to you on the functioning, firewalls around these have necessarily to be created. Otherwise, for anyone to go and intervene in that and, therefore, the process of commerce is set at naught would be quite easy.

It is not that we have gone and blindly followed what G-20 has been saying. From 2008 onwards, even though India is an invitee, this entire negotiation with the global fraternity has been going on. We cannot afford to live an isolationist existence. We cannot provide a banking system which is inconsistent or a financial system which is inconsistent with global standards. So, right through 2008 to 2010, the finalization of those standards with regard to the service providers was finally decided in 2012, when the UPA was in power. I find nothing wrong with it because that is how the entire financial system has to evolve. Otherwise, if we have an obsolete financial system, the world will not trust us to the level at which the world should if we are to relegate ourselves to a country whose financial system must really have confidence itself.

Now, the question raised by Kumari Sushmita Dev, our hon. Member from Assam, is what will happen or whether this will override even earlier transactions or subsequent transactions which are taking place. Supposing, I make a payment through a clearing house to any of my learned friends here, and the interim agency is the clearing house, whose face I do not see or none of us sees, but it is an intermediary. Where did that intermediary bursts? The payment instead of reaching you lands up with the third party. Once insolvency takes place, what is the law that must regulate? Let this payment go to the third party. If that is the

law in India, then the world at large or even Indian parties would think twice before transacting through these instruments.

So, the object is that there is an obvious gap. You cannot have a court decree and somebody comes up and say that I have a court order in my favour. So, the payment which is made by Mr. Jaitley to Mr. Roy lands up with Mr. Jagdambika Pal. It cannot happen. I am just referring to the two main speakers who spoke. Therefore, the payment must reach you. Even if the third party has a court order in his favour and if he says under a special law of Companies Act or Banking Regulation Act, I will stand before Mr. Roy as far as the queue is concerned, this law says no. This is for these instruments under the Payments and Settlements Act the person you have paid to, it must reach him and if it does not reach him because of a contingency, the law must provide for a settlement by a process through which it reaches him. This was the gap in the law and that gap is what we are really trying to fill up.

Mr. Mahtab raised a question as to what is the object of section 23(1) in this Act itself. The real object is that the procedure and the priority being given to the payee must be recorded statutorily in this Act and this Act, therefore must have the effect of over-riding other Acts to the contrary. Otherwise Contracts will not be honoured itself. The hon. Member who spoke towards the later part of the debate wanted to know whether there is a contradiction between the Contract Act and this Act. It is perfectly consistent with the Contract Act and the reason is contracts are to be performed and not to be breached. That is the underlying principle of fairness in any private sector or the Public Sector contract. If we are in an economy which is now a free market economy or at least moving towards that, it also essentially implies fair economy. Unless it is a fair economy where contracts are performed and not breached and if I make a payment for the benefit of somebody and there is an intermediary, the implicit contract is that the payment must reach him. If the law so provides, how can such a law be contrary to any

provisions of the Contract Act itself? If bank frauds are taking place, each fraud must be looked at on its merits or demerits. If there is a violation of a statutory provision, people must be taken to task. If there is a gap in law, we must fill up the gap in law. But that cannot be a reason that we allow this obvious gap to continue that the payment intermediary goes insolvent and the payment does not reach the payee. That is the limited objective of this law.

All other amendments, which are being brought about are consequential to the principal objective and therefore, this being in consonance with the principles of fairness and the best international practices, I would commend to this House while thanking all the hon. Members who have taken keen interest. But I must end only by saying when I heard Mr. Roy, he is wiser than most of us. So, initially, when he was saying that this is a complicated piece of legislation, after hearing him I understood that he understood this law more than any one of us. Therefore, his elaborate speech itself now establishes that the law can be passed today without a reference to the Standing Committee. Thank you Sir.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That the Payment and Settlement Systems (Amendment) Bill, 2014 be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

> "That clauses 2 to 5 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:

"That the Bill be passed."

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

16.16 hrs

DISCUSSION UNDER RULE 193
(i) Natural calamities in various parts of the country

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, as you are aware, discussion under Rule 193 on "Natural calamities in various parts of the country with special reference to rains and floods in Jammu and Kashmir, cyclone Hudhud in Andhra Pradesh and Odisha and drought in Maharashtra" was deferred yesterday to facilitate reply by the hon. Minister of Agriculture to certain clarifications.

Hon. Minister is present in the House. I will now call the Members who want to seek clarifications. You can ask only one question each.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): The Agriculture Minister is here. Yesterday, it was promised in the House. This subject has come again in the agenda because yesterday the Minister was not here. You had promised that we would get the reply from him. We are waiting to listen to him as to what he is going to say about Maharashtra and other things. … (*Interruptions*)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : महोदय, इस पर बोलने का मौका दीजिए। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: The Member from your Party has already spoken.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Here, I would just like to make a small clarification about what Shri Kharge said that the Minister was not here. The fact is that the Minister did intervene and had given a reply on the subject. When he had done that, they were not present in the House. Still we were very generous. We decided to ask the Minister to come back again and reply. So, this should be put on record, instead of saying that the Minister was not there. … (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, if you are convinced, we will sit. You are a senior Member of Parliament. You know that. When the debate is not concluded, discussion is not concluded, how can he give the reply? At the most, he can intervene. It cannot be called a reply. It can be called a reply when the entire discussion is over. After discussion, all those who are connected to the subject, they can reply. You tell us the rule, then I will sit. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: I am not quoting any rule.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Yesterday, the House was adjourned because of this. … (*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, it is just not a matter of scoring a point. It is a simple matter. We just want to flag an issue. Possibly what the Minister in his intervention said would have been easier for them to understand if they were present in the House. They chose not to be present in the House. Now they are taking a cause to say that the Minister of the Government was at fault, which is not correct. They will have to put the record straight. The Minister was not present because it was listed in a different Ministry altogether. Let us put it on record for the future also. … (*Interruptions*)Let us put the records correct. If this is going to be the system, it is going to be a problem for any Government. Let me put the record straight. … (*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: I am not arguing with him. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Let him finish.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: The initial discussion was only on Hudhud and Kashmir floods on natural calamities. … (*Interruptions*) Why do you not have the patience to listen? The initial discussion was listed virtually on Natural Calamity which was to be responded by the Minister of Home Affairs. Subsequently, when the Members of Maharashtra raised the issue of drought, then we said, yes, we would take it into account. So, it was not the substantive business of the House.…

(*Interruptions*) Then we added. So, there is virtually no Department where two Ministers come to answer one debate. It is generally one Minister who comes to answer one debate. Since this was an additional gesture on the part of the Government, we took up the issue and that should be placed on record.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Deputy-Speaker, Sir, actually a piquant situation has arisen and this House is supreme to settle this issue. As the hon. Minister just now mentioned, the original notice for consideration of a discussion under Rule 193 related to cyclone in Andhra Pradesh and Odisha and flood in Jammu and Kashmir. It did not mention the flood in North-East also. The original notice which was moved by Shri Kalikesh Singh Deo was relating to these two natural calamities relating to the Ministry of Home Affairs. There was no mention in that about the drought situation of Maharashtra or any other State which has been affected. Later on we were really surprised because yesterday when the Member from Maharashtra and some other Members from the Congress Party also raised this issue that why not there is a response from the Agriculture Minister. Agriculture Minister had replied, or intervened in between. At that time because of certain other circumstances the hon. Members from this side were not present.

We have to settle it and you have to give a direction in that respect. Yesterday when I stood up and said, should we say that the Home Minister or the Minister of State for Home Affairs is concluding this issue and Agriculture Minister will intervene tomorrow, there was a direction, that was the question which I asked towards the end of the deliberation that let us conclude what Home Minister has to say. That is why the questions were replied. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: I allowed Mr. Mahtab to speak. Not all others. Let him conclude.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : That is why I said it is a piquant situation. It is a piquant situation because agriculture came in, drought situation came in.

I would say, Sir, the Secretariat can help us out, there was no notice relating to drought situation in Maharashtra.

HON. DEPUTY SPEAKER: That is why he wants to know and he has a right to ask.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : It was done because of the request of some hon. Members from Maharashtra. The original notice was relating to flood, relating to cyclone. Our notice was relating to Home Affairs. It had nothing to do with agriculture. If the House could have taken up drought situation, then there are other areas which are affected by drought which could have been deliberated upon.

Therefore, I would say that you take the view of other Members. Let the House deliberate and you take a decision. But as far as I understand with my limited knowledge of Parliamentary practice, yesterday the Home Minister had replied to the deliberation relating to the notice and partly Agriculture Minister was supposed to reply to the affairs that were relating to Maharashtra.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Mr. Mahtab has tried to enlighten the House. The fact of the matter is that he may be right insofar as his particular party Member's notice was concerned. But as far as this topic of debate is concerned, it was a consolidation of a number of notices that were put together. … (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : That was on the second day, not on the first day.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA : I was not interrupting you while you were speaking, Mr. Mahtab. I would appreciate if you did the same.

There were a number of notices that were consolidated together to make this topic. Once a topic is printed in the List of Business and it does include the drought issue in Maharasthra, then it is incumbent on the Government to respond to that issue as well, which you yourself, Sir, had ruled yesterday that the hon.

Agriculture Minister will respond on the issue of the drought situation. The Agriculture Minister is here, we would like to hear his response so that this debate is concluded. But let us not get into the technicalities. The Minister is here and we should hear his response. Let us not try and score points and dig ourselves deeper in the process. The country requires a discussion and a response from the Government which is what they are willing to offer and we should accept it and go ahead.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, what Mr. Scindia is saying is absolutely correct. When Mr. Kharge pointed out that the Minister was not present here yesterday, that is our only objection because it was not the substantive business. … (*Interruptions*) This will happen again and again. (…*Interruptions*) This debate was to conclude yesterday, but the Government was generous enough to say that we will ask the Agriculture Minister to reply. (…*Interruptions*) To say that he was not present yesterday, is a wrong statement and that is what I am saying. (…*Interruptions*) The business of the House cannot be changed to the tune of some people who decide it. (…*Interruptions*) What you have introduced today has never happened before in this House.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): HON. Deputy Speaker Sir, I request you to urge the Minister of State for Parliamentary Affairs who is newly appointed, not to be like a Jack in the Box. (…*Interruptions*) At every opportunity, he jumps up and says something. He may say something, but he cannot intervene again and again. (…*Interruptions*) Jack in the Box is a parliamentary word. (…*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You are a senior Member, you can speak whatever is right. At the same time, you cannot hurt others. Any aspersion will be expunged.

PROF. SAUGATA ROY : Let me complete my submission. I point out to one factual inaccuracy in the Minister's statement. He said that never in this House in a discussion on 193 two Ministers reply. Even in the 15th Lok Sabha, there were

six different discussions on price rise issue and on every occasion, two Ministers- Shri Pranab Mukherjee, then Finance Minister and Shri Sharad Pawar, the then Agriculture Minister replied. This is a standard practice. If you take a holistic motion, there is no difficulty, no bar on two ministers speaking. Secondly, for the first time I am hearing in this House discussion on the history of a motion. I can understand Shri Bhartruhari Mahtab's eagerness to glorify his own party that they had given the motion. … (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : This is not glorification. … (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY : Sir, you were here yesterday. What does the motion read? … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Mahtab, please take your seat

…. (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY : We do not discuss the history of a motion. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please allow me to run the House.

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY : It says: Further discussion on the natural calamities in various parts of the country with special reference to rains and floods in Jammu & Kashmir, cyclone Hudhud in Andhra Pradesh and Orissa and drought in Maharashtra. So, drought in Maharashtra is very much a part of the motion.

HON. DEPUTY SPEAKER: Okay, you may please sit down. It is over. Nothing will go on record.

(Interruptions) ...[*]

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Thank you very much. I am really hurt. Thousands of farmers are waiting for the relief to be given by the Government, but we are scoring points against each other. The late Mahatma Gandhi said: spiritualize politics. But we are politicizing every issue, even the

[*] Not recorded.

spiritual aspects. I am really hurt. What Shri Rudy said is definitely right. At the same time, I would like to ask Shri Kalikesh Ji, when he has put this issue, it says: Further discussion on the natural calamities in various parts of the country with special reference to rains and floods in Jammu & Kashmir, cyclone Hudhud in Andhra Pradesh and Orissa and drought in Maharashtra. When this issue was incorporated in the motion, why should we debate such issues, when farmers are waiting for the relief?

So, I request that instead of going into technicalities, respecting the sentiments of the farmers, let the hon. Minister reply now. Kindly permit him to reply.

HON. DEPUTY SPEAKER: Since Shri Kalikesh is the initiator of the debate, I am permitting you. What do you want to say now? He is the initiator and he wants to say something.

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO (BOLANGIR): With due respect to my colleagues from the Congress, the TMC and of course, the Ruling Party, I had given a notice on cyclone Hudhud and Philain and also flood in Kashmir. I had given a separate notice on drought in Orissa. My objection is that if you include the drought in Maharashtra – I have full sympathies for my friends from Maharashtra – why did you not include my notice on drought in Orissa also? We could have discussed about drought in Orissa also. I had given both the notices. This is my objection. Since we are discussing an issue of great importance, I would request you to allow the hon. Minister to give his statement in response to my friend's request.

HON. DEPUTY SPEAKER: Whenever a discussion involving two Ministers is there, the reply to the debate is given by only one Minister. The other Minister only intervenes in the debate.

Anyhow, since the Minister wants to say something in response to whatever is raised yesterday, he may please answer.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: No. It is not allowed. Nothing will go on record, except the hon. Minister's reply.

(Interruptions) ... *

HON. DEPUTY SPEAKER: After the ruling, I cannot allow; hon. Minister can reply. I cannot listen to anything else. Mr. Minister may reply now. Hon. Minister may address the Chair.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You may address the Chair and I will manage the House.

… (*Interruptions*)

* Not recorded.

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : महोदय, सिंधिया जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि टेक्निकल मामले में मत जाइए। नौवीं लोक सभा से हम भी यहां पर हैं, यह ध्यान में रहे, बीच में आप भी किसी दूसरे सदन में होंगे, इस सदन में नहीं होंगे। लेकिन जब भी कोई मुख्य विषय होता है, मेहताब जी ने जो बात कहीं, पिछली बार हम सूखा पर चर्चा कर रहे थे, बाढ़ भी उसमें जुड़ गया था, गृह मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया था, मुझे भी इस बार हस्तक्षेप करना पड़ा और मैंने हस्तक्षेप किया। हमने लगभग 20-25 मिनट तक अपनी बातें रखीं। महाराष्ट्र के सूखे के संबंध में भी हमने कहा। उस समय हमने जो कहा था, उसकी दो लाइनें मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों की प्रशंसा करता हूं, क्योंकि उसमें महाराष्ट्र के सूखे का जो विषय है, उस संबंध में, मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहूंगा। प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित कई राज्यों पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन महाराष्ट्र में भी सूखा है, इसलिए मैं कुछ बातें इसमें रखना चाहता हूं। पूरी चर्चा का उत्तर गृह मंत्रालय की ओर से दिया जायेगा। संसद के पहले सत्र में हमने चार दिनों तक सूखे पर चर्चा की थी। सामान्यतया सूखा जुलाई-अगस्त के महीने में डिक्लेयर होता है। हम बीच में लोक सभा में नहीं थे, लेकिन जो 25-30 साल से बराबर लोक सभा के सदस्य रहे हैं, उन्हें भी पता होना चाहिए कि जुलाई-अगस्त इसका मौसम है। उस समय इस पर विस्तार से चर्चा हुई थी और उस चर्चा का लाभ भी हुआ था। वह लाभ यह हुआ कि मौसम विभाग जो रिपोर्ट देता है, वह क्षेत्रवाइज, जोनवाइज, डिवीजनवाइज देता है। अब जिलों में क्या स्थिति है, उससे पता नहीं चलता। पिछली बार जब हमने चार दिनों तक चर्चा की, तो उसमें एक बात यह पता चली कि बहुत सारे जिलों और इलाकों में माइनस 50 परसेंट वर्षा हुई। उस समय विदर्भ की स्थिति कुछ अच्छी थी लेकिन मराठवाड़ा की हालत बहुत खराब थी। उसका लाभ यह हुआ कि प्रधान मंत्री जी ने तुरंत कैबिनेट की बैठक बुलाई और उसमें एक हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी। उसमें चार बिन्दू थे कि डीजल पर राज सहायत दी जायेगी। दूसरा, यदि बागवानी को नुकसान होता है, तो उसे 35 हजार प्रति हैक्टेयर सहायता दी जायेगी। तीसरा, चारा विकास कार्यक्रम के लिए सहायता दी जायेगी। ...(व्यवधान) चौथा बिन्दू यह था कि हम सोयारहित खली, मूंगफली की खली, सूरजमुखी की खली पर आयात शुल्क की माफी की जायेगी। इसका लाभ यह हुआ कि बिहार ने डीजल पर राज सहायता देनी शुरू कर दी। अभी उसका विवरण नहीं आया है। उसके बाद महाराष्ट्र ने कहा कि हमें साढ़े बारह करोड़ रुपये चारे के विकास के लिए चाहिए, क्योंकि हमारा इतना नुकसान हुआ है। उन्हें सवा छः करोड़ रुपये भेज दिये गये। मध्य प्रदेश ने 16 करोड़ और हरियाणा ने 6.97 करोड़ रुपये का प्रस्ताव चारे

के लिए भेजा। बागवानी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 553 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा। इन सबका अध्ययन हो रहा है और यह राशि तुरंत जायेगी। लेकिन सूखे की घोषणा बाद में हुई।

जब हरियाणा में चुनाव शुरू हुआ, तो उसके दो दिन पहले इसकी घोषणा हुई। उत्तर प्रदेश के बाई-इलैक्शन की घोषणा होने वाली थी, उसके पहले घोषणा हुई। महाराष्ट्र के कई सदस्यों ने यहां बताया कि वहां बहुत पहले से माइनस 50 परसेंट वर्षा हो रही है। ...(व्यवधान) किसी ने डिक्लेयर ही नहीं किया था। लेकिन जब डिक्लेयर किया, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा ने किया तो वहां हमारी टीम तुरंत गयी। उस टीम की रिपोर्ट भी आ गयी है, जो अब एनडीआरएफ में जायेगी। हम सबको पता है कि एसडीआरएफ का एक फंड होता है, जो राज्यों मे होता है। सूखे की घोषणा राज्य सरकार कर सकती है और उस फंड से खर्चा कर सकती है। उस के बाद यदि वह अधिसूचना जारी कर दे और यहां मेमोरेंडम भेजे तो यहां से टीम वहां जाती है जो आकलन करती है। उसके बाद वह रिपोर्ट एनडीआरएफ में जाती है। महाराष्ट्र में हमने यह स्वीकार किया कि सूखे की घोषणा पहले होनी चाहिए थी, लेकिन उसमे विलंब हुआ। इस सरकार ने घोषणा की। .(व्यवधान)

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : महाराष्ट्र में इलैक्शन के कारण कोड ऑफ कंडक्ट था। ...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : मैं बता रहा हूं कि इलैक्शन नोटिफिकेशन के दो दिन पहले हरियाणा ने घोषणा की थी। ...(व्यवधान)

श्रीमती सुप्रिया सुले : वहां कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने प्रपोजल भेजा था। ...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : मैं वही बता रहा हूं कि इसमें इलैक्शन आड़े नहीं आया। ...(व्यवधान) हमारी टीम हरियाणा गयी। ...(व्यवधान) जब सूखे की घोषणा होती है तब राज्य सरकार अधिसूचना जारी करती है। ऐसी कोई अधिसूचना महाराष्ट्र सरकार ने नहीं की, लेकिन हरियाणा सरकार ने की। ...(व्यवधान) आप तो इतिहास बना रहे हैं कि इन्टरवीन करने के बाद दोबारा आपके आग्रह पर मैं बोल रहा हूं। आप पढ़िए, मैंने इतनी सारी बातों का जिक्र किया था। आप बॉयकाट कर गए थे इसलिए आपके ध्यान में नहीं है। मैं भी अपनी ड्यूटी समझता हूं ताकि यह बात सबके ध्यान में आ जाए। मैं इस नाते तकनीकी विवाद में न पड़कर इन बातों को आपके सामने रख रहा हूं।...(व्यवधान)

महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की, हमने अखबार में खबर देखी। हमने तुरंत खबर ली और दो तारीख की रात को ई-मेल से पेपर को मंगाया। हमारी बात मुख्यमंत्री जी से हुई। कृषि मंत्री जी को मैंने यहां बुलाया। हम जिस दिन जवाब दे रहे थे, उसी दिन हमने सुबह कृषि मंत्री जी को पूरे पेपर्स लेकर बुलाया था चूंकि ई-मेल से भी आए थे लेकिन कुछ और जानकारी चाहिए थी। हमने यहां चर्चा में घोषणा की कि कल

हमारी टीम जाएगी। दूसरे दिन हमारी टीम गई। वहां शपथ ग्रहण हो रहा था, उसके बावजूद हमारी टीम ने अधिकारियों के साथ बैठक की और दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे। राज्य सरकार के अधिकारियों को लेकर जिले में जाना पड़ता है इसलिए 14 से सब जिलों का दौरा बना। उनके अधिकारी बनाकर दे रहे हैं, हमने बनाकर दे दिया है। वहां दो दिन हमारी टीम के लोग रहे।

महाराष्ट्र के इतिहास को आप देखिए। आपको हमने उस दिन भी बताया था कि महाराष्ट्र में 2013-14 में एनडीआरएफ ने 1269 करोड़ की सहायता की थी और वर्ष 2012-13 में 1800 करोड़ रुपए की सहायता की थी। जब आपदा आती है तो इसमें राजनीति नहीं होती है। आपने इतिहास जरूर बनाया कि मंत्री ने जो इन्टरवीन कर दिया फिर उसे बोलना पड़ रहा है लेकिन आपदा की राहत पर राजनीति नहीं होती है। यहां हम और आप राजनीति कर लेते हैं, लेकिन आपदा में न आपकी सरकार ने राजनीति की है और न ही सरकार राजनीति करने जा रही है। आपदा के समय कोई राजनीति नहीं होती है। ...(व्यवधान) मैं यह भी बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में एसडीआरएफ में वर्ष 2013-14 में 567 करोड़ रुपया गया था लेकिन वह खर्च नहीं हुआ है। इस बार भी इसकी एलोकेशन 403 करोड़ रुपया है। मैंने वहां के रिलीफ कमिश्नर से बात की, मैं मानता हूं कि खर्च जरूर हुआ होगा लेकिन रिपोर्ट भेजने में आलस्य होता है। हमने वहां के मुख्यमंत्री से रात को कहा है, हो सकता है आज रिपोर्ट आ जाए।...(व्यवधान) आप कुछ समझिए, आप बिना समझे बोल देते हैं।...(व्यवधान) इस साल एसडीआरएफ का 3 करोड़ रुपया पड़ा है, हम इसे जल्दी भेजना चाहते हैं। इसके पीछे हम लगातार लगे हुए हैं। हम पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जब रिपोर्ट आएगी तो पूरी सहायता करेंगे। इसमें कोई राजनीति नहीं होगी, मैं ऐसा विश्वास आपको दिलाता हूं।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : I am not seeking any clarification or anything but the record should be straight.

Yesterday, Naiduji himself agreed that the Minister of Agriculture will come and he will intervene about Maharashtra drought. According to that, we requested him to reply on the drought. The hon. Minister is telling that we are doing politics on the issue. We are only seeking relief. What relief are you going to give to Maharashtra as also to flood-affected areas like Jammu and Kashmir, Odisha and other places. We are not against anything. You should not say that you had boycotted the House and that you were not present here. Yesterday, it was clarified and according to our request, the Minister himself agreed to reply.

Therefore, he should not say that he is doing some great obligation to us. It is his duty to reply whenever this House needs.

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण (नांदेड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। आज मुझे ऐसा लगा कि कल जो हाऊस में हुआ, उस पर आदरणीय मंत्री जी कुछ बयान देंगे। महाराष्ट्र के सांसदों ने यहाँ पर जो मुद्दे उठाये, बदकिस्मती से उस पर मंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने सिर्फ यह कहा कि हमने इतना पैसा यहाँ दिया, केवल सैद्धांतिक मुद्दों पर उन्होंने जवाब दिया है। कल मैंने जो मुद्दे उठाये थे, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा। मैंने कहा था कि रोज वहाँ पर कम से कम दस से बीस लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मेरा सवाल मंत्री जी से यह है कि आज तक तकरीबन चार सौ से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है, उन आत्महत्याओं को रोकने के लिए क्या वे कदम उठाएंगे?जो पैसा उन लोगों ने बैंकों से कर्ज लिया है, उनको वे वापस करने में असमर्थ हैं। इसलिए रोज़ तकरीबन 15-20 लोग राज्य में आत्महत्या कर रहे हैं। जो फीगर है, वह आज चार सौ से भी ज्यादा हो गयी है। यह चिन्ता की बात है। हम भी इस पर कोई राजनीति करना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र की तमाम पार्टियों- शिव सेना, भाजपा के लोग बैठे हैं, विदर्भ और मराठवाड़ा के सभी लोग इसमें शामिल हैं। मेरी आपसे गुज़ारिश है कि इसके संबंध में स्पष्टीकरण दें कि जो कर्जा उन्होंने बैंकों से लिया है, वह ऋण आप माफ करेंगे या नहीं, हम इसका जवाब आप से चाहते हैं।

SHRIMATI SUPRIYA SULE : Sir, I thank you and I appreciate the hon. Minister's intervention where he says that there is no politics in drought. I respect that and I appreciate the packages which the hon. Minister is suggesting for our Government. I think, the whole discussion is centered around humanitarian grounds and not about who is on which side. My only request to you is to take Ashok ji's point ahead. A delegation from Maharashtra met the hon. Minister two weeks ago regarding the milk prices in Maharashtra as well as the drought situation. Specifically if you see what kind of intervention the Government of India is doing to help the basic farmers in the drought situation and the milk growing farmers for whom the prices are rock bottom now. As usual Maharashtra has a wonderful production whether it is cotton, sugarcane or milk.

श्री राधा मोहन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद महोदय ने अभी आत्महत्या की चर्चा की है। कल कौन-कौन से सवाल उठाये गये थे, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने कल इंटरवीन किया था और मूल चर्चा

का उत्तर गृह मंत्रालय को देना था, उन्होंने विस्तार से इसका उत्तर दिया होगा। ...(व्यवधान) लेकिन अभी जो आत्महत्या का मुद्दा आपने उठाया, उसका उत्तर मैं विस्तार से दे रहा हूँ। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 2008 में 694 किसानों ने कृषि कारणों से आत्महत्या की थी। ...(व्यवधान) वर्ष 2008 में कुल 3802 किसानों ने आत्महत्या की थी। राज्य सरकार की रिपोर्ट था कि कृषि कारणों से 694 किसानों ने आत्महत्या की। इसी प्रकार से, वर्ष 2009 में 3141 किसानों ने आत्महत्या की थी, जिसमें से 572 किसानों ने कृषि कारणों से आत्महत्या की थी। यह मैं नहीं बता रहा हूँ, उस समय पता नहीं किसकी सरकार थी। ...(व्यवधान) यदि आप बहुत नहीं सुनना चाहते हैं तो आप एक वर्ष के आंकड़ों के बारे में तो सुन लेंगे। ...(व्यवधान) जैसी आपकी चिन्ता है, वैसी ही मेरी भी चिन्ता है। इसीलिए उस चिन्ता को मैं और मजबूत बना रहा हूँ। इस पर हम दोनों और मजबूती से चिन्ता करें। इसीलिए मैं इतने आंकड़े सदन के सामने रख रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ ताकि पूरा सदन इस विषय पर गंभीरता से सोचे। वर्ष 2013 में, अभी तक 2013 के आंकड़े आए हैं, वर्ष 2014 के आंकड़े नहीं आए हैं। वर्ष 2012 मे 3786 लोगों ने आत्महत्या की थी, जिनमें से 642 लोगों ने कृषि कारणों से आत्महत्या की की थी। यह जानकारी राज्य सरकार देती है। वर्ष 2013 मे 3145 लोगों ने आत्महत्या की थी, जिनमें से 407 लोगों ने कृषि कारणों से आत्महत्या की की थी। अब चाहे 400 लोगों ने आत्महत्या कृषि कारणों से की हो या बाकी 2700 लोगों ने अन्य कारणों से आत्महत्या की हो, कारण चाहे जो भी हो, पूरी आत्महत्या की चिन्ता करनी चाहिए। कारण अलग-अलग हैं और कृषि के कारणों से 400 एवं अन्य कारणों से 2700 लोगों ने आत्महत्या की। निश्चित रूप से सदन ने आज तक चिन्ता नहीं की, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, चिन्ता भी की और यह दौर भी चलता रहा, इसलिए अब हम और आप मिलकर ऐसी चिन्ता करें कि यह दौर रुके और आत्महत्याएं कम हों। इसके लिए हम सभी प्रयास करें, यही मेरी विनती है। आप पूरे दिन इस पर चर्चा कीजिए।...(व्यवधान) हम सभी को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we will take up item No. 19.

… (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदय, हम लोग यह पूछ रहे हैं कि आप क्या कदम उठा रहे हैं?...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: The hon. Minister has already replied on the issue. If you are not satisfied, then it is a different issue. What can I do for that?

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, they are not going to take any step in this regard. We are not satisfied with the reply of the hon. Minister. So, we are walking out.… (*Interruptions*)

16.52 hrs

At this stage, Shri Mallikarjun Kharge, Shri Rajesh Ranjan and some otherhon. Members left the House.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Mr. Deputy-Speaker Sir, umpteen number of times, this issue was discussed in the House at length..… (*Interruptions*) Sir, you have allowed them and what they have said has gone on record.… (*Interruptions*) ऐसा कमेंट नहीं करना। ...(व्यवधान) वापस आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते या दस साल के बाद आएंगे, आपको क्यों चिन्ता हो रही है। मेरा कहना है … (*Interruptions*)

Sir, an issue was raised and it is a very important issue. Please recall as to when this discussion was admitted, how much time we have spent on it, what was the practice earlier and how many hours we have spent on this issue. The Members who had given notice were not there and they came subsequently. Even then they made a suggestion yesterday that some Members including a former Chief Minister of Maharashtra wanted to make some valuable comments. So, the Government had agreed, the hon. Minister was here and he has responded to them. This reply may not be to their satisfaction. Sir, if they are going to be fully satisfied, then they will not be on that side, they will be joining this side.

My point is, the Government have sent a team. The hon. Minister has given the figures. They quoted some figures about the suicide of farmers. When the Minister started quoting figures of 2008, 2009, 2010, 2011 and 2012, it is unpalatable to them. When they raise a point, they must be able to hear the other

side also as well as the Government's reply. They cannot just say whatever they want, then accuse the Government, then walk out and then make slogans while walking out. This is not the way to do it.

They have been in power all these years. While they walk out, they may say something as they definitely have the right to say something but at the same time, going on repeating and then saying that they are not allowed to speak is not fair. I hope that they will realize it in future. If there is a debate, let it be a meaningful debate. Let there be a constructive debate. We do not want to politicalise it. In Maharashtra, till yesterday, their Government was there. Today, our Government is there. The Central Government and the State Government must join together and work together to address the problems of the farmers. That is the stand of the Government. There is no question of not taking the views of the hon. Members seriously.

16.55 hrs

(ii) Reported dilution of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up item no. 19.

Shri Sankar Prasad Datta.

SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): Respected Deputy-Speaker, Sir, all of us know that in the year 2005, after a long struggle by our country's downtrodden people, a new Act was brought in. On 5th September, 2005 the new Act known as the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act came into force. Though this Act was implemented poorly, this has brought some relief to the unemployed and the under-employed people of our country.

In a statement, our present Finance Minister said that under this legislation, 4.5 crore households have been provided an average of 45 days' work in 2013-14. So, now the downtrodden people of our country are getting food and work from this Scheme. But now-a-days we are seeing that MGNREGA is now being linked to how national resources should be used. The MGNREGA, however inadequate it may be, was a step in the right direction. It provides a share of national resources to create employment opportunities to the people of rural India, thus directly increasing the purchasing power of the rural poor of our country.

The aim of planning these projects is to meet the requirements of the village people, unlike plans to build infrastructure which primarily helps corporates. There is a wider impact which prevents wages from coming down below the legal level, thus preventing, at least in theory, gross exploitation of rural labour through dismal wages by the various sections of the rural elite. That is why the plan to scrap the Act has the backing of the representatives of the rural elite, the landlords and the big contractors.

In the year 2012-13, for MNREGA, an amount of Rs. 33,000 crore was spent. But in the beginning, Rs. 40,000 crore was spent towards MGNREGA. So, in the beginning the amount was Rs. 40,000 crore, but in the year 2012-13, it came down to Rs. 33,000 crore. From the period 2005, when it was started, to 2012-13, the number of people covered gradually increased. But the initial allocation of Rs. 40,000 crore was brought down to Rs. 33,000 crore in 2012-13. That is why we are saying that the UPA Government was not at all sincerely interested in implementing the MGNREGA.

Now, we have to see what is the NDA Government talking about this Scheme. We heard that on 4th August a meeting was held under the leadership of our Minister of Rural Development.

17.00 hrs

We know that under the MGNREGA at least 100 days work should be provided to the people of our country. It was not necessary that the people who have the quality to do better work, and the people who have the quality and technical efficiency are not required for the purpose of MGNREGA work. MGNREGA work can be done by any person. If I would like to do MGNREGA works, I may register my name, I would get the work and the MGNREGA guaranteed that at least 100 days work would be given. Now a days, this Act has now been diluted.

17.01hrs (Dr. Ratna De (Nag) *in the Chair*)

On 4th August, in a meeting, our hon. Minister of Rural Development has proposed that MGNREGA will no more be an Act but it would be a Scheme like other schemes. Today in the newspapers, I read that we have 60 schemes in our country. Our Government is thinking of bringing it down to 10 schemes. Is it a fact or not? I don't know. The MGNREGA was an Act but the Government is thinking of make it as a scheme.

We have 676 districts in our country. The Government is thinking that MGNREGA works will be executed in only 200 districts. It will be restricted to

only 200 districts. Our Government is thinking that these 200 districts consist of Scheduled Castes people, downtrodden people and the other districts are in good position. So, in those districts, MGNREGA works are not necessary. So, the Government is thinking about only 200 districts.

In 4th August meeting, our Minister of Rural Development proposed that - in the South, Kerala and Tamil Nadu, in the North, Rajasthan and Punjab, and in the West, Gujarat and Maharashtra – these six States do not needed MGNREGA works. If it is required later on, the same can be taken up. Those six States will go out from MGNREGA works. How would the poor people of those six States and 476 districts of our country live?

You can remember that some days back in many newspapers of our country, 28 eminent economists suggested and appealed to our hon. Prime Minister that MGNREGA works should not be diluted or curtailed because the downtrodden people of our country will be affected. Those 28 eminent economists are not from India; many economists are from abroad who love the people of our country written a letter to our Prime Minister. What is the actual position in our country? Madam, in these 200 districts, which have been chosen by the Central Government, maximum number of poor people is living. What is the exact percentage? If we see the share of India's poor people in these 200 districts, the share is 31.40 per cent. But in other districts, 68.60 per cent poor people are living. In those districts, are MGNREGA works not needed? The percentage of Dalit population in those 200 districts is 26.10, but in the other 476 districts, 23.50 percent Dalits are living. In households with no education, 30 per cent people are living in those 200 districts, but in the remaining 476 districts, 26 per cent of illiterate people are living.

What is the position of ST population in those 200 districts? The Government is saying that they will protect the ST people. But in those 200

districts, 11.70 per cent ST people are living and in the remaining 476 districts, 9.60 per cent ST population is there.

In respect of participation of households in rural employment guarantee work, only 28.40 per cent people are participating in 200 districts, but in the balance 476 districts, 22.80 per cent people are participating in this work whereas the Government is saying that this programme is not needed in those districts because no poor people are living there.

In respect of share of income, 12 per cent income is coming from those 200 districts and 14 per cent income is coming from the remaining 476 districts. There are five categories of poor people in our country. The lowermost category is the poorest of the poor and 22 per cent of such people are living in 200 districts and 19 per cent are living in 476 districts.

So, why is the Government thinking of diluting MGNREGA? From the figures that I have quoted here, it is crystal clear that there are so many poor people, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and illiterate people are living in the remaining 476 districts and they are in need of this rural employment guarantee work. In the month of February this year, it was finalised by the Government that in the year 2014-15 around 227 crore man days of work would be there. This is slightly higher than the figure of 219.72 crore man days of work created in 2013-14. This 227 crore man days of work required an allocation of Rs. 61,000 crore. But what exactly was allocated in the Budget? The Government allocated only Rs. 33,000 crore in this year's Budget. What is the reason for this?

The Government is giving statements again and again that they are not going to dilute MGNREGA and they are in favour of the poor people of our country. The Prime Minister is saying that the Government is in favour of the poor. But what exactly is required for the poor people of our country? The Government finalised that Rs. 61,000 crore is required, but only Rs. 33,000 crore

has been allocated in the Budget for MGNREGA work. I am from a tiny State of Tripura. In our State, in the last three years, a record has been established. In the last three years, throughout the country, Tripura stood first in doing MGNREGA work. In our State 86 to 88 days work has been done under MGNREGA. Madam, 98 per cent expenditure has been placed before the Central Government. But here, it is a sad of affairs that in the year 2012-13, in the labour budget, the Central Government approved Rs.1204.88 crore. But in that year, the Centre's share was Rs.768.90 crore; the State's share was Rs. 153.85 crore in our State. Tripura could manage 87 days' work in that year. But, what was the national average in that year? In that year, our national average was only 42 man-days. In the year 2013-14, the approved labour budget was Rs. 1354.66 crore. The Centre's share in that budget was Rs. 943.66 crore and State's share was Rs. 163.72 crore. In that year also, that in the last year, 88 man-days was created by the State Government under MGNREGA. But the national average was 44 man-days so that Tripura could stood first in 2011, 2012 and in 2013 also. It is a sad of affairs that though in the last year Tripura has done a good job to give work to the poor people and 98 per cent expenditure has been done but this year the labour budget approved by the Central Government is Rs.1406.94 crore but till 31st October, near about Rs. 200 crore have been allocated and some days ago Rs. 373.77 crore has been sanctioned for the State Government. This year, up to the month of November, only 22 man-days could be created in our State. But, the national average is 31 days. So, why is this being done by the Central Government with the State of Tripura? Is it a correct path for the Central Government?

While we are doing a good job in our State, it is necessary for the Central Government to provide money, to provide jobs to the downtrodden people of the State, but the Central Government has failed. I would say that the Central Government is not interested to run this scheme, to provide jobs to the people of the State and the people of the country. Not only Tripura, we have seen that in the

case of other States also. Last year, Bihar got Rs. 624 crore at one time and at another time they got Rs. 532 crore. But this year, up to November, they got only Rs. 256 crore. But in some cases while Tripura Government is getting less than 40 per cent from the earlier year from the Labour Budget that was finalised in the month of February. But in the case of other States this percentage is comparatively good. Till 20th October, the Government of Tripura got Rs. 180 crore up to that time it was 27 per cent. Now, it is below 40 per cent. But in case of other States it is quite good. The State of Andhra Pradesh received up till now 87 per cent; Madhya Pradesh received 84 per cent; Chhattisgarh received 82 per cent; West Bengal received 75.6 per cent; and Kerala received 46.58 per cent. We are happy that they are getting this money. But why is it not happening in case of Tripura? Why the Central Government is not interested in giving sufficient money to Tripura, Bihar and other States? So it is clear that the Government is interested to dilute MGNREGA. A proposal is being coming from the Ministry of Rural Development to make MGNREGA a Scheme and not an Act.

I would like to say here that if BJP led NDA Government sincerely wants to bring good days in this country, they should keep this Act as an Act and not as a Scheme. I would further like to say that the amount under the MGNREGA should be increased.

With these words, I conclude. Thank you.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदया, माननीय सदस्य बोल रहे थे, आँकड़े भी दे रहे थे, वे एक प्रदेश के बारे में ज्यादा कह रहे थे और अन्य प्रदेशों के सम्बन्ध में भी उदाहरण दे रहे थे। मैं अपनी पार्टी के नेताओं को धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने मुझे पहले वक्ता के रूप में अवसर दिया है।

पन्डित बाँचे पोथिन लेखा।
कबीरा बाँचे आँखिन देखा।।

हिन्दुस्तान में एक तो ऐसे लोग हैं, जो किताब पढ़कर बोलते हैं, दूसरे आँख से देखकर अनुभव से बोलते हैं। जो अनुभव आधारित ज्ञान है, वही परफेक्ट नॉलिज है। किताब के ज्ञान को कभी हम पूर्ण ज्ञान नहीं मानते हैं। इसलिए मैं इस विषय पर जब बोलूँगा तो सभी माननीय सदस्यों से कहूँगा कि "जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण माँजत रहिए, दर्पण में लागा काई तो दरस कहाँ से पाई"। हम इस संसद में जब बैठते हैं तो बात करने लगते हैं, यह हिन्दुस्तान न केवल मजदूर का है, न केवल किसान का है, न केवल व्यवसायी का है, न केवल उद्योगपति का है, न केवल विद्वान का है, न केवल अनजान का है, यह देश समग्र भारत में बसने वाले नीचे से ऊपर तक के सभी लोगों का है और इस धरती पर, इस मिट्टी पर सबको समान अधिकार है। यह भारत देश है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी जब कहते हैं कि "सबका साथ सबका विकास" तो उसमें नीचे से ऊपर तक सबका सहयोग चाहिए, सबका विकास चाहिए, समग्रता में चिन्तन चाहिए और हम समग्रता में चिन्तन करें।

अभी त्रिपुरा के माननीय सदस्य बोल रहे थे, 15वीं लोक सभा में विख्यात नेता, मार्क्सवादी पार्टी के 15वीं लोक सभा में नेता थे, पुराने मार्क्सवादी नेता बसुदेव आचार्य जी, वे कृषि सम्बन्धी स्थायी समिति के अध्यक्ष थे। मैं पाँच वर्ष तक लगातार उनके साथ कृषि समिति का सदस्य रहा। हमने सम्पूर्ण भारतवर्ष में दौरा किया। देश भर के किसानों के सभी दलों के संगठनों को बुलाया गया। गैर-सरकारी संगठनों को बुलाया। किसान क्षेत्र में जो एन.जी.ओ. काम करते थे, उनको बुलाया। अभिलेख है कि भारतवर्ष के सभी किसान संगठनों ने एक स्वर से माँग की थी कि अगर किसानों का हित चाहते हैं और खेती की तरक्की चाहते हैं तो इस मनरेगा को बन्द कर दीजिए। यह किसान की दृष्टि है। मैं बोलूँगा, क्योंकि, मैं किसान हूँ। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। मैं केवल चुनाव लड़कर लोक सभा में नहीं आ गया हूँ। मैं दो बार ग्राम पंचायत का प्रधान रहा हूँ। एक बार ब्लॉक का प्रेसीडेंट रहा। एक बार जिला परिषद का अध्यक्ष रहा हूँ। तीन बार मैं विधान सभा का सदस्य रहा और तब पाँचवीं छठवीं बार संसद का सदस्य हूँ। मैं गाँव की गली से चला हूँ, खेत की मेढ़ से चला हूँ। अपने हाथ से हल चलाया, कुदाल चलाया, खुरपी चलाया, हँसुआ चलाया, धान के

विचरे उखाड़े, धान की रोपनी की, अपने हाथ से कटनी की, अपने हाथ से सिर पर उस धान के बंडल का बोझा भी ढोकर खलिहान तक लाया। मैंने किसान के दर्द को देखा है, मेरे पूर्वज भी किसान थे। इसीलिए मैंने कहा कि - दरसन करना चाहिए तो दरपन मांजत रहिए, दरपन में लागा काई तो दरस कहाँ से पाई। मनरेगा योजना क्यों बनी? किसी चीज़ का मूल्यांकन करें, आज हिन्दुस्तान में क्या हमारे साथी लोग कभी इस बात की समीक्षा करेंगे कि सन् 1951 की जनगणना के मुताबिक खेतिहर मज़दूरों की संख्या 28.01 प्रतिशत थी और 2011 में 54.09 प्रतिशत हो गई है। आखिर यह संख्या क्यों बढ़ी, किसने बढ़ाई? जो किसान थे, वे मजबूर होकर खेतिहर मज़दूर बन गए। जितना 26 प्रतिशत किसानों की संख्या में कमी हुई है, उतना ही 26 प्रतिशत खेतिहर मज़दूरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब यह है कि यह आँकड़ा स्पष्ट करता है कि किसान जितना कम हुआ है, उतना खेतिहर मज़दूर बना है। खेतिहर मज़दूर का मतलब क्या है? जिसको मार्क्सवादी लोग सर्वहारा कहते हैं, 'Dictatorship of the proletariat', यह सर्वहारा का मतलब क्या है? मैं कभी कभी साधु-संतों की संगति में बैठता हूँ, शब्दों का विश्लेषण करता हूँ तो सर्वहारा का मतलब होता है जो सब कुछ हारा हुआ हो। तन का हारा, मन का हारा, धन का हारा, विद्या का हारा, बुद्धि का हारा, पेट में भरपेट रोटी न हो, तन पर भरतन कपड़ा न हो, पाँव पसारकर सोने के लिए परिवार भर को मकान न हो, वह है सर्वहारा। मैं पूछना चाहता हूँ कि सर्वहारा का नारा देने वाले जितने लोग रहे, उनके राज्यों में सर्वहारा की कितनी उन्नति हुई और कितने ऊपर गए और उसमें से कितना नेतृत्व पैदा हुआ जो केन्द्रीय स्तर से लेकर प्रांतीय स्तर तक आया। नेता, नीति और नीयत। नेता भी दुरुस्त हो, नीति भी साफ हो, लेकिन नीयत खराब हो तो नेता के देखने से और नीति के रटने से कुछ नहीं मिलेगा। आज भारत का सौभाग्य है कि भारत को जो प्रधान मंत्री मिले हैं, वे नेता भी सही हैं, नीति भी सही है और नीयत भी साफ है। गाँव गरीब मज़दूर किसान, मिलकर बनाएँगे हिन्दुस्तान, यह स्पष्ट दृष्टि है। लेकिन देखने की बात है जैसा मैंने पहले कहा कि आपकी दृष्टि जैसी होगी, वैसा आप देखेंगे, जैसी दृष्टि मेरी होगी, वैसा हम देखेंगे।

सभापति महोदय, सब कुछ की अदला बदली हो सकती है लेकिन दृष्टि की अदला बदली नहीं हो सकती है क्योंकि वह तो अंतर से प्राप्त होती है और अंतर्मन की दृष्टि अलग होती है, वह कोई दे नहीं सकता, किसी से उधार ले नहीं सकता। भले कोई विद्वान हो जाए, आँकड़े दे दे, किताबों में से जाल निकाल दें, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान में काम देने के लिए किताब में कहते हैं कि इतना दो। केवल हिन्दुस्तान अकेले त्रिपुरा नहीं है। केवल हिन्दुस्तान अकेले तमिलनाडु, बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं है। हिन्दुस्तान की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति अलग अलग है।

मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ लगे बिहार का रहने वाला हूँ। चाहे हरियाणा, पंजाब या जहाँ का भी किसान हो, जहाँ तीन फसला खेती है, वह खेत 12 महीनों में से मुश्किल से डेढ़-दो महीने खाली रहता है, नहीं तो हमेशा फसल रहती है। मिट्टी कहाँ काटेंगे? कहाँ से मिट्टी काटने देंगे? हम अपनी फसल कटवाकर दे देंगे। आज मेरे यहाँ बिहार में, मेरी ही पंचायत में मनरेगा वाले जाते हैं और किसान को अपने खेत में मिट्टी नहीं काटने देते हैं। ये कहते हैं कि 60 परसेंट मिट्टी का काम करो और 40 परसेंट पक्का काम करो। कागज़ में करो, चाहे हो या न हो। कागज़ में करो तो कागज़ में लिखो, कागज़ में अंगूठा छापो, कागज़ में लो, कागज़ में भुगतान करो, चाहे किसी के हाथ में जाए या न जाए। खाता न बही, और मनरेगा का एजेन्ट जो कहे, वह सोलह आना सही। सरकारी अफसर जो कहे, वह सोलह आना सही। यही तो हो रहा है। आप जो बात यहाँ करते हैं, मैंने उसको देखा है। खेतों में गेहूं लगे होते हैं और उसमें से मिट्टी काट कर आज प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में डाल दी जाती है। किसानों की मिट्टी गयी, गांव में सड़क बनी, यह बड़ी अच्छी बात है। लेकिन, आज खेती केवल खेती नहीं है। मेरे दादाजी, पिताजी खेती करते थे, तो वे खेती करते थे। पर, आज जब मैं खेती करता हूं या मेरे बच्चे खेती करते हैं, तो उनकी खेती का व्यावसायीकरण हुआ है, क्योंकि उसमें पूंजी का इंवेस्टमेंट होता है। उसमें खाद डालते हैं, बीज डालते हैं, पैसे लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, उत्पादन बढ़ाते हैं, उत्पादकता बढ़ाते हैं। उससे किसी तरह अपनी जीवन और जिंदगी चलाते हैं और उससे दो पैसे कमाते हैं तो बच्चों को पढ़ाते हैं, बेटी का विवाह करते हैं, बाप का श्राद्ध करते हैं। यही तो हमारी पूंजी है। हमारा रिज़र्व बैंक तो हमारा गेहूं है। रिज़र्व बैंक, धान है। रिज़र्व बैंक, ज्वार-बाजरा है। रिज़र्व बैंक, सरसों है। वह फसल हमारी रिज़र्व बैंक है जो हमारे घर में बोरी में बंद है, जिसे जब चाहते हैं तो ले जाते हैं, बाजारों में बेचते हैं और पैसा लाकर अपना काम करते हैं, वह है रिज़र्व बैंक।

इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। जब योजना आयोग का रूपांतरण हो सकता है तो यह मनरेगा और फूड सिक्योरिटी का रूपांतरण क्यों नहीं हो सकता? क्या यह परम ब्रह्म परमेश्वर का अवतार है? क्या ये भगवान के अवतार हैं कि इनके रूप नहीं बदले जा सकते हैं? जब योजना आयोग का रूपांतरण हो सकता है, उसका ग्रामीणीकरण हो सकता है, उसका लोकतंत्रीकरण हो सकता है, जब जनोन्मुखी बनाने की योजना चल सकती है, जब देश में एक नयी राह बनेगी तो पुरानी राह पर चलने वाले को थोड़ी तक़लीफ जरूर होगी। यह शिखर से लेकर सतह तक की बात है। पहले योजना शिखर से लेकर सतह तक बनती थी। एक पाइप लगता था, जिससे पानी नीचे तक जाता था। उसके साथ-साथ दूसरा पाइप लगता था, जिसके मार्फ़त पानी वहां जाने से पहले रिटर्न होता था और जगह-जगह टोंटी लगे होते थे और सब

जगह वह पानी गिरते-गिरते शिखर से चल कर सतह में, ज़मीन में गए बगैर फिर लौट कर शिखर तक आता था और जगह-जगह वह पानी गिरता था। ये योजनाएं किसलिए बनीं थीं? योजना चलाओ, गरीबों को मूर्ख बनाओ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाओ, उनको कहो कि सब कुछ मिलेगा, इसके नाम पर वोट बटोरो और शिखर से लेकर सतह तक भ्रष्टाचार का जाल बिछाओ। शिखर का भ्रष्टाचारी आएगा, सतह तक भ्रष्टाचार ले जाएगा, और जब चुनाव आएगा तो भ्रष्टाचारी-भ्रष्टाचारी एक बन जाएंगे, सारे भ्रष्टाचारी मिल जाओ, मुझे वोट देकर सत्ता तक पहुंचाओ, हम भी लूटें, तुम भी लूटो, लूट-बांट कर खाओ, देश को रसातल में पहुंचाओ। ये जो भारत की योजनाएं बनती रहीं हैं, इन योजनाओं से अब देश को मुक्ति पाने का समय आया है, भारत के रूपांतरण का समय आया है, काया-कल्प का समय आया है। श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का काया-कल्प होने जा रहा है, भारत का रूपांतरण होने जा रहा है। इसलिए कुछ खलबली जरूर मचेगी।

मैं अपने उन साथियों से कहना चाहता हूं कि आखिर इन पैसों से गरीबों को काम देना है न? अगर सभी गांव की गलियों का पक्कीकरण कर दिया जाता, खड़ंजा लगा दिया जाता, पी.सी.सी. में ढाल दिया जाता तो आज वहां स्थिति अच्छी होती। हमारे बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, असम में चाहे जहां कहीं भी बाढ़ प्रभावित एरिया हैं, चार महीने उन गांवों की औरतों को जो तकलीफ़ होती है, उस तकलीफ़ का अहसास वही करेगा, जिसे एक बार औरत में जन्म लेकर उस इलाके में जाना पड़ेगा। इसके बिना वह उस दर्द को कैसे समझेगा? चार महीने तक घुटने भर कीचड़ है, कहीं निकलने का रास्ता नहीं है, उस समय उनको शौच लग जाए तो वे उस घुटने भर कीचड़ में कहां जाएं, किधर शौच को जाएं? वे अपने पाखाने को पेट में बारह घंटे तक सड़ा कर रखती हैं, इसलिए हिन्दुस्तान की माताएं बीमार होती हैं। जब माताएं बीमार रहेंगी तो बच्चे भी बीमार और विकलांग पैदा लेंगे। इसलिए हिन्दुस्तान में विकलांग बच्चों की संख्या ज्यादा है। आपने ग्रामीण भारत का रूपांतरण क्यों नहीं किया? अगर गांवों को खुशहाल बनाना था तो इन पैसों को क्यों नहीं लगाए? आपने नारा लगाया कि शौचालय बनाएंगे, शौचालय बनाएंगे। क्या कहा? आधा देगा पी.एच.ई. और आधा देगा मनरेगा। बताइए, कौन सी योजना बना रहे हैं? खिचड़ी बनाओ, चावल तुम्हारा, दाल मेरी, तुम चावल लगाते जाओ, दाल हम न देंगे, खिचड़ी कैसे बनेगी, तो आप खा लेना। अगर मनरेगा के कुल पैसे को एक काम में लगा दिया जाता कि स्वच्छ भारत का निर्माण करना है, सर्व स्वच्छता अभियान, श्रीमान् अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जो चलाया गया था, उस सर्व स्वच्छता अभियान के तहत अगर हर घर में शौचालय बनाने के लिए मनरेगा की राशि को लगा दिया गया होता, तो आज गांव से गंदगी मिट गयी होती। यह क्यों नहीं किया गया, उस पैसे को क्यों नहीं लगाया

गया, क्योंकि हमारी नीयत नहीं थी, हमारी आंख में आंसू थे, लेकिन दिल में दर्द नहीं था। हमारे मुंह में वाणी थी, लेकिन हमारे हृदय में करूणा नहीं थी।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने अंतिम मानव की कल्पना की थी, अंतिम मानव जब खुशहाल होगा, गांधी जी ने भी उसकी कल्पना की थी। अंतिम मानव कौन? हिंदुस्तान के गांव में बसने वाला, शहर में बसने वाला, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाला, गली में रहने वाला, मेहनत मजदूरी करने वाला, उसके उत्थान के लिए आपने योजना क्यों नहीं बनाई? ...(व्यवधान) मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इन बातों पर सोचें। ...(व्यवधान) मैं भी गांवों में घूमता हूं, किसानों के बीच में जाता हूं, खेत-खलिहान में जाता हूं, सब जगह मैं इस बात को देखता हूं। ...(व्यवधान) सरकार को अगर चिन्तन है और सरकार इसे करना चाहती है तो यह क्यों नहीं होगा?

मैं हाथ जोड़कर किसान की तरफ से, गांव के गरीब किसान, मजदूर, पिछड़े दलित की तरफ से मांग करूंगा। आजाद भारत में जितनी योजनायें चलायी गयीं, उन सभी योजनाओं का मूल्यांकन होना चाहिए। जैसे एक बिल लाकर नब्बे या सौ पुराने बिलों को निरस्त कर दिया गया, उसी तरह एक बिल लाकर सब योजनाओं को निरस्त कर दें और नये सिरे से भारत में नई योजना का निर्माण करें। जो जनता के लिए हो, देश के लिए हो, भारत के लिए हो, गांव, गरीब और किसान के लिए हो।

संयोग से महात्मा गांधी का नाम इसमें जोड़ दिया गया, यह नरेगा से हो गया मनरेगा। हमारे यहां किसान लोग कहते हैं कि मनरेगा का मतलब है कि देश का किसान मरेगा, उसका नाम है मनरेगा। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि सारी योजनाओं पर पुनर्विचार हो। केवल इसलिए कि हमारा नाम चले, हमारे खानदान का नाम चले, हमारे रिश्तेदार का नाम चले, बाप बेटा दलाल और बैल की कीमत बारह आना। क्या इसलिए योजना चलाई जाए? योजना का मतलब है कि वह गांव के लिए हो, किसान के लिए हो, मजदूर के लिए हो, पिछड़े के लिए हो, दलित के लिए हो, छात्र के लिए हो, नौजवान के लिए हो और समग्रता में चिन्तन हो। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाना चाहिए। इसकी समीक्षा हो, मूल्यांकन हो, उपयोगिता पर चिंतन हो और आवश्यकता के अनुसार इसका रूपांतरण किया जाए। समय बदलेगा, भारत की जनता चलती रही है।

सन् 1967 में डॉ. राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में हम लोगों ने नारा दिया था, पंडित दीन दयाल उपाध्याय और डॉ. लोहिया मिलकर चले थे, तब हमने नारा दिया था कि कांग्रेस हटाओ और देश बचाओ। जय प्रकाश जी, आप सन् 1967 में बच्चे रहे होंगे या मां की गोद में खेलते होंगे, आप क्या जानेंगे हुक्मदेव

नारायण के उस संघर्ष को, जिसके कारण हुक्मदेव नारायण लड़ा है। ...(व्यवधान) पसीना बहाये कोई और, मालपुआ खाए बिहार में कोई।

सन् 1967 में डॉ. लोहिया ने कहा था कि कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ। सन् 1967 में लोहिया जी ने कहा, 1967 से लेकर आज तक चलते गए। एक बार डॉ. लोहिया ने मुझे कहा था कि हुक्म चंद तुम घबराना मत, मेरी राह पर चलते जाना। एक न एक दिन आएगा, हिंदुस्तान के किसी पिछड़े वर्ग का बेटा निकलेगा, जो समग्र भारत का नेता होगा। समग्र समाज का उसे समर्थन मिलेगा और एक न एक दिन भारत में कोई पिछड़े का बेटा, भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। उस दिन कांग्रेस का जड़-मूल से सफाया होगा। डॉ. लोहिया का वह सपना आज साकार हो गया है। नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर लोहिया का सपना साकार हो गया है। हम क्या करते रहे हैं, नाम लिया लोहिया का और काम उनके आचरण के विरुद्ध किया है। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि मूल्यांकन हो, आत्मचिंतन हो, समीक्षा हो, हजारों रुपए लगे, कई हजार रुपए लगाए गए, उन हजारों रुपए से योजनाएं बनाई जाती हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। एक योजना बनाइए और उसमें पैसा लगाइए ताकि हर खेत में पानी जाए। हर खेत को पानी और हर हाथ को काम, यह सपना साकार हो। अगर योजना बने तो किसी एक योजना की तरफ चलना चाहिए। यह नहीं कि हम आंख मूंद कर चलें।

मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले आपसे प्रार्थना करूंगा कि तीन तरह के लोग होते हैं। एक होता है - आगे देखूं, दूसरा होता है - पीछे देखूं, तीसरा होता है - बगल देखूं। आज़ादी के बाद जितनी सरकारें देश में आईं, वे सब बगल देखू रही हैं, बगल वाला क्या करता है, अमेरीका कैसे चलता है, इंगलैंड कैसे चलता है, जापान कैसे चलता है। हिन्दुस्तान में किसानों को चाहिए कि खेतों में 'जाय पानी', तो हमने नारा लगाया कि खेती करो जापानी। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मनरेगा योजना पर संसद में जो बहस हुई है और बहस हो रही है, हमारे साथी उस पर अपना विचार देंगे।

अंत में केवल मैं यही निवेदन करूंगा कि योजना का स्वरूप, योजना की दिशा और योजना की गति, इन तीनों की समीक्षा हो, उसका मूल्यांकन हो, उसका सही विश्लेषण हो। उसका विश्लेषण कौन करे? एक विश्लेषण योजना बनाने वाले शिखर पर करते हैं और एक विश्लेषण सतह पर होता है। सतह का विश्लेषण करने वाले इधर हों या उधर हों, ऐसे बहुत से लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं। जयप्रकाश जी, समझिये जो समाजवादी धारा से निकल कर भाजपा में आए हुए हैं वह डॉक्टर लोहिया के साथ वाले समाजवादी हैं, किसी और नेता के साथ वाले समाजवादी नहीं हैं। वह पिछलग्गू समाजवादी नहीं हैं। हमारे डॉक्टर लोहिया ने जो कहा था, उसी के आधार पर मैं आज यहां बोल रहा हूं।

इसी जगह वर्ष 1963 में डॉक्टर लोहिया ने बहस करते हुए, तीन आना बनाम तेरह आना का बहस चलायी थी, उससे पंडित नेहरू भी हतप्रभ हो गए थे और उनकी सरकार की चूलें भी हिल गई थी। आज श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो एक सपना देखा है, उसे साकार करने के लिए, भारत के रूपांतरण के लिए, गावों को खुशहाल बनाने के लिए, गरीब को खुशहाल बनाने के लिए, हिन्दुस्तान में सबके हाथ को काम मिले, सबको रोटी मिले, सबके तन पर कपड़ा हो, सबको मिले मकान, यही है हिन्दुस्तान। हम समाजवादी आंदोलन में नारा लगाते थे - मांग रहा है हिन्दुस्तान, रोटी कपड़ा और मकान। नरेन्द्र मोदी जी आए हैं, वह भी कहते हैं कि हिन्दुस्तान को चाहिए - रोटी, कपड़ा और मकान। उस सपना को साकार करना है तो कांग्रेसी हटाओ और देश बचाओ। कांग्रेस हटाया, देश बचाया तो कांग्रेस ने जितनी योजनाएं चलायी थीं, उन सभी का बंडल बांध कर होली जला दें, उनको राख बना दें और नए भारत का निर्माण करें। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The next speaker is Shri K. H. Muniyappa.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing else will go on record.

(Interruptions) ... *

* Not recorded.

SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Madam, Chairperson, thank you very much for giving me an opportunity to speak on the issue of MGNREGA. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, it is not going on record. Only Shri Muniyappa's speech will go on record.

(Interruptions) …[*]

SHRI K.H. MUNIYAPPA : I would like to share that MGNREGA is in the name of Mahatma Gandhiji, which the UPA Government had started with an Act in 2005. In 2006, 200 districts established this programme. Subsequently, in 2007 and 2008, the entire country with more than 650 districts extended the programme. It is being implemented properly. Those who are below poverty line like labourers, small and marginal farmers have no work for their livelihood during the summer time. Keeping this in view, under the able guidance of Shrimati Sonia Gandhi and the then Prime Minister Dr. Manmohan Singh, a deep study was done by the UPA Government and we have extended this programme to whole country and it is being implemented well. In 2012-13, a substantial amount of Rs. 30,000 crore was allocated and, before the end of the UPA Government, we have provided Rs. 33,000 crore for this programme. Under the programme, every Panchayat can draw up its own plan. The Panchayats and Gram Sabhas will decide the type of works to be undertaken under the programme and, accordingly, when the States formulate the plans and send them to the Central Government, they are sanctioned.

The number of people who are below poverty line and who are without food is more than 37 per cent in the entire country. Keeping the motto, "Live and let live", the UPA Government has started this programme.

Recently, the BJP-led NDA Government have planned to reduce the allocations to this programme. They have given only Rs. 1,000 crore extra this

[*] Not recorded.

year as compared to the previous year's allocation. They are also planning to dilute and dismantle this programme. On one occasion, the hon. Minister said that they were not diluting this programme. He explained it by saying, "We cannot dilute this MGNREGA programme. NDA will further improve MGNREGA." This is what Chaudhary Birender Singh has said, who was earlier on this side and now he is on that side. Practically, they are going to dilute this programme.

I would like to share what some eminent luminaries and economists have said. They have shared their anguish against the steps that this Government was going to take. Mr. Zimmermann of the University of Michigan said, "The programme, when properly implemented, would arrest the distress." Similarly, a study done by Clement Imbert of Oxford University shows that the villages with early access to the programme have less temporary outmigration to the urban sector. These important people have mentioned these things. The People's Action for Employment Guarantee met the hon. Prime Minister on 8th October 2014 and submitted a memorandum signed by 200 eminent citizens. They have appealed to him that in no case this programme should be diluted and that it should be given more importance. It is because it is the people's programme. It is the common people's programme and most of the people are below poverty line and the agricultural labourers, the small farmers and the marginal farmers are below the poverty line. I cannot understand what is behind this Government's thinking to dilute this programme. I urge upon this Government to increase the job and give more money for this programme for creating the infrastructure. Again, they are planning. Earlier, it was 60:40, that is labour oriented is 60 per cent and the infrastructure is 40 per cent. Now, they are diluting it to 51:49. More than two crore population are suffering from this. While they are reducing the labour, the affected people are more than two crore.

There is another important area which I want to tell in this House. They have provided work to the 8.3 crore population in 2014 with a balance of 2.3 crore

population. Unemployment has increased in 2014. The demand is 10.6 crore households that is who have applied for work. They made the provision only for 8.3 crore. When our Government was there, the demand was 10.6 crores. We have provided to the 9.8 crore households. This is the programme. The left out household is 1.3 crore and now the left out household is 2.3 crore. This is the difference between the NDA Government and the UPA Government. I think hon. Minister will take note of all these things and will try to correct these things. Otherwise, the people of this country cannot tolerate you. Because of magic, you have made to get into the power.

I would like to tell the hon. Minister this. On the birthday of Mahatma Gandhi that is 2nd October, 2014, our Prime Minister started to clean the nation. I think media has made so much of this well established programme. Where is the money? Where is the programme? Have you given the money to make this one to clean the country? The UPA Government has given money for the purpose of Jawaharlal Nehru National Urban Renewable Mission in the cities and towns. We have given thousands and thousands of crore of rupees. This is the practical thing where we have given the money. This is given to see that to provide drinking water, roads and all other facilities are provided. This is the practical thing that we have done at the time of our Government.

I have another most important thing which I would like to tell. In the name of Mahatma Gandhiji, we have started this programme but they have not given money for any one of the programme which they have announced. They have given only assurance.

There is another thing that is Jan Dhan. Jan Dhan is not a new thing. It was started at the time of Indira Ji's time. Abolition of privy purses, nationalisation of banks, allow the poor people, the small and marginal farmers into the banks are the things done by our Government. This programme was not only for the landlords. After that, UPA Government has started the no-frill

account. What is no frill account? Without paying a single paisa, the bankers should go to the villages and rural huts. More than 80 to 90 percent in the villages were enrolled through the Aadhar cards. They are given employment to the people directly in MGNREGA. This is the programme given by the UPA Government. It has been named as Jan Dhan Programme. What is 'Jan Dhan'? What is the programme? They have started the programme when more than 80 per cent work is over. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair and conclude.

… (*Interruptions*)

SHRI K.H. MUNIYAPPA : Under the Aadarsh Gram Programme, the gram will become orphan now. Neither the State Governments nor the Central Government nor the MPs will be able to take care of the village. If you ask an MP to take up a village under Aadarsh Gram Programme, on that day, that village will become an orphan.

I would like to suggest one thing. If they really want to make an Aadarsh Gram, if they want to make improvement in the villages and panchayats, we had started a programme under the Rural Development Ministry. We should not sanction a house without a toilet. That is the programme. If they take care of this programme and implement properly under the rural development, then only we can have an Aadarsh Gram. For this purpose, they can come with another programme.

In 1991-92, when Shri Narasimha Rao was the Prime Minister, it was he who started the MP Fund for the benefit of the villages, where it is required badly. We had increased this amount up to Rs.5 crore. If you are to really develop the villages and gram panchayats as Aadarsh Gram, you give extra money for this purpose either in the Budget or to the MP Fund, then only this programme will be

implemented. Otherwise, it will be difficult to implement it. मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, आश्वासन देने वाले लोग ज्यादा हैं, घोषणा करने वाले लोग ज्यादा हैं, लेकिन कहकर काम करने वाले लोग बी.जे.पी. सरकार में कम हैं।

SHRI V. ELUMALAI (ARANI): Madam, I thank you for the opportunity given to me to participate in the discussion on the working of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, which guarantees right to a minimum of 100 days work to rural poor. It aims to ensure livelihood security in rural areas by providing at least 100 days of wage employment in a financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work.

This Programme was launched in 2006 and it had come into force in 200 backward districts of the country. It is a legal entitlement for the rural poor. This System was hailed by the Government as "the largest and most ambitious social security and public works programme in the world". In its World Development Report 2014, the World Bank termed it a "stellar example of rural development". But what is happening on the ground is quite the opposite and there are many problems in the implementation of this scheme.

Poverty alleviation measures in rural areas have a long history in India. During the last three decades, the Government launched major schemes like Jawahar Rozgar Yojana, Employment Assurance Scheme, Food for Work Programme, Jawahar Gram Samridhi Yojana and Sampoorna Grameen Rozgar Yojana that were fore-runners to Mahatma Gandhi NREGA. Unlike the previous programmes, the Mahatma Gandhi NREGA guaranteed employment as a legal right. MGNREGA is an important step towards realization of right to work. It is expected to enhance people's livelihood security on a sustained basis, by developing economic and social infrastructure in rural areas. One of the most distinguishing features of MGNREGA is that it empowers the citizens to play an active role in the implementation of the employment guarantee schemes.

However, there are various problems reported from the field-level in the implementation of this scheme. To begin with there are complaints about non-issuance of job cards to those who demanded them.

The operational guidelines of MGNREGA detail a household as a nuclear family, comprising of mother, father and their children. In addition, a household refers to a single member family. There is still a lot of confusion about this definition. Our country has historically followed the system of joint families and the present practice of MGNREGA will put the joint families in a disadvantageous position.

There are reports that the authorities deny registration to single woman headed households and physically challenged persons. There are also reports that there is a lot of discrimination on the basis of caste. These are to be removed if this Scheme is to be made a success.

There are some States where even now the application forms are being charged in clear violation of the guidelines which state that the application forms can be had even on a plain piece of paper. Another general problem is the absence of the system of issuance of receipts to applications. This happens due to lack of awareness. But receipts are very crucial because this is a proof of having worked which would entitle him to claim wages.

MGNREGA provides for facilities for safe drinking water, shed for children. It assures periods of rest and also provides for first aid box at the worksite. But contrary to this, cutting across all the States what we find is that these facilities are not provided at any of the sites. The familiar site in every place is that small children are left unattended in the heat. As a consequence, women are hesitant to bring their children to worksites.

Another problem is of contractors. Contractors are becoming a threat to MGNREGA. Private contractors are finding their way slowly into the MGNREGA system. But the Act very clearly shows that the contractors are banned and no contractor is permitted in the implementation of the projects.

Seldom have we found muster rolls at the workplaces. Rough notebooks and diaries are being used to mark attendance and to make payments. In the absence of muster rolls there is every chance that people get cheated.

Shortage or lack of staff is having a negative impact on the working of MGNREGA. A survey has found that engineers are burdened with the task of maintaining job cards. This jeopardizes their real work and this implies that their primary task suffers.

Delay in payment of wages is a matter of concern. This continues to plague the system. Wage payments are delayed by months and workers do not get minimum wages as guaranteed. This is making a mockery of the system, which aims to remove poverty amongst the rural poor.

There is a set of demands proposed for improvements in MGNREGA. One demand is that the number of workdays should be increased to 200 with a minimum of assured 100 days, and also the wage should be increased to Rs.300. Here I would like to say that the Government is thinking of cutting the budget of MGNREGA. But since there is huge demand, it should be increased and not curtailed as is proposed.

18.00 hrs

Another demand is that job card should be issued to those who demand jobs. There is another demand that the scheme should be extended to urban poor also. The other most important demand is that the monitoring mechanism should be

strengthened to check corruption and for proper implementation of the scheme. MGNREGA is supposed to give people the fundamental right to live with dignity but the success of MGNREGA will depend on people's realization of the Act.

18.01 hrs (Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You can continue tomorrow. Now because it is six o' clock, we start zero hour with item no. 9.

18.02 hrs **PAPERS LAID ON THE TABLE ....Contd.**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपला): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) संविधान के अनुच्छेद 338 के खण्ड (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) न्यायपालिका में आरक्षण के बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन, मार्च, 2012

(दो) न्यायपालिका में आरक्षण के बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन, मार्च, 2012 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1066/16/14]

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रति वर्ष भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा पशु चिकित्सकों के अध्ययन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया प्री-वेटेनरी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। उक्त परीक्षा में वर्ष 2011 तक प्रश्नपत्र हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आते थे। परन्तु वर्ष 2011 के बाद भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा यह तय किया गया कि प्रश्नपत्रों की भाषा केवल अंग्रेजी होगी। अब प्रश्नपत्र केवल अंग्रेजी भाषा में आने के कारण हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से अध्ययनरत छात्रों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गयी है। फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलॉजी आदि अपने विषयों में अच्छी जानकारी होने के बावजूद प्रश्नपत्रों की भाषा अंग्रेजी होने के कारण कई बार वे सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। परिणामस्वरूप देश के ग्रामीण क्षेत्रों से आए प्रतिभाशाली छात्र, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण नहीं की है, उनको पशु चिकित्सक की शिक्षा प्राप्त करने के अवसर कम हो जाते हैं। पूर्व में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य किये गये थे, जिनकी वजह से पिछले दस वर्ष में बहुत सारे काम नहीं हो पाये थे। लेकिन जब से एन.डी.ए. की सरकार बनी है, तब से पिछले छः महीने में हमारे माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद में आमूलचूल परिवर्तन किया गया, जिसके कारण बहुत सारे काम अब ठीक हुए हैं। परिणामस्वरूप मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् को निर्देशित करने की कृपा करें कि आगामी परीक्षा सत्रों में अंग्रेजी के साथ हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से भी प्रश्नपत्र दिये जाएंगे।

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Hon. Deputy Speaker, Sir, I am from the temple town of Tirupati. Tirupati is the most visited temple in the country and even in the world. Each day, one lakh devotees visit the temple and Tirupati is the richest temple. Tirupati temple does a lot of charitable works like free food schemes and maintenance of free hospitals, schools and colleges. Of late, there have been aspate of new articles in the media about probable terror attack on Tirupati temple. If any untoward incident happens, it will affect the sentiments of the entire nation. Therefore, I urge upon the Central Government to provide additional security to the temple because the central forces are more equipped and they have better access to intelligence. A combination of Central and State Government security will be the ideal solution for the safety of the Tirumala.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, मुंबई शहर में जब वर्ष 2010 में आदर्श मामला सामने आया था तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक सर्कुलर निकालकर यह कहा कि रक्षा विभाग के अगल-बगल जितनी जमीन हैं, अगर उस पर डेवलपमेंट करना है तो उनकी एनओसी लेनी चाहिए, उनको इनफार्म करना चाहिए। उसके एक साल बाद, वर्ष 2011 में रक्षा विभाग के लोगों ने एक सर्कुलर निकालकर यह कहा कि उसके 500 मीटर तक अगर किसी को डेवलपमेंट का काम करना है तो हमारी एनओसी लेने की आवश्यकता होगी। यह ठीक है, लेकिन पिछले चार-पांच साल में उन्होंने एक भी एनओसी नहीं दी है और लगातार पांच साल से सारे डेवलपमेंट के कामों को बंद करके रखा है। वर्ष 2014 के लोक सभा चुनाव के समय एमओएस स्वयं मुंबई आए थे और आश्वासन दिया था कि हम तुरंत इस सर्कुलर को विदड्रॉ करेंगे, इसमें सुधार करेंगे। लेकिन नई सरकार आने के बाद हम सम्माननीय मंत्री जी से मिले, एमओएस से मिले। इस सभागृह में किरीट सोमैया जी और मैंने कॉलिंग अटेंशन मूव किया। हमको आश्वासन दिया गया, लेकिन रक्षा विभाग के सचिव ... * ने इतने समय बाद भी इसका कोई अंतिम निपटारा नहीं किया। It is a very important issue. I will take only one more minute. अगर किसी विभाग का अधिकारी एक सर्कुलर निकालकर पांच साल लगातार डेवलपमेंट के कामों को बंद रखता है तो मुझे लगता है कि लोक सभा, विधान सभा या न्याय मंडल की इस देश में आवश्यकता ही नहीं है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, आज दोपहर में किरीट सोमैया जी, शेवाले जी और मैंने उनसे मुलाकात की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि तुरंत इस सर्कुलर विदड्रॉ करेंगे।

मैं इस सभागृह के माध्यम से मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Arvind Sawant and Shri Rahul Shewale are allowed to associate with this issue.

* Not recorded.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Thank you, Mr. Deputy-Speaker, Sir.

I would like to place before this House a very important issue. The Government has announced that the Planning Commission would be wound up. He has taken this step publicly a day after the Parliament Session ended, without any discussion in Parliament or consultation with political parties or other concerned-entities. The decision is in line with the prevailing neo-liberal view that there is no need even for a discussion on this, in a market-oriented economy.

When the Parliament is supreme and the Prime Minister has made this statement only in public, it is really a violation of the right of the Parliament and itse Members. The role of the Planning Commission has already been curtailed in the last two decades, under liberalization. What our Prime Minister has done is to really give it a final burial.

The Planning Commission has been tasked with certain allocation of resources under the plan, providing for a balanced development, keeping in mind regional disparities and monitoring the important schemes and projects.

The Government claims that the Planning Commission was not in tune with the federal principles. To some extent, I agree with that. That is why, we have been advocating that the Planning Commission should be made an executive wing of the National Development Council so that it becomes truly a federal institution.

But if the Planning Commission itself is dismantled, the allocation of the States will be decided by the Finance Ministry which will only lead to further centralization and bring in political bias as far as the States are concerned. The Government has not spelt out what will be put in place instead of Planning Commission. This is really an arbitrary decision taken by the Government. … (*Interruptions*) So, the Planning Commission should not be an affair of the Central Government. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You can send slips. If you want to associate, you have to send slips.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premchandran, Shri P.K. Biju, Shri Jitendra Chaudhury and Shrimati P.K. Sreemathi Teacher are allowed to associate with this issue.

डॉ. यशवंत सिंह (नगीना) : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर की नगीना सीट का प्रतिनिधित्व करता हूं। इस लोक सभा क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा उत्तरांखण्ड के साथ जुड़ा हुआ है और उत्तरांखण्ड को जाने वाली ज्यादातर सड़कें मेरे लोक सभा क्षेत्र से निकलती हैं, इसलिए वहां पर यातायात का बहुत दबाव रहता है। मेरे लोक सभा क्षेत्र के कस्बा शिवहारा से लखनऊ और चण्डीगढ़ की ओर जाने वाली ट्रेन संखय 12231 अप एवं 12232 डाउन चण्डीगढ़ एक्सप्रेस गुजरती है, जो पहले शिवहारा स्टेशन पर रुका करती थी। वहां से बहुत से यात्री इस ट्रेन पर चढ़ा करते थे, लेकिन न जाने क्यों इस ट्रेन का स्टॉपेज वहां बंद कर दिया गया है जिससे जो लोग चण्डीगढ़ इलाज कराने के लिए जाते थे या लखनऊ किसी काम से जाते थे, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ-साथ, नगीना जो मेरे लोक सभा क्षेत्र का मेन रेलवे स्टेशन है, वहां पर पुल नहीं है। फाटक पर प्रतिदिन तीन से चार घण्टे जाम लगता है। इसकी वजह से आने वाले लोगों को एनएच-74 पर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार एम्बुलेंस में लेटे मरीज क्रॉस न करने की वजह से मौत को प्राप्त होते हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि जो स्टॉपेज 12231-अप एंड 12232-डाउन बंद किया गया है. इन्हें पुनः चालू किया जाए और इस पर पुल निर्माण की स्वीकृति जो पहले से है, इस कार्य को बहुत शीघ्र ही पूरा किया जाए। धन्यवाद।

SHRI C. MAHENDRAN (POLLACHI): Hon. Deputy-Speaker, Sir, my sincere thanks to the former People's Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma for allowing me to represent Pollachi Constituency.

Thanks to the hon. Prime Minister for announcing SAGY, Sansad Adarsh Gram Yojana based on the THAI Scheme introduced by Puratchi Thalaivi Amma in the year 2011-12 itself to overcome the bottlenecks in the uneven distribution of resources and to provide minimum basic infrastructure facilities to all the habitations. The THAI Scheme announced by Puratchi Thalaivi Amma is the role

model scheme for SAGY. Tamil Nadu is the only State which is focusing on habitation as the unit of development. No other State in the country is implementing such an innovative scheme.

Puratchi Thalaivi Amma's THAI scheme is presently covering the expenditure to the extent of Rs.30 lakh to Rs.50 lakh for each village. Under SAGY the Central Government should extend additional contribution to the extent of Rs.2 crore to all the villages for speedy development of infrastructure of all the villages so as to benefit all sections of society as 60 per cent of the population lives in rural India.

The THAI scheme with the aim of extending basic facilities to the grassroots habitations in villages of Tamil Nadu has come as a boon. The scheme covers the minimum basic requirement of water supply, street lights, roads, burial grounds, pathway to burial grounds with additional requirements for Anganwadi centres, Public Distribution Shops, SHG building and play grounds and any other permitted work required by the villages.

I would request the hon. Prime Minister to kindly consider my request of giving additional fund to villages and allot Rs.2 crore to each village under this scheme.

*SHRI P. R. SUNDARAM (NAMAKKAL): Hon'ble Deputy Speaker Sir. Vanakkam. During the previous minority DMK rule in Tamil Nadu, in order to safeguard his family run TV Channel, the then Chief Minister and DMK leader blocked Tamil Nadu Arasu Cable TV Corporation. In the year 2011, when Hon'ble Puratchithalaivi Amma became the Chief Minister, Tamil Nadu Arasu Cable TV Corporation regained its vigour and started its services. As per the poll assurances given by Hon'ble Amma, this TV Corporation provided 100 Channels for meagre amount Rs.70/- per month and became very popular among the masses of Tamil Nadu. In this scenario, in the year 2012, the then DMK-Congress Coalition government at the Union brought a new legislation making DAS license mandatory for Chennai and other Metropolitan cities. Due to this effect, an application was submitted to Ministry of Information and Broadcasting for issue of DAS license for Tamil Nadu Cable TV in the year 2012. But the then DMK-Congress Coalition government at the Union kept this application pending. This paved way for encouraging private TV channels like SUN digital group. In this scenario, after BJP came to power at the Centre, Hon'ble Chief Minister Puratchithalaivi Amma met Hon'ble Prime Minister on 3rd June 2014 and requested for issue of DAS license to Tamil Nadu Cable TV Corporation. Since TRAI has directed not to issue digital license to any State government, the present Union government has also kept this application of TACTV pending. Under the able guidance of Puratchithalaivi Amma 48 MPs from Tamil Nadu of both the Houses of Parliament met Hon'ble Minister for Information and Broadcasting Shri Arun Jaitley and submitted an application requesting for issue of digital license. Hon'ble Deputy Speaker Sir. What I want to say in this august House is that well before the TRAI's direction Tamil Nadu Arasu Cable TV Corporation had applied for issue of digital license on 5 July 2012 and 23 November 2012. After due consideration of facts and respecting the sentiments of the people of Tamil Nadu,

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

and as demanded by Puratchithalaivi Amma, Hon'ble Prime Minister should intervene in this matter. I therefore urge upon the Union government through this august House that service oriented Tamil Nadu Cable TV corporation which runs on not-for-profit basis should be granted Digital Access System (DAS) license immediately. Thank you Sir.

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Hon. Deputy Speaker, Sir, under 20 Point Programme, Dalits were allotted housing plots and agricultural lands. Now 38 years have passed but they have not been given *bhoomidhari* rights which means that they cannot claim their right. In some of the places what happened is that their plots have been converted into parks and village land. As on date, they are not in a position to develop their land because they are in fear that any time it can be taken back by the Government.

So I would like to state that this case is already 38 years old; they are already in possession of and are cultivating the land. The law says that 12 years of continuous possession gives the right of ownership. But till today, they have not been given the right of ownership. Most of these people are Dalits, poor, OBC, and backwards. They live in rural areas of Delhi. They have been fighting for it but yet it has not been sorted out.

So, I urge upon the Government that they should be given *bhoomidhari* rights. Today, they do not have the title rights though they are using it. This is what, I wanted to say.

डॉ. अंशुल वर्मा (हरदोई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं और संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र हरदोई में वर्ष 2012-13 के पीएमजीएसवाई फेज-10 के 25 मार्गों को पैकेजवार स्वीकृति प्रदान की गयी थी और मार्गों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था। ये धन अभाव के कारण आधे-अधूरे पड़े हैं। जिससे क्षेत्रीय कृषकों, व्यापारीगणों, छात्रों एवं जनता को आने-जाने में काफी कठिनाई होती है। इस संबंध में जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर अधिकारियों को स्वयं के द्वारा पत्राचार किया जा चुका है। फेज-10 के 25 मार्गों के पैकेज में 7662.35 लाख रुपये के सापेक्ष संख्या नम्बर 2243.06

लाख रुपये ही अभी तक मिले हैं। शेष आवंटन 5419.29 लाख रुपये बाकी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि शेष आवंटन राशि निर्गत करने की कृपा करें, जिससे अधूरे कार्य पूर्ण हो सकें और क्षेत्रीय जनता के बीच जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, सड़क निर्माण कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ही सांसदगणों के पास है, जिसका सीधा श्रेय भारत के प्रधानमंत्री जी को जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े-बड़े नेता मंचों से एवं समाचार पत्रों के माध्यम से घोषणा करते हैं कि यह सड़क निर्माण कराने की स्वीकृति उन्होंने दी है। यह सड़क जल्दी बनेगी, क्योंकि यह पीएमजीएसवाई की होती है। आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ला रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार सांसदों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। जैसे उत्तर प्रदेश शासन के विभागो में मंडी परिषद, गन्ना संस्थान, लोहिया समग्र विकास, गांव आंदि विभागों के विकास कार्यों में केवल सत्ता के एम.एल.ए. के ही प्रस्ताव स्वीकृत किये जाते हैं।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, my submission is in respect of the Employees' Provident Fund Pension Scheme. The UPA Government had declared that all employees coming under the Employees' Provident Fund Pension Scheme will be eligible for getting the minimum pension of Rs. 1000 per month with effect from 1.4.2014. According to the recent Gazette Notification dated 28.8.2014, the enhancement of minimum pension of Rs. 1000 per month of the Employees Provident Fund Organisation is not beneficial to the employees. The provisions of the notification are against the interest of the members of the scheme. The minimum pension of Rs. 1000 is not applicable to a member who opted for a reduced pension before the age of 58. Also, if a member had given option for commutation, this amount is to be reduced from Rs. 1000. The children pension is Rs. 250 and orphan pension is Rs. 750. The Government has given it a wide publicity. But the minimum pension of Rs. 1000 is applicable only to a limited number of employees and moreover certain conditions were also imposed which are adversely affecting a large number of employees, particularly those who opted for commutation. The Gazette Notification very specifically says that the scheme is applicable only for the current financial year. Almost all the Cabinet Ministers have gone to all the States and inaugurated the scheme and openly given

a specific commitment that all the workers are eligible for Rs. 1000. So, I urge upon the Government to revise the scheme so as to give minimum pension of Rs. 1000 to all entitled for pension.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri P. Karunakaran, Shri P.K.Biju, Shri Jitendra Choudhury and Smt. P.K.Sreemathi Teacher are allowed to associate with the matter raised by Shri N.K.Premachandran.

श्री भरत सिंह (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपका ध्यान बलिया लोक सभा क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, चूंकि मैं बलिया लोक सभा क्षेत्र को बिलांग करता हूं। बलिया के पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में बहुत बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। मंगल पांडे बलिया के थे, लोकनायक जय प्रकाश जी बलिया के थे। उस बलिया में आज गरीब लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। जिला अस्पताल में कोई हार्ट का डाक्टर नहीं है, न्यूरो सर्जन नहीं है, गाइनिकोलोजी का डाक्टर नहीं है, आक्सीजन की व्यवस्था नहीं हैं, वहां बहुत दुर्व्यवस्था है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि पूर्वांचल में एम्स बनना है तो बलिया में बनाया जाए और एम्स के स्तर की सुविधा वाला अस्पताल बलिया को दिया जाए। इसके साथ ही बलिया में ट्रामा सैंटर चालू किया जाए, जिससे कि गरीब लोगों को इलाज मिल सके। क्योंकि गरीब लोगों को उपचार के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, उन्हें कभी बनारस जाना पड़ता है, कभी लखनऊ जाना पड़ता है।

इसके साथ ही मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि मेरी बात ऊपर तक पहुंचा दें, आप जीरो ऑवर की इतनी उपेक्षा न करें। आप हर सब्जैक्ट पर हम लोगों को बुलवाते हैं, लेकिन जीरो ऑवर में कम से कम पांच मिनट सदस्यों को बोलने का मौका दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI M. UDHAYAKUMAR (DINDIGUL): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak in this august House. Kodaikanal, the popular hill station developed by the Britishers is also called the Princess of Hills. It is situated in my Dindigul constituency of Tamil Nadu. Though this hill town has become very popular, the town needs development and infrastructure. The Government of Tamil Nadu led by our leader Puratchi

Thalaivi, Amma released Rs. 100 crore to beautify the ancient horticultural garden and to widen and illuminate the roads apart from desilting the natural lake on top of this hill station.

The Union Ministry of Urban Development has identified 100 towns to be developed, with infrastructural facilities, as Modern Smart Cities with an allocation of Rs. 7300 crore. As hill stations are also to be included under the Smart Cities Programme, Kodaikanal may also be included under this Programme. This is an urgent need from the infrastructure point of view as inland tourists and foreigners are visiting this hill station throughout the year in great number.

Modernization of Kodaikanal may provide for a helipad and a Greenfield Airport apart from protecting the eco system and developing a wildlife sanctuary. Linking of the bordering Kerala through Kosan Road may develop Kodaikanal further.

Hence, I urge upon the Centre to include Kodaikanal Hill Station in the Central Government's Smart City Programme.

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): Mr. Deputy-Speaker, I thank you for permitting me to mention the following matter in the Zero Hour.

With deep regret, I inform the House that Indian Railways, being the world's largest public railway network, has now become the world's first late running network in the country. During the last six months, a number of trains has reached the destination on their scheduled time though they have departed on scheduled time. The number of trains has increased; routes have been extended; fares have been hiked but security, and punctuality and cleanliness of trains have been neglected.

I would like to inform the House that CAG states that the Zones are reporting wrong data in order to show that 95 per cent of the trains were punctual. In addition, the CAG also reports that trains were late on 54 occasions while

prestigious trains like Rajdhani Express were late on 53 occasions. Thus, there is a need to take measures and report punctuality from the passengers' perspectives.

I would, therefore, request the hon. Minister, through you, to inform the House about the last three months statistics of Rajdhani Express and Shatabdi Express and the detailed causes for late running of the trains and ensure punctuality, cleanliness and security of the passengers and goods trains.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश का पहला एंटीबायोटिक कारखाना जो भारत सरकार का है, आज आर्थिक समस्या से जूझ रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी श्रीमती कस्तूरबा गांधी को बीमारी में जरूरी एंटीबायोटिक नहीं मिली, तब देश के पहले प्रधान मंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 मार्च, 1954 में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की स्थापना पिंपरी, महाराष्ट्र में की थी। यह देश की पहली कंपनी है, जिसने एंटीबायोटिक दवाइयों का निर्माण किया। आज देश में बहुत सारी कंपनियां अनेक तरह की दवाइयां बना रही हैं, बल्कि विदेशों से बहुत सारी दवाइयां आज देश में आती हैं। भारत सरकार की अपनी कंपनी हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड आज आर्थिक समस्या से जूझ रही है। यहां तक कि इसके कर्मचारियों को पिछले 5 महीनों से वेतन तक नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने के बावजूद भी सभी कर्मचारी कंपनी में पूरी मेहनत से काम कर रह हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कंपनी के लिए सरकार से जल्द से जल्द आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, जिससे सभी कर्मचारियों को पूर्व का वेतन मिले एवं कंपनी चलने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए।

*SHRI RANJIT SINGH BRAHMPURA (KHADOOR SAHIB): Sir, I want to draw the attention of the Central Government towards a problem faced by people of Gehri Mandi, Jandiala Guru, in my parliamentary constituency Khadoor Sahib. There is an urgent need for the construction of a railway over-bridge or an under-pass at the railway crossing in this area.

The double-crossing railway line at Gehri Mandi, Jandiala Guru, passes through the G.T.Road. It is the route of North-Western Railway. It is a very busy railway line. However, Punjab's second largest agriculture 'Mandi' is located here where foodgrains in bulk are sold. It caters to the selling of wheat, maize etc.. This is a very busy place as far as trade and business of foodgrains between India and Pakistan is concerned. The Food Corporation of India's and Railway's godowns are also located in this area.

However, Sir, as there is no overbridge or under-pass at this railway-crossing, the commuters on the G.T.Road are suffering. It has also adversely affected the carrying of foodgrains etc. on the trucks. Massive traffic-jams have become the order of the day.

So, I urge upon the Hon'ble Railway Minister to ensure that a railway overbridge or under-pass is constructed at the site of this railway crossing at the earliest.

Thank you.

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

श्री राजवीर सिंह (राजू भैया) (एटा) : महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, चुनाव से पहले मैं बहुत स्वस्थ हुआ करता था। चुनाव होने के बाद मैंने सिर दर्द की बीमारी मोल ले ली है और इसलिए ले ली है कि जब से लोक सभा के द्वारा बी.एस.एन.एल. के दो सिम दिए गए हैं, जब भी उनसे फोन मिलाते हैं, तो फोन मिलता ही नहीं है। यह सिर्फ मेरा ही कष्ट नहीं है, बल्कि हम सब जितने यहाँ सांसद हैं, शायद यह सबका कष्ट होगा और सिर्फ सांसद ही नहीं, जिनके पास भी बी.एस.एन.एल. का कनेक्शन है, वे भी निश्चित रूप से इस बीमारी से ग्रस्त होंगे।

महोदय, जब से यह फोन हमें मिला है, नम्बर एक बात तो यह है कि जब भी हम इससे नम्बर मिलाते हैं तो वह मिलता ही नहीं है। दूसरी बार फोन मिलाओ तो कहता है कि यह नम्बर स्थाई रूप से काट दिया गया है। तीसरी बार फोन मिलाइये तो बोलता है कि नेटवर्क बिजी है। चौथी बार फोन मिलाने पर टूं-टूं करके बन्द हो जाता है। अगली बार फोन मिलाओ तो आवाज बहुत कम आती है और अगर आवाज आती भी है तो एक तरफ से ही आवाज आती है। अगर उसके बाद और फोन मिलाने का प्रयास करेंगे तो यह बात करते हुए एक मिनट में दो बार कटता है। अगर आप सभी माननीय सदस्य मेरी बात से सहमत हों तो मेरे विषय के साथ अपने आपको सम्बद्ध कीजिएगा।

महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमारा बी.एस.एन.एल. भारत सरकार का उपक्रम है। इसे कोई फीस या कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। बी.एस.एन.एल. के अलावा एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, रिलायंस आदि हैं, इन सबकी सर्विस उम्दा क्वालिटी की है। आप कहीं भी चले जाइये, वहाँ इनका नेटवर्क आता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार को कोई टैक्स भी नहीं देना है, उसके बावजूद भी इतनी थर्ड क्लास की सेवाएं क्यों हैं? मैं तो यह चाहूँगा कि इन सिम को वापस कर लिया जाए और अगर हो सकता हो तो हमें दूसरी कम्पनी के सिम दे दिए जाएं।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The BSNL is also paying money to the Government.

श्री राजवीर सिंह (राजू भैया) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि बी.एस.एन.एल. की सुविधायें दुरूस्त की जाएं।

अनेक माननीय सदस्य : महोदय, हम भी इनसे सहमत हैं।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Please send the slip.

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) : महोदय, मैं आपका ध्यान भारत के ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ। वहाँ के लोगों का जो बेसिक स्वास्थ्य है, वह आशा बहुओं के जिम्मे है।

महोदय, जो वहाँ की आशा बहुओं की नियुक्ति है, उनका जो काम है, वे एक एजेन्ट की तरह काम कर रही हैं। उनके द्वारा डिलिवरी पर 600 रूपए, आँख की जाँच कराने जाएं तो 50 रूपए, कुष्ठ रोग की जाँच हेतु जाएं तो 150 रूपए लिये जाते हैं।

महोदय, ग्रामीण इलाकों में हालत बहुत खराब है। जब देश में बड़े-बड़े एम्स और बड़े-बड़े हॉस्पिटल और स्वास्थ्य के बारे में बड़ी-बड़ी बातें की जाती हों, तो वहाँ पर बेसिक स्वास्थ्य की बात एक एजेन्ट के माध्यम से या एजेन्ट की तरह किया जा रहा है, यह बहुत ही दुखदायी है।

महोदय, इनकी जो नियुक्ति है, वह भी ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान के द्वारा की जाती है, जिसके कारण इनकी नियुक्ति में बहुत भेदभाव होता है। इसके कारण इनसे जिस सेवा की उम्मीद की जाती है, वह लोगों को इनसे मिल नहीं पा रही है। इनकी समस्याओं पर भी सरकारों की ओर से ध्यान नहीं दिया गया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से और प्रदेश सरकार से माँग करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि उनकी नियुक्ति को नियमित किया जाए और जो ए.एन.एम. की सुविधायें हैं, वे इन्हें दी जाएं। जिससे इनके पास जो स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं आती हैं, उसे ये ठीक तरह से निभा सकें। एजेन्ट की तरह काम करने के कारण कभी-कभी ये मरीज को सरकारी अस्पताल में न ले जाकर, पैसे के लालच में, लोभ में प्राइवेट नर्सिंग होम में भी ले जाते हैं।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि प्रदेश सरकार द्वारा इनका नियमितीकरण कराया जाए और इनको ए.एन.एम. की तरह वेतन दिया जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The name of Shri Ashwani Kumar Choubey is associated on this issue raised by Shri Vinod Kumar Sonkar.

श्री हरीश मीना (दौसा) : महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा में जयपुर से दिल्ली रेलवे लाईन गुज़रती है। यह रेलवे लाईन् करीब 60 साल पुरानी है। जब यह बनी थी, तब यह शहर के बाहर थी। अब शहर बढ़ता गया और यह रेलवे लाईन् शहर के बीच आ गई। मेरे क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण स्थान हैं - बांदी कुईं, बस्सी एवं बसवा, जिनके बीच

में से यह गुज़रती है। महोदय, वहाँ बच्चों को स्कूल में जाने में दिक्कत होती है, पेशेन्ट्स को हॉस्पिटल्स में जाने में दिक्कत होती है, व्यापारियों को भी बहुत दिक्कत आती है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि इन तीनों शहरों में रेलवे ओवर ब्रिज बनाए जाएँ ताकि आम जनता को सुविधा हो। इसके अतिरिक्त दौसा शहर जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र का जिला मुख्यालय है, जिसकी आबादी एक लाख से ज्यादा है, उस शहर में एक भी अंडरपास नहीं है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि दौसा शहर में कम से कम एक रेलवे अंडरपास बनवाएँ ताकि जनता को सुविधा हो।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, some requests have come from the hon. Members to speak in the `Zero Hour'. The number of matters to be raised in the `Zero Hour' is decided by ballot and the time given is two minutes. If any Member is having any urgent issue to be raised, the same may be allowed but for one minute only. I would not allow the Members to repeat the issue and those who are regularly raising the issue in the `Zero Hour' are not allowed. If I allow it regularly, then ballot would not be of any value. Therefore, only if the issue is urgent, and those Members who have not participated, as a special case, will be allowed, not regular Members.

Only one minute, hon. Members are allowed to speak. If you exceed one minute, then, the same will not be recorded.

श्री गणेश सिंह (सतना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। एक बहुत महत्वपूर्ण मामला था जिस पर लगातार नोटिस दिया गया था लेकिन मौका नहीं मिल पाया। इसलिए मैं आपके माध्यम से इसे सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ।

मध्य प्रदेश के बरगी परियोजना की दाईं तट नहर को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने के संबंध में यह विषय है। यह मामला 2010 से भारत सरकार के पास विचाराधीन है। अभी भी 28 अक्तूबर, 2014 को इस संदर्भ में मेरे पत्र के जवाब में माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि यह 17 फरवरी, 2010 को आयोजित उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति के पास भेजा गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि आखिरकार उसमें अंतिम निर्णय क्या हुआ और 5 दिसंबर, 2014 को व्यय वित्त समिति ई.एफ.सी. के अनुमोदन हेतु वित्त मंत्रालय में भेजा गया है जिसे लगभग तीन माह हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी मांग है कि बरगी बांध की दाईं तट नहर को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने हेतु ई.एफ.सी. का अनुमोदन करते हुए कैबिनेट में स्वीकृति दिये जाने की कृपा करें।

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Hon. Deputy Speaker, Sir, in Andhra Pradesh, as of now, palm oil is being cultivated in 1,37,000 hectares with 76,300 farmers' fields. To protect the interests of palm oil growers, the Government of India has to make amendments in subsidy policy and import policy.

Recently, FFB prices started falling from Rs.8,441 per MT to Rs.6,589 per MT since the cost of cultivation like labour cost and input cost had increased but the demand in FFB prices has decreased due to fluctuation of import duty.

Import of edible oil was brought under OGL in 1995. Presently, import duty on CPO is 2.5 per cent and oil is 10 per cent. Domestic prices of palm oil are significantly affected by cheaper imports from Malaysia and Indonesia because of which there were considerable fluctuations.

Hence, I would request the hon. Minister that there is every necessity to increase the import duty taking into consideration of palm oil growers' sustainability in Andhra Pradesh.

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): I would like to bring a serious issue to the notice of the House. I am not describing the issue. It is reported that the driver who is the rapist has been arrested but this clearly is not enough. Delhi Police and the Transport Department have clearly not learnt any lessons from last year's incident and such cabs and companies violate all rules like identity cards and verification of drivers. This state of affairs cannot be allowed to continue.

The Delhi Police should immediately file a FIR against this company Uber since it has indulged in a severe breach of public trust.

I demand that in future all cases of sexual assault and rape should be tried in Fast Track Courts.

I would also urge upon the Government to ensure security of women in public places and the Government must send out a strong message of zero tolerance on cases of violence against women.

DR. K. GOPAL (NAGAPATTINAM): Mr. Deputy Speaker, Sir, I would like to urge upon the Government to remove salt cess collected by the Salt Department of the Central Government. The Government presently levies salt cess on the salt produced in the land exceeding 10 acres. A majority of people who are engaged in salt trade are very poor farmers and their livelihood runs on their daily earning. In this scenario, it is unjustifiable to levy cess on the salt production which was opposed by the Father of our Nation and it led to a great revolution during the pre-independent period as Salt Satyagraha. The Varadaraja Committee has already recommended the abolition of salt cess in the year 1980 and even the Exchequer is getting less than Rs. Five crore from the whole country as salt cess levied on thousands of poor salt workers.

Therefore, I strongly urge the Government to abolish salt cess immediately. I would also like to urge upon the Government to remove salt from the Central List as Item No. 58 in the Seventh Schedule of the Constitution of India, in view of the fact that only 10 per cent of the salt land is owned by the Salt Department of the Central Government.

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर सर, वर्ष 1979 से वर्ष 2012 तक अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 625 फायर ब्रिगेड नॉन गजटैड पर्सोनेल्स को एक माह का एक्स्ट्रा पे, मतलब कम्पेनसेटरी पे मिलता था। अचानक वर्ष 2013 से यह बंद कर दिया गया। अंडमान और निकोबार पुलिस मैनुअल के मुताबिक बाकी 9 यूनिट्स में ये कम्पेनसेटरी पे दिया जाता है। इस तरह का कम्पेनसेटरी पे जम्मू-कश्मीर, अरूणाचल प्रदेश, दिल्ली में दिया जाता है। चूंकि इनके पास कोई वीकली लीव नहीं है, पब्लिक हॉली-डे नहीं है। सप्ताह में करीब 84 घंटे इन्हें काम करना पडता है। बहुत से राज्यों में फायर ब्रिगेड पर्सोनेल्स को रिस्क एलाउंस दिया जाता है जबकि अंडमान फायर ब्रिगेड में यह एलाउंस नहीं मिलता है। इस कारण से यह दिया जाता था। अचानक इसे वर्ष 2013 से बंद कर दिया गया।

मैं अपनी सरकार और गृह मंत्री से आग्रह करता हूं कि 625 फायर ब्रिगेड नॉन गजटेड इम्प्लॉइज को एक माह का कम्पेनसेटरी पे तुरंत पिछले एरियर्स के साथ दिया जाए।

श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी (मलकाजगिरी) : उपाध्यक्ष महोदय, अपना इंडिया यंग पिपुल का है। भारत की सवा करोड़ आबादी में से 50 करोड़ लोग 25 साल की उम्र के नीचे के हैं। पिछले पांच सालों से ए.आई.सी.टी.ई. ने हमारे देश के इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था को पूरा खराब कर दिया। ऑनलाइन एप्लीकेशन बोल कर, ज़ीरो डिफिशियन्सी कह कर एक-एक कॉलेज को हर साल 120 इनटेक दे दिया। इससे एक-एक कॉलेज का 800-1000 इनटेक हो गया। उससे पांच साल पहले 360-420 सीलिंग था। अभी पूरे भारत में एक-एक कॉलेज का इनटेक 1000-1200 हो गया। इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे तेलंगाना में 315 कॉलेजेज हैं, 1,85,000 इनटेक है, लेकिन उसमें वर्ष 2014 में एक लाख सीट बच गया। वहां 175 कॉलेजेज बंद हो गए। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टीज, पूरे 30,000 लोग रोड पर आ गए। ए.आई.सी.टी.ई. पूरे इंडिया के लिए गाइडलाइन्स फ्रेम करता है, लेकिन फी स्ट्रक्चर को वह फ्रेम नहीं करता। अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग फी है। हमारे स्टेट में 35,000 रुपये है, एक स्टेट में 50,000 रुपये है और दूसरे स्टेट में 80,000 रुपये है। लेकिन, इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई समान है। अब 35,000 रुपये और 50,000 रुपये में वे लोग कैसे पढ़ाई कर सकते हैं? इसकी फी की फ्रेमिंग भी बराबर होनी चाहिए।

SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): Mr. Deputy Speaker, Sir, the fall in the price of natural rubber has adversely affected all the rubber growers in India, especially the rubber growers in Kerala. Kerala alone produces about 90 per cent of natural rubber in India and about 1.5 million small farmers have been adversely affected. All these small farmers have an average holding of 5.4 hectares of land. In February, 2011, the price of natural rubber was Rs. 242 per kilogram and now it has come down to Rs. 100 per kilogram.

It has made the cost of production much higher than the revenue. The main reason for the fall in price of natural rubber is basically because in 2010 the Government has decided to reduce the import duty from 20 per cent to Rs. 20. Earlier the price of natural rubber was Rs. 242 per kilo. But we found an indiscriminate import of natural rubber. Take for example, last year alone, the gap

between demand and supply was only 1,40,000 metric tonnes. But the Government of India has imported about 3,00025 metric tonnes of natural rubber. The remaining about 2,50,000 tonnes of stock was there during the last year. Cutting across the party lines, we had agitated in front of the Parliament regarding this issue. This is not the issue of any constituency alone.

HON. DEPUTY SPEAKER: What do you want? What is your demand?

SHRI JOSE K. MANI : Actually, one particular demand is that the import of natural rubber for the time being, for the period of minimum one year, should be banned. At the same time, Rs. 100 crore should be given for procurement from the Price Stabilization Fund. I hope that the Government will taken immediate action.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, Shri Jitendra Chaudhury and Shrimati P.K. Shreemathi Teacher are permitted to associate with the issue raised by Shri Jose K. Mani.

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर शहर): महोदय, जयपुर शहर में पेयजल आपूर्ति वर्तमान में बीसलपुर परियोजना से की जा रही है। आसपास के कस्बों में भी पेयजल की लगातार मांग बढ़ रही है। बीसलपुर परियोजना से जयपुर शहर के आस-पास के कस्बों, कालोनियों व बगरू विधानसभा क्षेत्र और विद्याधर नगर विधान सभा क्षेत्र, जो मेरे लोक संसदीय क्षेत्र में आता है, वहां पानी की समस्या है, उसको इससे जोड़ा जाए। जयपुर शहर की चार दीवारी क्षेत्र को रामगढ़ बांध से पूर्व में भी पानी सप्लाई होती थी। रामगढ़ बांध पेयजल, सिंचाई एवं पर्यटन की दृष्टि से अहम स्थान रखता था। जो आज ऊपर बने ऐनिकटों के कारण पानी की आवक बन्द होने से सूखा पड़ा है, इससे मुक्ति दिलाई जाए।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि रामगढ़ बांध परियोजना को विशेष आर्थिक पैकेज देकर चालू करवाया जाए, जिससे जयपुर की जनता को पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी एवं इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पूर्व में भी एशियाड खेल नौका प्रतियोगिता रामगढ़ बांध में हुई थी। कृपया पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको तुरन्त चालू कराया जाए।

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Thank you, Deputy Speaker, Sir. Ambarnath is an upcoming town in my constituency where we have the Shiv Mandir constructed 954 years ago. Like many ancient temples of the time, this one was located on the banks of the River Waldhuni.

With industrialization, the river is ruined and is now flowing like a nullah with all the industrial and other wastes released into the same. This pollution has been so drastic that the ancient stone crafted temple is losing grips at some places and some of the carved stones are falling apart. The same Waldhuni River was in news for pollution at Ulhasnagar where more than 1500 people had to be admitted to hospitals.

The point here is that such ancient relics of mythology should be preserved with utmost care, which is not happening, causing further damage to the temple.

First of all, the Waldhuni Development Authority, which was created in 2007, should be revitalized and work should be undertaken for reduction of pollution which is taking toll on ancient Shiva Temple and also on the health of thousands of the people.

I would request the Government, through you, Sir, to take immediate action and send a team of experts for the conservation of this 1,000 year old heritage site and its beautification. Thank you, Sir.

श्री राजकुमार सैनी (कुरुक्षेत्र) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे कुरुक्षेत्र लोक सभा में यूं तो सैकड़ों रेलवे फाटक हैं, परन्तु सबसे ज्वलंत समस्या यह है कि पांच फाटकों से लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। यहां हजारों पर्यटक महाभारत की धरती गीता स्थली से क्या संदेश लेकर जाते हैं, यह आप भी जानते होंगे। तीन फाटक कुरुक्षेत्र शहर को बीचोंबीच दो भागों में बांटते हैं, एक दिल्ली अम्बाला कैंट लाइन पर शाहबाद में झांसा रोड पर और जगाधरी अम्बाला लाइन पर ऊंचा चानना में लाडवा रोड पर है, ये दोनों रेल लाइनें अति व्यस्त हैं। फाटक अक्सर बन्द ही रहते हैं। घंटों जाम से शहर व क्षेत्र के लोग, बाहर से आए पर्यटक बेहद दुखी होते हैं।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि तुरन्त समस्या का निदान किया जाए और इन पर ओवर ब्रिज या अंडर पास बनाए जाएं।

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Sir, I would like to raise a very important issue. You know that Tripura is situated in one of the remotest corners of the country. Here the air journey is not a luxury but it is a compulsion. Very recently the Air India and two other private airlines, Spice Jet and Jet Airways, have withdrawn their flights. Due to this hundreds of passengers are stranded in Kolkata and Agartala. People have to fly by air, whether they are patients, students etc.

That is why Air India should take immediate initiatives to evacuate stranded passengers from both the places and also normalcy should be brought in by increasing the number of flights. That is my request, through you, to the Civil Aviation Minister.

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : महोदय, मैं एक विकलांग अधिवक्ता के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। कुमारी संगीता तुकाराम रोकड़े जो पेशे से वकील है। वह दिनांक 20.06.2013 को नागपुर से महाराष्ट्र एक्सप्रेस के संबंधित टी.सी.ओ. से बातचीत कर तथा उनकी अनुमति लेकर ए.सी. कोच में बैठी थी। जो लीगल चार्ज देने हेतु तत्पर थी। परन्तु टी.सी.ओ. चार्ज तो ले रहा था, परन्तु वह उसे रसीद नहीं दे रहा था, जिसको लेकर बहुत बातें हुईं, फिर विकलांग के साथ बदतमीजी की गई, पशुओं जैसा उसके साथ व्यवहार किया गया। इस घटना की लिखित शिकायत रेलवे में भी दर्ज की गई है, परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई है और विकलांग वकील को मिलने वाली सुविधाओं को बन्द कर दिया गया है।

आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहती हूं कि विकलांग महिला को मिलने वाली सुविधाएं उसे दी जाएं। उस घटना की जांच के लिए जांच कमेटी बैठायी जाय और उसे उचित सहयोग दिया जाये।

SHRI S.R. VIJAYA KUMAR (CHENNAI CENTRAL): Hon. Deputy Speaker, Sir, I would like to draw your attention to the requirements of ICF Hospital located in Chennai Central Constituency. This Hospital is an important institution that caters to the medical needs of ICF employees and their families along with the retired staff. However, there are multiple challenges faced by the people visiting

the Hospital. The ICF Hospital meets a daily footfall of 800 outpatients but has only 19 doctors. Out of these 19 doctors, six are contract employees. Similar is the case with the other para medical staff consisting of nurses, lab technicians, pharmacists and others.

In addition to the above, attendants of inpatients have a major challenge because neither there is any accommodation facilities nor canteen services. The Hospital also does not have incubator facilities for newborn babies. They do not have ICU, MRI and other critical equipments because of which patients are suffering from critical diseases and are referred to the Railway Hospital.

Hence, I urge the Union Government to do the needful immediately.

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): उपाध्यक्ष महोदय, 4 दिसम्बर के पेपर में खबर आया था कि 'दिल्ली सस्पैंड्स एनी इन्डस्ट्रीयल पॉलिसी'। असम में 25 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवक हैं। अगर इन्डस्ट्रीयल पॉलिसी सस्पेन्ड कर दी जाएगी तो उससे कितनी बेरोजगारी बढ़ेगी, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे यहां इन्डस्ट्रीज की बहुत कमी है। जब प्रधानमंत्री जी वहां गए थे तो उन्होंने कहा कि हम उसको इन्डस्ट्रीयल हब बनाएंगे और वहां दूसरे चीजों की सहुलियत देंगे।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि उसको विथड्रा किया जाए और वहां इन्डस्ट्रीज को और बढ़ावा दिया जाए।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, पूरे देश में तम्बाकू युक्त गुटका आदि की अवैध बिक्री के कारण कैंसर एक महामारी के रूप में पूरे देश में फैल रहा है। आपको हर जगह एवं हर घर के आस-पास कैंसर के मरीज आपको मिलेंगे। उनके इलाज में व्यक्तियों का घर तबाह हो जाता है और कैंसर के मरीज को भारी कष्ट उठाना पड़ता है। कैंसर का इलाज महंगा है। उसके इलाज के लिए अस्पताल हर जगह नहीं होने से प्रमुख जगहों के अस्पतालों में भारी भीड़ देखी जा रही है, जिससे उन्हें जांच, इलाज थेरेपी व ऑपरेशन के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है, फलस्वरूप मर्ज बहुत ही बढ़ जाता है।

अतः उन अवैध गुटकों पर अविलंब प्रतिबंध लगाया जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र के 300 किलोमीटर के आस-पास ऐसा कोई अस्पताल नहीं होने के कारण उन्हें इलाज के लिए मुम्बई तक जाना पड़ता है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा चित्रकूट में कैंसर हॉस्पिटल खोला जाय और उसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

SHRI R. GOPALAKRISHNAN (MADURAI): Sir, Puratchi Thalaivi Amma, the former hon. People's Chief Minister of Tamil Nadu has taken a series of measures for the healthcare of the people of Tamil Nadu. Setting up of AIIMS type Super Specialty Hospital in Madurai is the top priority. Accordingly, proposals have been submitted to the Central Government. The proposed site is K. Puthupatti in Madurai.

Madurai is a major city for the people of southern districts of Tamil Nadu. People from about 12 districts covering a population of about 2.3 crore would be benefited by the AIIMS type hospital at Madurai. Madurai city itself is having a population of about 15 lakh.

The proposal submitted by the Tamil Nadu Government contains all the details, namely, the site selected, disease profile with the number of patients per year, NCD Report, prevalence of health hazard diseases in and around Madurai, and water and electricity supply to the proposed AIIMS hospital. Further, the Local Planning Authority and the Tamil Nadu Pollution Control Board are willing to extend full cooperation to the Health Department as also the District Administration in this regard.

Keeping in view the importance of the Madurai city and the interests of crores of people in and around Madurai, I would urge upon the Union Government to consider and expedite setting up of the AIIMS type Super Specialty Hospital-cum-Teaching Institute in Madurai. Thank you, Sir.

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पूरे देश में अंग्रेजों को हटाने के लिए आंदोलन हुआ था जिसमें कई लोग शहीद हुए थे। आप जानते हैं कि इस देश में ऐसे कई शहीदों के प्रति जो सम्मान होना चाहिए वह नहीं हो पाया,उसमें काफी चोट पहुंची है। मुजफ्फरपुर, बिहार में शहीद खुदी राम बोस ने 18 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। उन्हें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़ा था। किन्तु दुख की बात है कि शहीद खुदी राम बोस की चिता स्थल पर शौचालय बने हुए थे जिसे जनता ने तोड़ा भी किन्तु आज तक न ही उस मलबे को हटाया गया और न ही उनकी चिता स्थल पर कोई शहीद स्मारक बनाया गया। ...(व्यवधान) इसी प्रकार शहीद सतीश की पटना के सचिवालय पर तिरंगा झंडा फहराते हुए अंग्रेजों की गोलियों से जान गई उसमें सात लोग शहीद हुए थे।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि शहीद खुदी राम बोस के नाम पर मुजफ्फरपुर स्टेशन और उनकी चिता स्थल को शहीद स्मारक के रूप में बनाया जाए। साथ ही शहीद सतीश के गांव खडाहरा स्थित बाराहाट स्टेशन (बाँका जिला) का नाम शहीद सतीश स्टेशन रखा जाए।...(व्यवधान)

*SHRI RAHUL SHEWALE (MUMBAI-SOUTH-CENTRAL): Hon'ble Deputy Speaker Sir, Government of India confers classical language status to eminent languages in India. Government of Maharashtra is trying to get classical language status for Marathi language.

As of now, Tamil, Sanskrit, Telugu, Kannada and Oriya are six classical languages of India.

On getting this classical status, Central Government provides a huge grant for development of that language and its reputation also enhances. By getting such status a language gets importance and thus paving the way for its further development.

Government of Maharashtra constituted a committee under the chairmanship of Prof.Ranganath Pathare on 10th January 2012 for extensive research and study and to collect proofs to get classical language status for Marathi. This committee, after getting three extensions on 18 June, 2012, 14 August, 2012 and 12 March, 2013, had been asked to submit its report by 31 March, 2013.

Accordingly, this committee submitted its report in Marathi on 12 July, 2013 and in English on 16 November, 2013 to the Central Government. Sir, the Central Government norms for conferring classical language status to the Indian language are:

1. Ancientness of the language;
2. Originality and continuity of the language;
3. Established and independent linguistic and literary tradition and

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

4. The gap as well as connection / relation between the ancient language and its modern form.

Sir, Marathi language fulfills all the necessary parameters for being a classical language. Thank you.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 10th December, 2014 at 11 a.m.

18.59 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, December 10, 2014/Agrahayana 19, 1936 (Saka).